



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 2

PART II — Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 2017/ आषाढ़ 28, 1939 (शक)

No. 29] NEW DELHI, WEDNESDAY JULY 19, 2017/ASHADHA 28, 1939 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## RAJYA SABHA

The following Report of the Select Committee on the Constitution (One Hundred and Twenty-third amendment) Bill, 2017 was presented to the Rajya Sabha on 19th July, 2017:—

### समिति का गठन

श्री भूपेन्द्र यादव — अध्यक्ष

सदस्य

2. श्री चुनीभाई कांजीभाई गोहेल
3. डॉ० विकास महात्मे
4. श्री राम नारायण डूडी
5. श्री बी० के० हरिप्रसाद
6. श्री मधुसूदन मिस्त्री
7. श्री दिग्विजय सिंह
8. श्री हुसैन दलवाई
9. प्रो० राम गोपाल यादव
10. श्री शरद यादव
11. श्री सुखेन्दु शेखर राय
12. श्री ए० नवनीतकृष्णन

13. श्री सतीश चंद्र मिश्रा
14. श्री टी० के० रंगराजन
15. श्री दिलीप कुमार टिकी
16. श्री सी० एम० रमेश
17. श्री प्रफुल्ल पटेल
18. श्रीमती कानीमोझी
19. श्री अनिल देसाई
20. श्री नरेश गुजराल
21. मीर मोहम्मद फैयाज
22. श्री विश्वजीत दैमारी
23. श्री राजीव चंद्र शेखर
24. श्री स्वप्न दासगुप्ता
25. श्री राम कुमार कश्यप

#### सचिवालय

1. श्री जे०जी० नेगी, संयुक्त सचिव
2. श्री महेश तिवारी, निदेशक
3. श्री आर० एस० रावत, अपर निदेशक
4. श्री राकेश आनन्द, अपर निदेशक
5. सुश्री छाया गुप्ता, अवर सचिव
6. श्री मोहित मिश्रा, समिति अधिकारी
7. श्री थंग जॉयफुल तॉनसिंग, समिति अधिकारी

#### सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्रीमती जी० लता कृष्णा राव, सचिव
2. श्री बी० एल मीणा, संयुक्त सचिव
3. श्री के० नारायणन, एम०डी०, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम

#### विधि और न्याय मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री सुरेश चन्द्र, सचिव
2. श्री रामायण यादव, अपर सचिव

#### विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. डॉ० जी० नारायण राजू, सचिव
2. डॉ० रीता वशिष्ठ, अपर सचिव
3. श्री आर० श्रीनिवास, अपर काउंसिलर

#### संक्षिप्ताक्षर

ओबीसी  
एससी  
एनसीएससी  
एसईबीसी  
एनबीसीएफडीसी

अन्य पिछड़ा वर्ग  
उच्चतम न्यायालय  
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग  
सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग  
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

### प्रस्तावना

मैं, संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 संबंधी प्रवर समिति का अध्यक्ष, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर विधेयक से संबंधित यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक 2017 लोक सभा में 05 अप्रैल, 2017 को पुरः स्थापित किया गया ताकि भारत के संविधान में आगे और संशोधन किया जा सके। लोक सभा में यह 10 अप्रैल, 2017 को पारित हुआ। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक, विधेयक की जांच के लिए 11 अप्रैल, 2017 को सभा द्वारा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव पर राज्य सभा के 25 सदस्यों वाली प्रवर समिति को भेजा गया और अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक उसे इस पर राज्य सभा को रिपोर्ट देने को कहा गया। (उपाबंध -I)

3. विधेयक पर विचार करते हुए समिति ने उसके समक्ष रखे गए निम्नलिखित दस्तावेजों/पत्रों आदि को नोट किया:

- (क) संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017, लोक सभा द्वारा 10 अप्रैल, 2017 को यथापारित रूप में।
- (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक से संबंधित ब्रीफ।
- (ग) विधि और न्याय मंत्रालय (विधिक कार्य तथा विधायी विभाग) द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक के संबंध में सूचना-पत्र।
- (घ) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक पर सूचना/पत्र।
- (ङ) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक के संबंध में सूचना/पत्र।
- (च) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक के संबंध में सूचना/पत्र।
- (छ) भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक के संबंध में सूचना/पत्र।
- (ज) राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया ज्ञापन।
- (झ) विशेषज्ञों और अन्य पणधारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया ज्ञापन।

4. कुल मिलाकर समिति ने सात बैठकें कीं।

5. समिति ने 17 अप्रैल, 2017 को हुई अपनी बैठक में विधेयक की जांच के लिए कार्य योजना तथा प्रक्रिया के बारे में विचार-विमर्श किया। सदस्यों ने विधेयक के उपबंधों के संबंध में अपने विचार तथा चिंताएं भी व्यक्त की और संबंधित मंत्रालयों के साथ उन मुद्दों पर चर्चा करने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित मंत्रालयों की राय के अलावा, समिति के विचारार्थ प्रसिद्ध विशेषज्ञों और संगठनों के मत लिए जाएं। तत्पश्चात् अध्यक्ष ने उन व्यक्तियों और संगठनों के नाम जानना चाहा, और इस विषय पर उनके मतों के बारे में समिति विचार करना चाहती थी और निदेश दिया कि उन्हें बाद की बैठक में चर्चा के लिए बुलाया जाए। समिति ने इस विधेयक के संबंध में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के विचार प्राप्त करने का भी निर्णय लिया। जनता से टिप्पणियां/ज्ञापन आमंत्रित करते हुए प्रेस विज्ञापित जारी करने का भी निर्णय लिया गया। प्रत्युत्तर में, समिति को विधेयक के उपबंधों के संबंध में जनता से 72 ज्ञापन प्राप्त हुए और इस विधेयक के संबंध में 23 राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने-अपने विचार प्रस्तुत किये।

6. 24 अप्रैल, 2017 को हुई समिति की दूसरी बैठक में, इसने विधेयक के उपबंधों के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव के विचारों को सुना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध निदेशक ने इस निगम के कार्यकरण और भावी कार्य योजना के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया।

7. समिति की 2 मई, 2017 को हुई तीसरी बैठक में इसे आरक्षण के संबंध में इंद्रा साहनी संबंधी निर्णय से लेकर वर्तमान निर्णयों के बारे में बताया गया। समिति ने वर्तमान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा न दिये जाने के कारणों से लेकर इस विधेयक के अंतर्गत ओबीसी सूची का संरक्षण सुनिश्चित करने संबंधी मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा।

8. समिति की 15 मई, 2017 को हुई चौथी बैठक में, इसने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी० ईश्वरैया, पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, डॉ० के० वीरमणि, अध्यक्ष, द्रविड कषगम और श्री एस० के० खरवेंतन, पूर्व संसद सदस्य और पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के विचारों को सुना।

9. समिति ने 5 जून, 2017 को हुई अपनी पांचवीं बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चातर शिक्षा विभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग एवं वित्तीय सेवाएं विभाग तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिवों के साथ सकारात्मक कार्रवाई के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श किया। इसके पश्चात् समिति ने इस विधेयक के उपबंधों के संबंध में देश को विभिन्न हिस्सों से आए चौदह व्यक्तियों और पिछड़े वर्गों के सशक्तीकरण के लिए काम कर रहे विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के विचारों को सुना।

10. समिति ने 3 जुलाई 2017 को इस विधेयक पर खंडशः विचार किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) तथा विधि और न्याय मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग) ने, जहां कहीं आवश्यक हुआ अपनी टिप्पणियां/स्पष्टीकरण भी दिये। विस्तृत चर्चा के उपरांत समिति ने बिना किन्हीं संशोधनों के सभी खंडों को स्वीकार किया।

11. तदनुसार, एक प्रारूप प्रतिवेदन तैयार किया गया और सदस्यों को परिचालित किया गया।

12. समिति ने 14 जुलाई, 2017 को हुई अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया। संक्षिप्त चर्चा के दौरान, समिति ने इस प्रतिवेदन को स्वीकार किया।

13. राज्य सभा में उक्त विधेयक के पुरःस्थापन के दौरान एक सदस्य द्वारा विधेयक के संबंध में उपस्थिति किए गए संशोधन भी इस समिति को भेजे गए थे। इन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को उनकी टिप्पणियों/स्पष्टीकरणों के लिए भेजा गया। अब मंत्रालय से टिप्पणियों/स्पष्टीकरण प्राप्त हो चुके हैं और साथ में संलग्न हैं। (उपाबंध -IV)।

14. समिति आवश्यक जानकारी/प्रलेख उपलब्ध कराने और समिति की चर्चाओं में इसे बहुमूल्य सहायता देने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) तथा विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधिक कार्य विभाग) के प्रतिनिधियों के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहती है। समिति उन सभी विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहती है जो समिति के समक्ष उपस्थित हुए और जिन्होंने इस विधेयक के संबंध में अपने मूल्यवान विचार दिये और इस विधेयक की जांच के संबंध में लिखित टिप्पण तथा जानकारी प्रस्तुत की।

नई दिल्ली;  
19 जुलाई, 2017

भूपेन्द्र यादव  
अध्यक्ष,  
संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 संबंधी प्रवर समिति।

## प्रतिवेदन

### पृष्ठभूमि

लोक सभा में पुरःस्थापित किए गए संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 के साथ जोड़े गए उद्देश्यों और कारणों का कथन में कहा गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 के पारित किए जाने के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया। उक्त आयोग, 1987 के संकल्प के अधीन स्थापित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के स्थान पर 12 मार्च, 1992 को गठित किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान या अन्य विधियों के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित सभी रक्षापाथों को मानीटर करने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन गठित किया गया था।

2. संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 338क अंतःस्थापित करके पृथक् राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया था। परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन निर्देश, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तक निर्बंधित था। वर्तमान में, संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (10) के अधीन, इस समय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के साथ भेदभाव से संबंधित शिकायतों और परिवादों की जांच-पड़ताल करने के लिए भी सशक्त है।

3. अनुच्छेद 340 के अंतर्गत प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जनवरी, 1953 में गठित किया गया था जिसके अध्यक्ष श्री काका साहेब कालेलकर थे। आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1955 में प्रस्तुत किया था जिसे सितम्बर, 1956 में संसद के समक्ष रखा गया था। आयोग ने सिफारिश की कि जनगणना जाति आधार पर होनी चाहिए। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 1978 में गठित किया गया था। आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिसंबर, 1980 में प्रस्तुत किया। आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के निर्धारण हेतु ग्यारह मानदंड तैयार किए।

4. भारत सरकार ने मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार किया और केन्द्रीय असैन्य पदों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करते हुए अगस्त, 1990 में आदेश जारी किए।

5. केन्द्रीय सरकार के पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का उपबंध करने वाले कांज़ा को इंद्रा साहनी मामले में चुनौती दी गई थी। वर्ष 1992 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने इंद्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले (एआईआर 1993, एससी 477) में निम्नलिखित समुक्ति की थी:

*“भारत सरकार, प्रत्येक राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन आज से चार माह के भीतर नागरिकों की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किए जाने के अनुरोधों तथा अधिक सम्मिलित किए जाने और कम सम्मिलित किए जाने की शिकायतों को ग्रहण करने, उनकी परीक्षा करने और उनकी सिफारिश करने के लिए एक स्थायी निकाय गठित करेंगे।”*

6. उक्त निर्णय के अनुसरण में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम अप्रैल, 1993 में अधिनियमित किया गया था और उक्त अधिनियम के अधीन 14 अगस्त, 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) का गठन किया गया था। वर्तमान में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सूचियों में किसी पिछड़ी जाति के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने के लिए अनुरोधों की परीक्षा करता है तथा ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अधिक सम्मिलित किए जाने या कम सम्मिलित किए जाने की शिकायतों को सुनता है और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सलाह, जो वह उचित समझे, देता है। अब, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की ओर अधिक प्रभावी रूप से सुरक्षा करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समान संवैधानिक प्रास्थिति के साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का प्रस्ताव है।

7. संसद ने श्री बी०के० हांडिक की अध्यक्षता में पहली अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी समिति गठित की। समिति ने 27.08.2012 को प्रस्तुत अपने पहले प्रतिवेदन में सिफारिश की कि नया अनुच्छेद 338ख के अन्तः स्थापन के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए और इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के समान शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। समिति ने 25.4.2013 के अपने दूसरे प्रतिवेदन में अनुच्छेद 338 के खंड 10 को हटाने और नया अनुच्छेद 338ख अन्तःस्थापित करने की सिफारिश की। अपने तीसरे प्रतिवेदन में, समिति ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के संबंध में इसके द्वारा पूर्व में प्रस्तावित संशोधन की पुनःपुष्टि की।

8. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपने 2014-15 के प्रतिवेदन में यह भी सिफारिश की है कि अनुच्छेद 338 के खंड (10) के अधीन सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की शिकायतों की सुनवाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दी जानी चाहिए।

9. संविधान में प्रस्तावित संशोधन निम्नानुसार हैं:

- (i) अनुच्छेद 338(10) में “ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग” के उल्लेख का विलोपन।
- (ii) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया का उपबन्ध करने के लिए नए अनुच्छेद 342क का अन्तःस्थापन।
- (iii) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए अनुच्छेद 366 के अन्तर्गत खंड 26(ग) का अन्तःस्थापन प्रस्तावित है।

#### प्रवर समिति का विचार-विमर्श

10. 17 अप्रैल, 2017 को आयोजित अपनी पहली बैठक में समिति को जिस पृष्ठभूमि में विचाराधीन विधेयक का प्रारूपण किया गया उस पृष्ठभूमि के बारे में और पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण ने इतिहास के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे, अर्थात्:—

- (i) क्या किसी अधिसूचित वर्ग के ‘समावेशन’ और ‘अपवर्जन’ के आधार को निर्णीत करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया कोई वस्तुनिष्ठ मानदंड है;
- (ii) विचाराधीन विधेयक के प्रभावी हो जाने के पश्चात् अन्य पिछड़ा वर्गों की मौजूदा सूची की स्थिति क्या रहेगी;
- (iii) विचाराधीन विधेयक के प्रभावी हो जाने के पश्चात् अन्य पिछड़ा वर्गों की मौजूदा सूची की स्थिति क्या रहेगी;
- (iv) वर्गों को अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने या निकालने के संबंध में निर्णय लेने में राज्यपाल की क्या भूमिका रहेगी।

11. समिति को बताया गया कि मंडल द्वारा उपलब्ध कराए गए ग्यारह संकेतक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की केन्द्रीय सूची में शामिल किए जाने वाले वर्गों के संबंध में निर्णय लेने के लिए स्थूल ढांचा उपलब्ध कराएंगे। समिति को सूचित किया गया कि प्रस्तावित संशोधन केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए है जबकि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बिना किसी आशोधन के पूर्ववत कार्य करते रहेंगे। यह भी सूचित किया गया कि संसद में दो विधेयक नामतः (i) संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन), विधेयक, 2017; और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किए गए हैं जिनमें उक्त अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई की व्यावृत्ति का उपबन्ध किया गया है।

12. यह भी स्पष्ट किया गया कि पिछड़ा वर्गों के संबंध में, दो सूचियां हैं अर्थात् केन्द्रीय सूची और राज्य

सूची। केन्द्रीय सूची में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार केन्द्रीय सरकार की संस्थाओं में शिक्षा और रोजगार के अवसरों का उपबंध किया गया है। राज्य सूची में, राज्य अपनी पिछड़े वर्गों की सूची में समावेशन या अपवर्जन के लिए स्वतंत्र हैं। यह संवैधानिक संशोधन राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों की मौजूदा शक्तियों या कृत्यों को किसी भी रूप में प्रभावित या परिवर्तित नहीं करता है और राज्य पिछड़ा वर्गों की सूची में पिछड़ा वर्गों को निकालने या शामिल करने की उनकी शक्तियां अपरिवर्तित रहेंगी।

13. 24 अप्रैल, 2017 को आयोजित इसकी दूसरी बैठक में समिति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग विकास और वित्त निगम (एनबीसीएफडीसी) के कार्यकरण के संबंध में जानकारी दी गई। समिति की यह राय थी कि एनबीसीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से पिछड़ा वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी।

14. 2 मई, 2017 को आयोजित इसकी तीसरी बैठक में समिति को सूचित किया गया कि उच्चतम न्यायालय ने इन्दिरा साहनी मामले में अपने निर्णय में समुक्ति की थी कि “भारत सरकार, प्रत्येक राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन आज से चार माह के भीतर अन्य पिछड़ा वर्ग नागरिकों की सूची में सम्मिलित किए जाने के अनुरोध और अधिक सम्मिलित किए जाने और कम सम्मिलित किए जाने की शिकायतों को ग्रहण करने, उनकी परीक्षा करने और उनकी सिफारिश करने के लिए एक स्थायी निकाय गठित करेंगे। ऐसे निकाय द्वारा दी गई सलाह सामान्यतः सरकार पर बाध्यकारी होगी।”

15. तदनुसार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया गया और उक्त अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया।

16. 15 मई, 2017 को हुई अपनी चौथी बैठक में समिति ने पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए कार्यरत विशेषज्ञों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। मुद्दों पर आगामी पैराओं में संक्षेप में चर्चा की गई।

17. कई विशेषज्ञों और संगठनों ने महसूस किया कि विधेयक में कोई परिवर्तन या संशोधन किए जाने की आवश्यकता नहीं है और आगे चर्चाओं के लिए विधेयक में किसी परिवर्तन से इन प्रक्रिया में विलंब ही होगा जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए हानिकारक होगा। आयोग में महिलाओं को शामिल करने, आयोग में शामिल किए जाने वाले सदस्यों की संख्या जैसे अन्य सुझावों पर प्रस्तावित उपबंधों के अधीन उपयुक्त नियम बनाते समय विचार किया जा सकता है।

18. यह भी कहा गया कि वर्गों की पहचान, राज्य सूची में उनके अपवर्जन और समावेशन के संबंध में राज्य सरकार और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोगों की शक्तियों और कार्यों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसके अलावा विधेयक में राज्यपाल से परामर्श की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए।

19. उठाए गए उपर्युक्त मुद्दों के प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 338ख का उपखंड (9) किसी भी तरह राज्य सरकारों द्वारा अपनी स्वयं की सूची तैयार करने की शक्तियों में दखल नहीं देता है। समिति को यह भी सूचित किया गया कि राज्य पिछड़ा वर्ग सूची में इस प्रकार शामिल वर्ग अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में अपने आप शामिल नहीं हो जाएंगे।

20. अपनी पांचवी बैठक में प्रतिनिधियों/सदस्यों ने अनुच्छेद 342क के उपखंड (1) के बारे में चिंता व्यक्त कि क्या राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार से परामर्श के बाद सूची जारी की जाएगी या क्या केवल राज्य के राज्यपाल से ही परामर्श किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 154 का खंड (1) और अनुच्छेद 163 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत राज्यपाल संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों के माध्यम से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने प्राधिकार का प्रयोग करेगा। संविधान का अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों के संबंध में राज्य के राज्यपाल से परामर्श किए जाने का प्रावधान करता है और संविधान का अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल से परामर्श किए जाने का प्रावधान करता है। जैसा कि परिपाटी रही है, कभी भी राज्य सरकार को परामर्श प्रक्रिया से बाहर नहीं रखा गया है। निरपवाद रूप से राज्य सरकार ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समावेश/अपवर्जन के संबंध में

राष्ट्रपति को सिफारिश करती है। सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में समावेशन हेतु पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने की स्थिति में इसी तरह का उपबंध किया गया है। राज्यपाल से परामर्श का मतलब राज्य सरकार से परामर्श होता है।

21. अपनी छठी बैठक में समिति ने विधेयक पर खंड-वार विचारण के साथ-साथ सदस्यों द्वारा उठायी गई कतिपय अन्य चिंताओं पर विचार किया।

**विधेयक पर खंड-वार विचार किया जाना**

22. समिति ने विधेयक पर खंड वार विचार किया जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

23. प्रारंभ में कुछ सदस्यों ने नये आयोग जिसे मौजूदा अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित किए जाने के बजाए अनुच्छेद 338 ख के अंतर्गत गठित किया जाएगा, की संवैधानिकता को लेकर चिंताएं व्यक्त की। यह स्पष्ट किया गया कि संविधान का अनुच्छेद 340 मंडल आयोग और काका साहेब कालेलकर आयोग जैसे तदर्थ/अस्थायी आयोगों के गठन का प्रावधान करता है। यह भी सूचित किया गया कि जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया या तो अनुच्छेद 338 क अंतःस्थापित किया गया था। इसलिए स्वाभाविक परिणामस्वरूप अनुच्छेद 338ख के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जा रहा है।

24. समिति मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरणों से सहमत हुई और उसका यह विचार था कि उपयुक्त मंच पर अन्य पिछड़े वर्गों की शिकायतों को सुनने के लिए संवैधानिक तंत्र की व्यवस्था करने की दृष्टि से इस प्रयोजनार्थ संविधान में अनुच्छेद 340 उपलब्ध है। अतः सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 338ख सर्वाधिक उपयुक्त अनुच्छेद है।

25. तत्पश्चात् समिति ने खंड 2 पर विचारण शुरू किया।

#### **खंड 2: अनुच्छेद 338 का संशोधन**

26. विधेयक का खंड 2 अनुच्छेद 338 के खंड (10) का संशोधन का प्रस्ताव करता है ताकि निम्नलिखित शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का लोप किया जा सके “*ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश, जिनको राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के खंड (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रति निर्देश भी है*”।

27. विधेयक का खंड 2 बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

#### **खंड 3: नये अनुच्छेद 338 ख का अंतःस्थापन**

28. अनुच्छेद 338 ख का उपखंड 1 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान करता है।

29. कुछ सदस्यों ने अनुच्छेद 338 ख के उप-खंड (1) के अंतर्गत यथा उपबंधित प्रस्तावित आयोग का नाम बदलने के लिए संशोधन करने और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय सामाजिक और पिछड़ा वर्ग आयोग करने।

30. इसके प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित आयोग का नाम अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद तय किया गया है और यह महसूस किया गया कि उसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहना प्रकृति में स्वतः स्पष्ट है।

**आयोग का गठन**

31. अनुच्छेद 338ख उपखंड (2) आयोग के गठन का उपबंध करता है और अनुच्छेद 338ख का उप खंड (3) कहता है कि प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुद्रा सहित नियुक्त किए जाएंगे।

32. कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की अर्हताएं संशोधन में उपबंधित की जानी चाहिए। कुछ सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय/उच्च-न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उपाध्यक्ष ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय से हो सकते हैं। साथ ही एक महिला सदस्य भी इसमें हो



तथा सदस्य-सचिव भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी हो सकते हैं। अन्य सुझाव वर्गों से संबंधित मामलों में विशेष जानकारी रखने वाले समाज विज्ञानी और विशेषज्ञ तथा कम से कम एक सदस्य सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग या अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत समुदाय से शामिल करने के संबंध में थे।

33. उत्तर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 निरस्त हो जाएगा तो नए नियम बनाए जाएंगे और सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर विधिवत रूप से विचार किया जाएगा।

34. समिति ने इस संबंध में मंत्रालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को नोट किया।

#### आयोग के कर्तव्य

35. अनुच्छेद 338ख का उप-खंड (5) आयोग के कर्तव्यों और कार्यों का उपबंध करता है।

36. सदस्यों ने सुझाव दिया कि अनुच्छेद 338ख(5) के उप-खंड(ग) को संशोधित किया जाए और इस प्रकार पढ़ा जाए:—

*‘सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के आयोजन प्रक्रिया में भाग लेना तथा सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य में उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।’*

37. उत्तर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने कहा कि अनुच्छेद 338ख के खंड (5) के अधीन सभी उप-खंड प्रस्तावित आयोग के लिए सहभागी भूमिका की ओर संकेत करते हैं।

38. समिति ने इस संबंध में मंत्रालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को नोट किया।

39. तत्पश्चात् समिति ने कुछ अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित संशोधनों को लिया:—

*पृष्ठ 2, पर लाइन 11 के पश्चात् दो नए उप-खंड (क) और (ख) जोड़ा जाए और मौजूदा उप-खंड (क) से (च) को फिर से (ग) से (झ) अंकित किया जाए। नया उपखंड (क) एवं (ख) को निम्नलिखित प्रकार पढ़ा जाए:—*

*‘(क) (i) अनुच्छेद 342क(1) के अधीन लोक अधिसूचना के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की प्रारूप की जांच तथा केन्द्रीय सरकार को ऐसी सलाह देना जिसे यह उपयुक्त समझे।*

*(ii) आयोग द्वारा दी गई सलाह सामान्यता केन्द्रीय सरकार के लिए बाध्यकारी होंगी:*

*परंतु यह कि यदि केन्द्रीय सरकार आयोग की सलाह से सहमत नहीं होती है तो यह इसका कारण लिखित में अभिलिखित करेगी और प्रारूप सूची के साथ-साथ ये कारण राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगी।*

*(ख) (i) सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची सम्मिलित करने या अपवर्जित करने के लिए अनुरोध की जांच करना तथा अनुच्छेद 342 क(2) के अधीन सूची को संशोधित करने के लिए संसद को समर्थ बनाने के प्रयोजन को केन्द्रीय सरकार को सलाह देना तथा ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग के ओवर इन्क्लूजन और अंडर इन्क्लूजन की शिकायत को सुनना तथा केन्द्रीय सरकार को ऐसी सलाह देना जो यह उपयुक्त समझे।*

*(ii) आयोग द्वारा दी गई सलाह सामान्यता केन्द्रीय सरकार के लिए बाध्यकारी होगी:*

*परंतु यह कि यदि केन्द्रीय सरकार आयोग की सलाह से सहमत नहीं होती है तो यह इसका कारण लिखित में अभिलिखित करेगी और संसद की दोनों सभाओं में रखेगी।*

40. समिति ने अनुच्छेद 338ख के खंड (5) में एक नए उप-खंड (छ) के अन्तःस्थापन से संबंधित प्रस्तावित संशोधन को भी लिया:—

*‘नागरिकों के किसी वर्ग को सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित करने के अनुरोध की जांच करना तथा इस सूची में किसी पिछड़े वर्ग के ओवर इन्क्लूजन या अंडर इन्क्लूजन की शिकायत को सुनना तथा केन्द्रीय सरकार को ऐसी सलाह देना जो यह उपयुक्त समझे।’*

41. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया कि प्रस्तावित आयोग द्वारा शिकायतों के सुने जाने का उपबंध अनुच्छेद 338ख के उप-खंड (5) के अधीन किया गया है और किसी वर्ग को पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित किए जाने के अनुरोध की जांच के संबंध में स्पष्ट किया गया कि यह अधिकार आयोग को विधेयक का अधिनियमन हो जाने पर जारी किए जाने वाले तौर-तरीकों के भाग के रूप में उपलब्ध होगा।

42. तत्पश्चात् समिति ने अनुच्छेद 339ख के खंड 5 के उप-खंड (घ) में कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तावित इस संशोधन को विचार के लिए लिया कि ‘ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग उचित समझे’ शब्दों को हटाया जाए। समिति ने विभिन्न आयोगों/समितियों के वार्षिक प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष रखने में अत्यधिक विलंब के बारे में चर्चा की।

43. उत्तर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि आयोगों के वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाते हैं। मंत्रालय राज्यों तथा विभिन्न मंत्रालयों से की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन प्राप्त करता है और संसद के पटल पर रखता है। इसके अलावा, आयोग दो-तीन विशेष प्रतिवेदन, जैसे किसी राज्य विशेष में किसी घटना के संबंध में प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करता है। ये वार्षिक प्रतिवेदन से भिन्न प्रतिवेदन होते हैं।

44. समिति ने मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को नोट किया और आशा की कि प्रस्तावित आयोग अपने वार्षिक प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदन संसद के विचार के लिए उसके समक्ष ठीक समय पर रखेगा।

45. समिति ने अनुच्छेद 338ख के उप-खंड (8) में कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित संशोधनों को विचार करने के लिए लिया:—

*पृष्ठ 2 पर पंक्ति 41 और 42 के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: ‘(8) आयोग उप-खंड (क) एवं (ख) में यथासंदर्भित अनुरोधों और शिकायतों की जांच करते हुए या उप-खंड (ग) में यथासंदर्भित किसी मामले की जांच या खंड 5 के उप-खंड (च) में यथासंदर्भित किसी शिकायत की जांच करते हुए... करेगी’*

46. उत्तर में यह स्पष्ट किया कि उप-खंड (क) में संदर्भित किसी मामले की जांच करते हुए या खंड (5) के उप-खंड (ख) में संदर्भित किसी शिकायत की जांच करते हुए आयोग के पास किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी।

47. समिति ने संशोधन पर चर्चा की जिसमें अनुच्छेद 338ख में नए उप-खंड (10) को रखने का प्रस्ताव किया गया था। इस उप-खंड (10) में निम्नलिखित कहा जाएगा:—

*‘खंड 9 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के पास सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्तियां बनी रहेंगी।’*

48. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समिति को स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावित संशोधन सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्य सरकारों की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करता है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की मौजूदा शक्तियां संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 के पारित होने के पश्चात् भी जारी रहेंगी।

49. समिति ने प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा की और मंत्रालय द्वारा दिए स्पष्टीकरण को दृष्टि में रखते हुए समिति ने खंड 3 को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया।

#### **खंड 4: नए अनुच्छेद 342 का अंतःस्थापन**

50. प्रस्तावित अनुच्छेद 342क सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया का उपबंध करता है।

51. इसके बाद समिति ने कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया अर्थात्:—

(i) अनुच्छेद 342क के उप-खंड (1) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए:

“राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां कोई राज्य है, वहां उसके राज्यपाल द्वारा अनुरोध पर लोक अधिसूचना द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट करेगा, जो भारत सरकार के अंतर्गत या भारत सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत या भारत सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत पदों या केंद्रीय सरकार की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण हेतु प्रावधान करने के प्रयोजनों के लिए समझे जाएंगे;”

(ii) अनुच्छेद 342क के उप-खंड (2) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए:

“राष्ट्रपति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के परामर्श पर खंड (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में समावेशन या अपवर्जन कर सकता है;”

(iii) अनुच्छेद 342क में उप-खंड (3) में निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाए:

“किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य के अंतर्गत या राज्य के किसी अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत या राज्य के नियंत्रण के अंतर्गत पदों, या उस राज्य के अंदर शैक्षिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण हेतु प्रावधान करने के प्रयोजन से लोक अधिसूचना द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट करेगा;” और

(iv) अनुच्छेद 342क के उप-खंड (4) को निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाए:

“राज्यपाल, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के परामर्श पर खंड (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की राज्य सूची में समावेशन या अपवर्जन कर सकता है।”

52. खंड 4 के संबंध में कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के अन्य सेट निम्नानुसार थे:—

(i) अनुच्छेद 342क के उप-खंड (1) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए:

“राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां कोई राज्य है, वहां केवल राज्य की पूर्व सिफारिश से और ऐसी सिफारिश को यथोचित सम्मान देते हुए लोक अधिसूचना द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट करेगा, जो यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची के रूप में समझे जाएंगे।”

(ii) अनुच्छेद 342क के उप-खंड (2) के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाए: अर्थात्:—

(3) “प्रत्येक राज्य सरकार लोक अधिसूचना द्वारा उस राज्य में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट करेगी, जो उस राज्य के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की राज्य सूची के रूप में समझे जाएंगे।”

(4) राज्य विधि द्वारा खंड (3) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों की राज्य सूची में किसी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को सम्मिलित या अपवर्जित कर सकेगा, किन्तु पूर्वोक्त के सिवाय उक्त खंड के अधीन जारी अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।”

53. खंड 4 के संबंध में कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के अन्य सेट निम्नानुसार थे:—

अनुच्छेद 342क(1):— पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 34 के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

‘परंतु यह कि ऐसी सार्वजनिक अधिसूचना अनुच्छेद 338ख(5) के अंतर्गत आयोग द्वारा दिए गए परामर्श

के आधार पर जारी की जाएगी और जारी जारी होने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों में रखी जाएगी:

परंतु यह भी कि राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श उस राज्य के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा राज्यपाल को दिए गए परामर्श के आधार पर किया जाएगा।'

अनुच्छेद 342क(2):— पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 39 के बाद निम्नलिखित पंक्तियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

'परंतु यह कि ऐसा कानून अनुच्छेद 338(5)(ख) के अंतर्गत आयोग द्वारा दिए गए परामर्श पर आधारित हो।'

अनुच्छेद 342क(3):— पृष्ठ 3 पर, अनुच्छेद 342क(2) के पश्चात् एक नया खंड जोड़ा जाए, अर्थात्:

'अनुच्छेद 342क(3):— केंद्रीय सरकार पिछड़े वर्गों के रूप में मान्यता समाप्त कर दिए गए ऐसे वर्गों को अपवर्जित करने के उद्देश्य से या ऐसी सूची में नए पिछड़े वर्गों को सम्मिलित करने हेतु आयोग की सलाह पर किसी भी समय और अनुच्छेद 342क(1) के अंतर्गत अधिसूचित सूची के लागू होने की तिथि से दस वर्षों के समाप्त होने पर, और इसके पश्चात् दस वर्षों की प्रत्येक अनुवर्ती अवधि में उस सूची की समीक्षा करेगी।'

54. उपस्थित किए गए संशोधनों के संबंध में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित आयोग द्वारा सूचियों की समयबद्ध दशकीय समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, आयोग को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकार वंचन तथा सुरक्षोपाय के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करने की शक्ति प्राप्त है।

55. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उस राज्य के अंतर्गत या राज्य के किसी अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत या राज्य के नियंत्रण के अंतर्गत पदों या उस राज्य के अंदर शैक्षिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण का पहलू वर्तमान विधेयक के दायरे से बाहर है और इसलिए, प्रस्तावित संशोधनों की अनुमति नहीं दी जाती है।

56. मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 154 के खंड (1) और अनुच्छेद 163 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद् की सलाह पर कार्य करेगा। यह सूचित किया गया कि उपरोक्त संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत राज्यपाल या तो प्रत्यक्षतः या संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्राधिकार का उपयोग करेगा। संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श का प्रावधान किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श का प्रावधान किया गया है। जैसा कि परिपाटी है राज्य सरकार को कभी भी परामर्श प्रक्रिया से बाहर नहीं रखा गया है निरपवाद रूप से हमेशा राज्य सरकार ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में समावेशन/अपवर्जन की श्रेणी की सिफारिश राष्ट्रपति को करती है। एसईबीसी की केंद्रीय सूची में समावेशन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के मामले में इसी प्रकार का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से राज्यपाल के साथ परामर्श को राज्य सरकार के साथ परामर्श समझा जाता है।

57. मंत्रालय ने समिति को यह भी स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 342क के खंड (1) में यथा उपबंधित वाक्यांश "इस संविधान के प्रयोजन के लिए" संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 की तर्ज पर ही है। प्रस्तावित आयोग का गठन सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के हित में प्रतिगामी नहीं होगा। अनुच्छेद 342क में केंद्रीय सूची में समावेशन/अपवर्जन के प्रत्येक मामले की विस्तृत जांच का प्रावधान होगा। ऐसे समावेशन/अपवर्जन की परम शक्ति संसद के पास निहित रहेगी।

58. समिति ने प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में विचार-विमर्श किया और मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत विस्तृत स्पष्टीकरणों के मद्देनजर समिति ने बिना किन्हीं संशोधनों के इस विधेयक के खंड 4 को स्वीकार कर लिया।

#### खंड 5: अनुच्छेद 366 के संशोधन का प्रावधान

59. इस खंड में अनुच्छेद 366 में एक नए खंड (26ग) को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है

जिसमें कहा गया है कि:—

“(26ग) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से “पिछड़े वर्गों” से ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342क के अधीन पिछड़ा वर्ग होना समझा गया है;”

60. इस विधेयक के खंड 5 को बिना किन्हीं संशोधनों के स्वीकार कर लिया गया।

#### खंड 1: अधिनियम सूची और विधेयक का संक्षिप्त नाम

61. खंड 1 में इस विधेयक के संक्षिप्त नाम और संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2017 के प्रारंभ का प्रावधान किया गया है।

62. इस विधेयक के खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का संक्षिप्त नाम को बिना किन्हीं संशोधनों के स्वीकार कर लिया गया।

#### सामान्य समुक्तियां

63. समिति ने प्रस्तावित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य विशेष प्रतिवेदनों को समय पर प्रस्तुत किए जाने के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर विचार किया। समिति ने गौर किया कि ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जब ऐसे प्रतिवेदन इतने अधिक समय के बाद सभा में प्रस्तुत किए गए कि तब तक संबंधित मुद्दा प्रासंगिक नहीं रह गया और इस विषय पर सभा में चर्चा नहीं हुई। इसलिए समिति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को यह सलाह देती है कि वे सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित आयोग के सामाजिक महत्व के दृष्टिगत इसका वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य प्रतिवेदन समय पर तैयार किए जाएं और संसद के समक्ष रखे जाएं तथा आम जनता की जानकारी के लिए प्रस्तुत किए जाएं।

64. समिति ने सदस्यों और समिति के समक्ष उपस्थित हुए अन्य विशेषज्ञों/संगठनों के विचारों को भी नोट किया कि प्रस्तावित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सामाजिक रूप से तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में सहभागी भूमिका होनी चाहिए। समिति ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए इस स्पष्टीकरण को भी नोट किया कि अनुच्छेद 338ख (5) के अधीन सभी खंडों में प्रस्तावित आयोग की सहभागी भूमिका अंतर्निहित है।

65. समिति ने मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को स्वीकार किया। तथापि, समिति का मत था कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित आयोग विधेयक के विभिन्न खंडों में अंतर्विष्ट किए गए अनुसार सामाजिक रूप से तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में अक्षरशः सक्रिय सहभागी भूमिका निभाये।

66. समिति महसूस करती है कि इस विधेयक में प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के हित में सकारात्मक कार्रवाई को और अधिक बल प्रदान करेंगे तथा केन्द्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक संघवाद की संकल्पना को और अधिक बढ़ावा देंगे।

67. समिति समुक्ति करती है कि संशोधन राज्य पिछड़ा वर्ग अयोगों की स्वतंत्रता और कार्यकरण को किसी भी तरह प्रभावित नहीं करते हैं और वे राज्य सूची के संबंध में अन्य पिछड़ा वर्गों के समावेशन/अपवर्जन की अपनी शक्तियों को अबाधित रूप से प्रयोग करते रहेंगे।

68. समिति ने आयोग की संरचना के संबंध में कुछ सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को भी नोट किया और समिति से आग्रह करना चाहेगी कि सदस्यों की चिंताओं का समाधान करते समय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए बनाए गए नियमों को ध्यान में रखा जाए। आयोग का मत है कि प्रस्तावित आयोग की संरचना और उसके अध्यक्ष के चयन हेतु नियम बनाने समय यह सुनिश्चित किया जाए कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के उन व्यक्तियों को यथोचित प्रतिनिधित्व दिया जाए जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों में विश्वास जागृत करते हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आयोग में कम से कम एक महिला सदस्य हो।

---

69. समिति आशा करती है कि यह विधेयक सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए एक प्रभावी और दक्षतापूर्ण परिदान तंत्र की व्यवस्था करके आमूलचूल परिवर्तन लाएगा।

## परिशिष्ट-I

## संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017

(लोक सभा द्वारा यथापारित)

## विषय: विसम्मति टिप्पण

उपर्युक्त विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैरा 3 में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि “..... वर्ष 1992 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने इंद्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले (एआईआर 1993, एससी 477) में भारत सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित किए जाने तथा अधिक सम्मिलित किए जाने और कम सम्मिलित किए जाने की शिकायतों के अनुरोधों को ग्रहण करने, उनकी परीक्षा करने और उनकी सिफारिश करने के लिए एक स्थायी निकाय गठित करने का निदेश दिया था। अब, पिछड़े वर्गों के हितों की और अधिक प्रभावी रूप में सुरक्षा करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समान संवैधानिक प्रास्थिति के साथ राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का प्रस्ताव है।”

वस्तुतः माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय देते समय अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया था कि जिनको आरक्षण प्रदान किया जाना है उन नागरिकों के पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें विनिर्दिष्ट करने की शक्ति के सहगामी निकाय के रूप में, अनुच्छेद 340 के साथ पठित अनुच्छेद 16(4) के अधीन, केन्द्रीय और राज्य दोनों ही स्तरों पर आयोग या न्यायाधिकरण के स्वरूप वाले स्थायी निकाय का गठन किया जाए।

उक्त आदेश और निर्णय के प्रवर्तनशील अंश को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पैरा 117 में और अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया गया है, जिसे तुरंत संदर्भ के लिए नीचे प्रस्तुत किया गया है:

निर्णय-इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ (एआईआर 1993, एससी 477) का पैरा 117

“हमारी सुविचारित राय है कि आयोग या न्यायाधिकरण के स्वरूप वाला एक स्थायी निकाय होना चाहिए जिसे अन्य पिछड़ा वर्गों की सूचियों में समूहों, वर्गों और अनुभागों के अनुचित समावेशन या गैर-समावेशन की शिकायतों की जा सकें। ऐसे निकाय को ऐसे स्वरूप की शिकायतों की जांच करने और उपयुक्त आदेश पारित करने की शक्ति अवश्य दी जानी चाहिए। इसकी सलाह/राय सामान्यतया सरकार पर बाध्यकारी होनी चाहिए। तथापि, जहां सरकार इसकी सिफारिश से सहमत न हो, वहां इसे इसके कारण अवश्य दर्ज करने चाहिए। यदि किसी नए वर्ग/समूह को भी अन्य पिछड़ा वर्गों में शामिल किए जाने का प्रस्ताव हो तो ऐसे मामले को भी सर्वप्रथम उक्त निकाय को संदर्भित किया जाएगा और इसकी सिफारिश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह निकाय इस क्षेत्र के विशेषज्ञों, सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह के, से बना होना चाहिए तथा इसमें समुचित और प्रभावी जांच की आवश्यक शक्तियां अवश्य निहित होनी चाहिए। यह भी उतना ही वांछनीय है कि प्रत्येक राज्य को ऐसे निकाय का गठन करना चाहिए जो एक ऐसा कदम होगा जो वास्तविक शिकायतों के समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसे निकाय का सृजन—जिनको आरक्षण प्रदान किया जाना है उन नागरिकों के पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें विनिर्दिष्ट करने की शक्ति के सहगामी निकाय के रूप में—अनुच्छेद 16 के ही खंड (क) के अधीन—या अनुच्छेद 340 के साथ पठित अनुच्छेद 141 के अधीन या अनुच्छेद 340 के साथ पठित अनुच्छेद 16(4) के अधीन किया जा सकता है। हम निदेश देते हैं कि ऐसे निकाय का गठन केंद्रीय स्तर और राज्यों के स्तर, दोनों ही स्तरों पर ..... तारीख से चार माह के भीतर किया जाए ..... “(जोर दिया गया) यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पूर्वोक्त निर्णय सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अधीन उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया कानून माना जाता है।



इस निर्णय की भावना से यह प्रतीत होगा कि माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय के माध्यम से केन्द्र और राज्यों दोनों को निदेश दिया था कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में उन नागरिकों के पिछड़े वर्गों, जिन्हें आरक्षण प्रदान किया जाना है, कि पहचान करने और उन्हें विनिर्दिष्ट करने के मामले में अपने-अपने कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करें। कहने की आवश्यकता नहीं है कि अनुच्छेद 16(4) और 300 के अधीन उपबंध संवैधानिक उपबंध हैं।

उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा 119(ख) में अन्य बातों के साथ-साथ समुचित की कि, “सच पूछिए तो, अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए अनुच्छेद 340 के अधीन आयोग की नियुक्ति आवश्यक नहीं है। अनुच्छेद 340 में ऐसा नहीं कहा गया है। इसके अनुसार, आयोग का गठन सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं ..... और जिन परेशानियों के बीच वे श्रम करते हैं, उनकी जांच करने तथा उन कदमों के संबंध में सिफारिश करने के लिए किया जाना है जो ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा उठाए जाने चाहिए .....।”

पूर्वोक्त निर्णय में अंतर्विष्ट आदेशों और निर्देशों और/अथवा उस निर्णय में की गई समुक्तियों जो उक्त निर्णय जिसका वहां ऊपर और ज्यादा पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है, का हिस्सा है, के बावजूद वर्तमान विधेयक एक राष्ट्रीय आयोग के गठन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क का संशोधन करने और अनुच्छेद 338ख का अंतःस्थापन करने का प्रस्ताव करता है जिसके पास न केवल “भारत के संविधान या किसी अन्य विधि के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करने” की बल्कि साथ ही संघ और किसी राज्य के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास के संबंध में सलाह देने और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करने तथा ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करने हेतु व्यापक शक्तियां और केंद्रीय प्राधिकार होगा जो विहित किए जाएं। विधेयक अनुच्छेद 342क के अंतःस्थापन का प्रस्ताव भी करता है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विनिर्दिष्ट कर सकते हैं जिन्हें सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग समझा जाएगा और किसी राज्य के मामले में राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ऐसा कर सकते हैं।

विधेयक अनुच्छेद 342क के अंतःस्थापन का प्रस्ताव भी करता है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विनिर्दिष्ट कर सकते हैं जिन्हें सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग समझा जाएगा और किसी राज्य के मामले में राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श से ऐसा कर सकते हैं।

वर्तमान विधेयक के उपबंधों के साथ-साथ इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने के उपरांत और इसके बारे में पूर्व में की गई चर्चाओं के आलोक में मेरा यह मत है कि संशोधन संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 राज्यों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध करने से वंचित करेगा।

दूसरी बात, वर्तमान विधेयक के माध्यम से भारत के संविधान में प्रस्तावित संशोधन सहकारी संघवाद की भावना के विरुद्ध प्रतीत होते हैं।

तीसरी बात, इस विधेयक के माध्यम से संविधान में प्रस्तावित संशोधन राज्य सरकारों और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों की भूमिका को कमतर बनाता है।

चौथी बात, इस विधेयक के माध्यम से भारत के संविधान में प्रस्तावित संशोधन उन विशेष समुदायों के विकास में बाधा बनेंगे जिनका राज्य में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

पांचवीं बात, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1(1) में परिकल्पना की गई है कि “भारत राज्यों का संघ होगा” न कि एकात्मक राज्य होगा। लेकिन संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 एक एकात्मक प्राधिकरण को विहित करता है जो असल में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और



उन्हें विनिर्दिष्ट करने तथा उनके कल्याण के संवर्धन के मामले में राज्यों के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करेगा और इस प्रकार संघीय स्वरूप को प्रभावित करेगा जो संविधान का मूल ढांचा है।

पूर्वोक्त के दृष्टिगत, मैं संविधान (एक सौ तेईसवां) संशोधन विधेयक, 2017 के पक्ष में नहीं हूँ और इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ।

दिनांक: 14 जुलाई, 2017

(सुखेन्दु शेखर राय)

सदस्य, राज्य सभा और सदस्य,  
संविधान (123वां) संशोधन विधेयक संबंधी प्रवर समिति।

## परिशिष्ट-II

## संसद सदस्य

(राज्य सभा)

सेवा में,

अध्यक्ष,

संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 से संबंधित प्रवर समिति

प्रिय महोदय,

हम सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का पूरा समर्थन करते हैं।

परंतु भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए इसे और अधिक प्रतिनिधिक स्वरूप देने के लिए हम प्रस्तावित विधेयक में नम्रतापूर्वक कुछ संशोधन प्रस्तुत करते हैं।

इसलिए हम अपना विसम्मति टिप्पणी प्रस्तुत कर रहे हैं।

## खंड 3

1. पृष्ठ 2 पर पंक्ति 2 एवं 3 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात्:—

“338ख(1) पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए ‘राष्ट्रीय आयोग’ के नाम से जाना जाएगा।

2. पृष्ठ 2 पर पंक्ति 5 में “तीन अन्य सदस्य” के स्थान पर “पिछड़े वर्गों से संबंधित पांच अन्य सदस्य जिनमें से एक महिला और कम से कम एक अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे” शब्द निविष्ट किए जाएंगे।

(3) पृष्ठ 2, पर लाइन 11 के पश्चात् दो नए उप-खंड (क) और (ख) को जोड़ा जाए और मौजूदा उप-खंड (क) से (च) को फिर से (ग) से (झ) अंकित किया जाए। नया उपखंड (क) एवं (ख) को निम्नलिखित प्रकार पढ़ा जाए:—

‘(क) (i) अनुच्छेद 342क(1) के अधीन लोक अधिसूचना के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की प्रारूप सूची की जांच तथा केंद्रीय सरकार को ऐसी सलाह देना जिसे यह उपयुक्त समझे।

(ii) आयोग द्वारा दी गई सलाह सामान्यतया केंद्रीय सरकार के लिए बाध्यकारी होगी।

परंतु यह कि यदि केंद्रीय सरकार आयोग की सलाह से सहमत नहीं होती है तो यह इसका कारण लिखित में अभिलिखित करेगी और प्रारूप सूची के साथ-साथ ये कारण राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगी।

(ख) (i) सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित करने या अपवर्जित करने के लिए अनुरोध की जांच करना तथा अनुच्छेद 342क(2) के अधीन सूची को संशोधित करने के लिए संसद को समर्थ बनाने के प्रयोजन से केंद्रीय सरकार को सलाह देना तथा ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग के ओवर इन्क्लूजन और अंडर इन्क्लूजन की शिकायत को सुनना तथा केंद्रीय सरकार को ऐसी सलाह देना जो यह उपयुक्त समझे।

(ii) आयोग द्वारा दी गई सलाह सामान्यतः केंद्रीय सरकार के लिए बाध्यकारी होगी।

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार आयोग की सलाह से सहमत नहीं होती है तो यह इसका कारण लिखित में अभिलिखित करेगी और संसद की दोनों सभाओं में रखेगी।

3. कि पृष्ठ 2 पर उप खंड 5 (ग) पंक्ति 18 में “सलाह देना” के स्थान पर “आयोजन प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना” जोड़ा जाए।

4. कि पृष्ठ 3 पर उप खंड (9) पंक्ति 13 में “पिछड़े वर्गों” के पश्चात् “एनसीबीसी को किसी राज्य विशेष मुद्दे के लिए राज्य सरकार से परामर्श करना चाहिए।” जोड़ा जाए।

#### खंड 4

कि पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 16 में “से परामर्श के पश्चात्” शब्दों के स्थान पर “की सहमति प्राप्त करने के पश्चात्” शब्द अंतर्विष्ट किया जाए।

कि पृष्ठ 3, पंक्ति 20, उप-खंड (2) को “राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित राष्ट्रीय आयोग की सलाह पर उप-खंड (1) के अंतर्गत जारी एक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित या अपवर्जित कर सकते हैं।”

यह भी नोट किया गया है कि लंबी अवधि से आयोग के सदस्यों, उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष के पद रिक्त पड़े हैं। इसलिए हम पृष्ठ 6 के पैरा 20 के पश्चात् एक अन्य पैरा 20क जोड़ना चाहेंगे जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए—

आपका

1. श्री दिग्विजय सिंह
2. श्री बी०के० हरिप्रसाद
3. श्री हुसैन दलवाई

## परिशिष्ट-III

## टिप्पण

मंडल आयोग की सिफारिशों और इंदिरा साहनी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अंतर्गत एक विशेषज्ञ निकाय का गठन किया गया था। मेरा यह दृढ़मत है कि संसद में विचाराधीन विधेयक अर्थात् राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017 के अंत में यह उल्लेख किया जाए कि इस अधिनियम के अंतर्गत गठित किए जाने वाले निकाय को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की तर्ज पर संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा और किसी अन्य खंड के अंतर्वेशन और अपवर्जन की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा यह भी मत है कि जातियों का अंतर्वेशन और अपवर्जन और उनका अनुमोदन राज्यपाल, संसद और राष्ट्रपति पर नहीं छोड़ा जाए क्योंकि यह एक पश्चगामी कदम होगा और इस प्रकार राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्ग आयोग (एनसीएसईबीसी) का निर्णय सरकार पर बाध्यकारी होगा और साथ ही जातियों के अंतर्वेशन और अपवर्जन के लिए राज्य सरकारों की मौजूदा भूमिका में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा।

ह/-

(शरद यादव)

श्री भूपेन्द्र यादव, संसद सदस्य  
माननीय अध्यक्ष  
सदस्य,  
संविधान (123वां) संशोधन विधेयक, 2017 संबंधी प्रवर समिति,  
नई दिल्ली।

2017 का विधेयक संख्यांक 71

[दि कांस्टिट्यूशन (वन हन्ड्रेड एवं ट्वेन्टी-थर्ड अमेंडमेंट) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

## संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2017

भारत के संविधान का और संशोधन  
करने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) अधिनियम, 2017 है।
- (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

संक्षिप्त नाम और  
प्रारंभ।

2. संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (10) में, “ऐसे पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश जिनको राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के खंड (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रति निर्देश भी है” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रति निर्देश है” शब्द रखे जाएंगे।

अनुच्छेद 338 का  
संशोधन।

3. संविधान के अनुच्छेद 338 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

नए अनुच्छेद  
338ख का  
अंतःस्थापन।

पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग।

“338ख. (1) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नामक एक आयोग होगा।

(2) संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी, जो राष्ट्रपति नियमों द्वारा अवधारित करें।

(3) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(4) आयोग को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

(5) आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे—

(क) इस संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अधीन सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंधित रक्षापायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और मानीटर करना;

(ख) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के अधिकारों से वंचित किए जाने और रक्षापायों के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(ग) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास के संबंध में सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य में उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(घ) राष्ट्रपति को, वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग उचित समझे, उन रक्षापायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ङ) ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में सिफारिशें करना, जो संघ या किसी राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए, उन रक्षापायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, किए जाने चाहिए; और

(च) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना,

जो राष्ट्रपति, संसद् द्वारा किए गए उपबंधों के अध्यक्षीन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(6) राष्ट्रपति, ऐसी सभी रिपोर्टों को, संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों, यदि कोई हों, सहित संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

(7) जहां ऐसी कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे मामले से संबंधित है, जिसका संबंध राज्य सरकार से है, वहां ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी, जो उसे, राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों, यदि कोई हों, सहित राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखवाएगा।

(8) आयोग को खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत की जांच करते समय किसी वाद विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की, और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत सभी शक्तियां होगी, अर्थात्:—

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना; और

(च) कोई अन्य विषय, जो राष्ट्रपति नियम अवधारित करें।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

4. संविधान के अनुच्छेद 342 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

नए अनुच्छेद  
342क का  
अंतःस्थापन।

“342क. (1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां कोई राज्य है, वहां उसके राज्यपाल से परामर्श के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट करेगा, जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग होने के रूप में समझे जाएंगे।

सामाजिक और  
शैक्षिक दृष्टि से  
पिछड़े वर्ग।

(2) संसद् विधि द्वारा खंड (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में या उससे किसी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को सम्मिलित या अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु पूर्वोक्त के सिवाय उक्त खंड के अधीन जारी किसी अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।”।

5. संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (26ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

अनुच्छेद 366 का  
संशोधन।

“(26ग) “सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों” से ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342क के अधीन पिछड़ा वर्ग होना समझा गया है;”।

## उपाबंध-I

**राज्य सभा**  
**संसदीय समाचार भाग-2**

सं० 56562                      बुधवार, 12 अप्रैल, 2017                      समिति समन्वय अनुभाग  
संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 को राज्य सभा की प्रवर समिति को  
सौंपा जाना

जैसा कि सदस्यों को विदित है कि राज्य सभा ने 11 अप्रैल, 2017 को हुई अपनी बैठक में संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 को राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपे जाने का निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया गया:—

“भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, राज्य सभा के अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिवस तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के अनुदेशों के साथ राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाए, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

1. श्री भूपेन्द्र यादव
2. श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल
3. डॉ० विकास महात्मे
4. श्री राम नारायण डूडी
5. श्री बी०के० हरिप्रसाद
6. श्री मधुसूदन मिस्त्री
7. श्री दिग्विजय सिंह
8. श्री हुसैन दलवाई
9. प्रो० राम गोपाल यादव
10. श्री शरद यादव
11. श्री सुखेन्दु शेखर राय
12. श्री ए० नवनीतकृष्णन
13. श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
14. श्री टी० के० रंगराजन
15. श्री दिलीप कुमार तिकी
16. श्री सी०एम० रमेश
17. श्री प्रफुल्ल पटेल
18. श्रीमती कानीमोझी
19. श्री अनिल देसाई



20. श्री नरेश गुजराल
21. मीर मोहम्मद फ़ैयाज
22. श्री बिश्वजीत दैमारी
23. श्री राजीव चन्द्रशेखर
24. श्री स्वपन दासगुप्ता
25. श्री राम कुमार कश्यप''

2. राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा के सदस्य श्री भूपेन्द्र यादव को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

शमशेर के० शरीफ,  
महासचिव।

## उपाबंध-II

## प्रवर समिति के समक्ष उपस्थित होने वाले साक्षीगणों की सूची

1. डॉ० के वीरमणी, अध्यक्ष, द्रविड़ कड़गम
2. न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) वी० ईश्वरैया, भूतपूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी)
3. श्री एस० के० खारवेंथन, पूर्व संसद सदस्य (लोक सभा) एवं भूतपूर्व सदस्य, एनसीबीसी
4. श्री जी० करुणानिधि, महासचिव, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ओबीसी इम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन
5. श्री कपिल हरीशचन्द्र पाटिल, एमएलसी, महाराष्ट्र विधान परिषद
6. श्री रयागा कृष्णैया, एमएलए, तेलंगाना विधान परिषद
7. श्री हरिभाऊ राठौड़, पूर्व संसद सदस्य और एमएलसी, महाराष्ट्र विधान परिषद
8. श्री पी०एस० कृष्णन, भूतपूर्व सचिव, कल्याण मंत्रालय
9. श्री साहू अक्षय भाई, मुख्य समन्वयकर्ता, राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग परिषद
10. श्री गुदुरी वेंकटेश्वर राव, अध्यक्ष, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग प्रजा कल्याण संगठन
11. प्रो० पी०सी० पतंजलि, अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग विकास मंच
12. श्री हसीब ए० अज़ीज़ नादाफ
13. प्रो० प्रकाश सोनावाने
14. श्री हंसराज, अध्यक्ष, अति पिछड़ा वर्ग महासंघ
15. श्री विश्वनाथ पाटिल, अध्यक्ष, कुन्बी सेना राम वड़ी
16. श्री शम्बीर अहमद अंसारी, अखिल भारतीय मुस्लिम अन्य पिछड़ा वर्ग संगठन
17. डॉ० कैलाश गौड़, पूर्व सदस्य, महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
18. श्री हाजी शौकत भाई तम्बोली

## उपाबंध-III

डॉ० दिलीप कुमार तिकी  
पदमश्री एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता  
संसद सदस्य, राज्य सभा

नेता, बीजेडी संसदीय दल  
सदस्य,  
कोयला, इस्पात एवं खान संबंधी स्थायी समिति।

दिनांक: 9 जून, 2017

श्री भूपेन्द्र यादव  
माननीय अध्यक्ष,  
संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017 संबंधी प्रवर समिति

विषय: उपर्युक्त विधेयक में संशोधनों का सुझाव

आदरणीय महोदय,

संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017 की जांच हेतु गठित राज्य सभा की प्रवर समिति के सदस्य के रूप में, मैं वर्तमान विधेयक में निम्नलिखित सुझाव और संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूँ:

1. पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 30 में “उसके राज्यपाल से परामर्श के पश्चात्” शब्दों के स्थान पर “केवल राज्य सरकार की पुर्वानुमति से और ऐसी सिफारिश को यथाचित महत्व देते हुए” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

2. पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 32 में “इस संविधान के प्रयोजनों के लिए” शब्दों का लोप किया जाए।

3. पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 33 में “पिछड़ा वर्ग” शब्दों के पश्चात् “की केन्द्रीय सूची” शब्द अंतःस्थापित किए जाएं।

4. पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 39 के पश्चात् निम्नलिखित दो पैरा अंतःस्थापित किए जाएं:

(3) “प्रत्येक राज्य सरकार सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा उस राज्य में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जिन्हें उस राज्य के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की राज्य सूची माना जाएगा।

(4) राज्य विधि द्वारा खंड (3) के अंतर्गत जारी किसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की राज्य सूची में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े किसी वर्ग को समाविष्ट कर सकता है अथवा उसे अपवर्जित कर सकता है, परंतु पूर्वोक्त के सिवाय उक्त खंड के अंतर्गत जारी किसी अधिसूचना में किसी परवर्ती अधिसूचना के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।”

सादर

ह/-

(दिलीप कुमार तिकी)

श्री भूपेन्द्र यादव

संसद सदस्य,

माननीय अध्यक्ष-संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017 संबंधी प्रवर समिति

नई दिल्ली

30 जून, 2017

माननीय अध्यक्ष महोदय,

संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017 के उपबधों और प्रवर समिति के समक्ष दी गई प्रस्तुतियों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद मैं निम्नलिखित निवेदन करना चाहूंगा:

द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किए जाने का स्वागत करती है। यह सामाजिक न्याय का एक ऐतिहासिक विधान है जिसमें वर्तमान में करोड़ों और भविष्य में इससे भी ज्यादा भारतीय नागरिकों के जीवन पर प्रभाव डालने की अंतर्निहित शक्ति है। ऐसा करते समय मैं पिछड़े वर्गों के उत्थान की राजनैतिक कहानी पर प्रकाश डालना चाहूंगा और इस संबंध में कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा कि विधेयक के वर्तमान स्वरूप में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है।

यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (डीएमके) अर्थात् जस्टिस पार्टी ने मद्रास प्रेजीडेंसी में जस्टिस पार्टी की सरकार के दौरान साम्प्रदायिक जी०ओ० पारित किया था। शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की व्यवस्था करने और हमें सामाजिक न्याय के मार्ग पर अग्रसर करने वाली यह अब तक की पहली सरकार है। जब स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपकम दोराईराजन 1951 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा इस साम्प्रदायिक जी०ओ० को निरस्त कर दिया गया था तो द्रविड़ कषगम के नेता थंथाई पेरियार ने इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई की थी जिसके चलते पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉ० बाबासाहेब अंबेडकर को संविधान में पहली बार संशोधन करना पड़ा था। संक्षेप में, इस तरह अनुसूचित जातियों (अजा), अनुसूचित जनजातियों (अजजा) और अन्य पिछड़े वर्गों (अपि०व०) हेतु आरक्षण के रूप में विशेष प्रावधान करने के उपबंध को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। स्पष्टता और सुविधा के लिए अंतःस्थापित अनुच्छेद 15(4) यहां पुनःउद्धृत किया जाता है:

*“इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।”*

इसलिए अन्य पिछड़े वर्गों की जिस परिभाषा की संकल्पना की गई थी, उसके अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग नागरिकों के वे वर्ग हैं जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और जो अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं। इनके चार दशक से भी अधिक समय बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट के संबंध में सरकार का आदेश इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 मामले की विषय वस्तु थी। इस निर्णय के पैरा सं० 847 में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया है:

*“हमारा विचरित मत है कि एक आयोग या अधिकरण के रूप में एक स्थायी निकाय होना चाहिए जिसके पास अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियों में समूहों, वर्गों और तबकों के गलत अंतर्वेशन या गैर-अंतर्वेशन से संबंधित शिकायतें की जा सकें। ऐसे निकाय के पास इस तरह की शिकायतों की जांच करने और उपयुक्त आदेश पारित करने की शक्तियां अवश्य होनी चाहिए। इसकी सलाह/राय सामान्यतः सरकार पर बाध्यकारी होनी चाहिए। तथापि, जहां सरकार इस निकाय की सिफारिश से सहमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे इसके कारण अभिलिखित करने होंगे। ऐसी स्थिति में भी जब किसी नए वर्ग/समूह को अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल किए जाने का प्रस्ताव हो, ऐसे मामले को भी पहले इस निकाय के पास भेजा जाना चाहिए और उसकी*

सिफारिश के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस निकाय में सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों से विशेषण होने चाहिए और उसे समुचित और प्रभावी जांच के लिए आवश्यक शक्तियां देनी होंगी। यह भी इतना ही वांछनीय है कि प्रत्येक राज्य भी ऐसे निकाय का गठन करे जिससे वाजिब शिकायतों के निवारण में काफी मदद मिलेगी। उन पिछड़े वर्गों जिनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जानी है, की पहचान करने और उन्हें विनिर्दिष्ट करने की शक्ति रखने वाले सहवर्ती निकाय के रूप में अनुच्छेद 16 के खंड (4) - या अनुच्छेद 340 के साथ पठित अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत ऐसे निकाय का गठन किया जा सकता है। हम निर्देश देते हैं कि आज से चार माह की अवधि के भीतर केन्द्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर ऐसे निकाय का गठन किया जाए। ऐसे निकायों को तत्काल कार्य शुरू करना चाहिए और वे तत्काल प्रभाव से ऊपर उल्लिखित प्रकृति की शिकायतों और मामलों यदि कोई प्राप्त हो, को स्वीकार करने और उनकी जांच करने की स्थिति में होने चाहिए। भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के पास ऐसे निकाय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को तैयार करने का अधिकार होगा। अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियों के अवधिक पुनरीक्षण के मामले में भी इस प्रकार गठित निकाय या निकायों से परामर्श किया जा सकता है। जैसा कि मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड द्वारा वसंत कुमार [1985 एसयूपीपीएससीसी 714: 1985 एसयूपीपी 1 एससीआर 3.52] मामले में सुझाव दिया गया है, उन वर्गों जो अब पिछड़े नहीं रहे, को अपवर्जित करने अथवा नए वर्गों को सम्मिलित करने जैसी भी स्थिति हो, के लिए इन सूचियों का आवधिक पुनरीक्षण किया जाना चाहिए।'

1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का यही आधार था। वर्तमान संविधान (123वां) संशोधन विधेयक, 2017 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की तरह संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए है। लेकिन ऐसा प्रयास राज्यों द्वारा परम्परागत रूप से भोगे गए अधिकारों की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

राज्य सरकारें स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही और मौजूदा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से पहले से ही पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उनकी भलाई हेतु उपाय करती रही हैं। तमिलनाडु में, द्रविड़ मुन्नेत्र कणगम की सबसे पहली सरकार के दौरान राज्य सरकार ने 1969 में ए० एन० सत्तानाथन की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया था। सत्तानाथन आयोग के प्रतिवेदन में कतिपय जातियों के शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन और उनके सदस्यों के व्यवसाय के आधार पर पिछड़े वर्गों को दो श्रेणियों अर्थात् पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग में विभाजित करने का सुझाव दिया गया। इंदिरा साहनी मामले में दिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में भी इन सुझावों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। पिछड़ेपन की मात्रा का अध्ययन करने के लिए 1982 में जे०ए० अम्बाशंकर की अध्यक्षता में एक और आयोग का गठन किया गया। इसलिए, अब सृजित किए जा रहे किसी नए संवैधानिक निकाय से पिछड़े वर्गों के सशक्तीकरण में राज्यों को उनकी परम्परागत और अभिन्न भूमिका से विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद	लोक सभा द्वारा पारित विधेयक	सुझाए गए परिवर्तन	स्पष्टीकरण
1	2	3	4
338ख, खंड 5	उप खंड (ग) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य में उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।	आशोधन: उपखंड (ग) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में योजना बनाने की प्रक्रिया भागीदारी करना और इसके संबंध में सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य में उनके	इसे अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338क, जोकि क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित हैं, में इसी प्रकार के उपबंधों के समरूप बनाना।

1	2	3	4
		विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।	
338ख, खंड 5	कोई उप खंड (छ) नहीं	अंतःस्थापन: (छ) सूचियों में पिछड़े वर्गों के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग के समावेशन हेतु अनुरोध की जांच करना और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन की शिकायतों को सुनना तथा केन्द्रीय सरकार को ऐसी सलाह देना जो यह उचित समझे।	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को समावेशन के अनुरोध की जांच करने और शिकायतों को सुनने की स्पष्ट रूप से शक्ति प्रदान करना।
338ख, खंड 10	कोई खंड 10 नहीं	अंतःस्थापन: खंड 101 खंड 9 में उपबंधित किसी बस के होते हुए भी राज्य सरकार के पास सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति बनी रहेगी।	राज्य सरकारों की स्वायत्तता और अधिकारों की रक्षा करना।
342क, खंड 1	राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां कोई राज्य है, वहां उसके राज्यपाल से परामर्श के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट करेगा, जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग होने के रूप में समझे जाएंगे।	आशोधन: राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां यह कोई राज्य है, वहां उसके राज्यपाल के अनुरोध पर भारत सरकार या भारत सरकार के किसी प्राधिकरण के अंतर्गत या भारत सरकार के नियंत्रणधीन किसी पद या पदों पर नियुक्ति या केन्द्रीय सरकार की शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण हेतु उपबंध करने के प्रयोजनार्थ लोक अधिसूचना द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट करेगा।	यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग केन्द्रीय सरकार को उसी तरीके से सलाह दे जिस तरह राज्य आयोग राज्य सरकारों को सलाह देते हैं।

1	2	3	4
342क, खंड 2	संसद विधि द्वारा खंड (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में या उससे किसी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को सम्मिलित या अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु पूर्वोक्त के सिवाय उक्त खंड के अधीन जारी किसी अधिसूचना में किसी पश्चात्पूर्वी अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।	अंतःस्थापन: राष्ट्रपति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह पर खंड (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में या उससे किसी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को सम्मिलित या अपवर्जित कर सकता है।	इस काम में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आयोग की प्रणालीबद्ध, विशिष्टीकृत और वैधानिक सिफारिशों से मार्गदर्शन प्राप्त होता है।
342क, खंड 3	कोई खंड 3 नहीं	अंतःस्थापन: किसी राज्य का राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा उस राज्य या उस राज्य के किसी अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत अथवा उस राज्य के नियंत्रणाधीन पदों में सीटों या उस राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं के आरक्षण हेतु उपबंध करने के प्रयोजनार्थ सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकता है।	राज्यपाल और राज्य सरकार के पास स्थानीय दशाओं तथा परिस्थितियों के अनुसार आरक्षण नीतियों को कार्यान्वित करने की शक्तियां बनी रहेंगी।
342क, खंड 4	कोई खंड 4 नहीं	अंतःस्थापन: राज्यपाल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह पर खंड (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की राज्य सूची में या उससे किसी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को सम्मिलित या अपवर्जित कर सकता है।	राज्य सूची के संबंध में राज्यपाल की शक्तियां केन्द्रीय सूची के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियों के समान हैं।

इस देश में पिछड़ा वर्ग आंदोलन में तीन प्रमुख ऐतिहासिक मील के पत्थर निम्नलिखित हैं:—

1. 1921 में साम्प्रदायिक जी०ओ० का जारी किया जाना और जस्टिस पार्टी की सरकार द्वारा 1927 में जी०ओ० के अनुसार कार्यान्वित किया गया।
2. 1951 में प्रथम संवैधानिक संशोधन
3. इंदिरा साहनी मामले (1993) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

इस बात में संदेह नहीं है कि अगला प्रमुख मील का पत्थर संविधान (123वां) संशोधन विधेयक, 2017 को पारित किया जाना होगा। हमारा मार्गदर्शन कर रही ऐतिहासिक उपलब्धियों और लाखों पिछड़े नागरिकों की उम्मीदों से प्रोत्साहन प्राप्त करते हुए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह संविधान संशोधन अपने वायदे पर खरा उतरे। मेरा यही अनुरोध है कि मौजूदा विधेयक में मेरे द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों पर इस प्रवर समिति द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले अपने प्रतिवेदन में विचार किया जाए।

शुभेच्छु,

कानीमोझी



बी०के० हरिप्रसाद  
संसद सदस्य  
(राज्य सभा)

सी 1/10, लोधी गार्डन  
नई दिल्ली-110003  
दूरभाष: का० 23793820  
आ० 24647664

प्रिय महोदय,

मैं संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 में संशोधन हेतु अपने प्रस्ताव अग्रेषित कर रहा हूँ। कृपया इन्हें हमारे प्रतिवेदन में समाविष्ट करने का विचार करें।

सभी संशोधन, जिनका उल्लेख किया गया है, पिछड़े वर्गों के पक्ष में विधेयक के उद्देश्य को सुदृढ़ करेंगे।

मेरे सुझाव इस पत्र के साथ संलग्न हैं।

सादर।

आपका विश्वासी

ह०/

(बी०के० हरिप्रसाद)

03.07.2017

अध्यक्ष

संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017

संबंधी प्रवर समिति

नई दिल्ली

व्याख्यात्मक टिप्पण:

निम्नलिखित के संबंध में उक्त विधेयक में संशोधन हेतु मेरा अनुरोध:

(क) वर्तमान समाज के संबंध में व्यक्तिगत समुक्ति;

(ख) इन्द्रा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य और (एआईआर 1993, एससी 477) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के नौ न्यायाधीशों का निर्णय; और

(ग) भारत के संघीय संरचना को बचाना।

सुझाव:

1. अनुच्छेद 338ख का उप-अनुच्छेद (2) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष को स्पष्ट करता है परंतु अर्हता विनिर्दिष्ट नहीं है जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 धारा 3(2) के अंतर्गत अर्हता का उपबंध करता है और हम एआईआर 1993, एससी 477 के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के “पैरा 847 का भी संदर्भ ले सकते हैं, कि;

न्यायिक दृष्टिकोण के लिए अध्यक्ष भूतपूर्व न्यायाधीश होने चाहिए; सदस्य सचिव भारत सरकार के पूर्व सचिव स्तर का अधिकारी होना चाहिए, एक समाज बिज्ञानी तथा पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान वाले दो व्यक्ति होने चाहिए।

2. अनुच्छेद 338ख, खंड-3 उप-खंड 9 का इस रूप में संशोधन किया जाए;

“संघ और प्रत्येक राज्य सरकार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों में आयोग से परामर्श करेगी।”

यद्यपि देखा गया है कि राज्य सरकार के पास शक्तियां जारी रहनी चाहिए परंतु साथ ही इससे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में निहित शक्तियों को प्रभावित होंगी परंतु यह विचार किया जाना चाहिए कि प्रत्येक राज्य के भिन्न-भिन्न मुद्दे और उसके विशिष्ट समाधान हैं और हमारे देश के संघीय संरचना को बचाने और वास्तविक शिकायतों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को राज्य विशेष मुद्दों के लिए राज्य की संस्तुतियों पर विचार करना चाहिए।

3. अनुच्छेद 342क(2) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए—

“राष्ट्रपति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह पर खंड (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में सम्मिलित या अपवर्जित कर सकता है।”

अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण से संबंधित समिति ने 27.08.2012 को संसद में प्रस्तुत अपने प्रथम प्रतिवेदन के भाग II के पैरा 2.1 के अंतर्गत अपने संकल्प में उन विचारों की भी सिफारिश की थी, जिसमें निम्नानुसार उल्लेख है:

“संविधान संशोधन में विद्यमान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वर्तमान शक्तियों, अर्थात् अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित करने या अपवर्जित करने की शक्तियां तथा सूची में संशोधन के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ परामर्श करने की भारत सरकार का दायित्व शामिल होने चाहिए।”

4. अनुच्छेद 338ख, खंड-5 को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा;

आयोग का यह कर्तव्य होगा—

उप-खंड-5(ग)—सामाजिक-आर्थिक विकास की आयोजन प्रक्रिया में भाग लेना तथा सलाह देना।

....विकास....के बाद “सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के तथा संघ एवं किसी राज्य के अंतर्गत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए” पंक्ति को अंतर्विष्ट करें।

इन्द्रा साहनी मामले (1992) में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अनुबंध 1 में दिए गए मेरे सुझाव एवं संशोधन इस संशोधन विधेयक के प्रयोजन को सुकर बनाएंगे और इस विधेयक के संबंध में इस ऐतिहासिक पहल जिसके लिए हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं में भाग लेने का सम्मान देने के लिए मैं आभारी हूँ।

सादर

हः/-

(बी०के० हरिप्रसाद)

**संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2017 के संबंध में राज्य सभा के निम्नलिखित  
सदस्यों के सुझाव**

सेवा में,

अध्यक्ष

**संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2017 संबंधी राज्य सभा की प्रवर समिति**

यह विधेयक लोक सभा में पहली बार 05.04.2017 को प्रस्तुत किया गया और 10.4.2017 को (5 दिनों में) पारित हुआ। इसके अगले ही दिन अर्थात् 11.04.2017 को इसे राज्य सभा में रखा गया। अब राज्य सभा ने इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा है। स्पष्ट है कि संविधान (123 संशोधन) विधेयक, 2017 की विषय वस्तु पर लोक सभा में कोई विस्तृत और व्यापक चर्चा नहीं हुई थी।

हमने संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2017 का अध्ययन किया है। सर्वप्रथम हम 2017 के विधेयक का उस सीमा तक जहां तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव करता है, स्वागत करते हैं।

तथापि यह नोट किया जाता है कि यह पहली बार नहीं है कि संविधान के अंतर्गत संवैधानिक आयोग की परिकल्पना की गई है क्योंकि अनुच्छेद 340 के अंतर्गत विहित आयोग मूल संवैधानिक आयोग है, जिसका विचार पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए संविधान निर्माताओं ने किया था।

सर्वप्रथम, जब अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए एक संवैधानिक आयोग का प्रावधान किया गया है तो यह समझना कठिन है कि अनुच्छेद 338 में 338ख के रूप में एक अन्य अनुच्छेद को अंतःस्थापित करने के लिए यह संवैधानिक संशोधन क्यों लाया गया। अनुच्छेद 338 मूल रूप से अनुसूचित जातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की परिकल्पना करता है जिसमें संशोधन करके (65वां और 89वां संशोधन) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए दो आयोगों के रूप में तब्दील कर दिया गया है।

आर्दश रूप से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 द्वारा गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुच्छेद 340 के अंतर्गत मान्यता देकर अंगीकार किया जाना चाहिए था अन्यथा आयोग के लिए अनुच्छेद 338 या 338क (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग) के अंतर्गत यथाविद्यमान अतिरिक्त कार्यों सहित अनुच्छेद 340क अंतःस्थापित किया जाना था।

साथ ही, यदि हम मुख्य मुद्दों के संबंध में सीधे बात करें तो हम विधेयक में निम्नलिखित कमियां देखते हैं:—

1. अनुच्छेद 338ख का उप-अनुच्छेद (2) कहता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं तीन अन्य सदस्य होंगे। परंतु इस कथन कि इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के पद की सेवा शर्तें एवं पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियमों द्वारा अवधारित करें, के अलावा उनकी अर्हता विनिर्दिष्ट नहीं है।

उप-अनुच्छेद (3) कहता है कि आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रासहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 ने अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता को स्पष्ट कर दिया गया था। चिंता का कारण यह है कि इस निकाय में विशेषण होने चाहिए। तदनुसार 1993 के अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत अर्हता का प्रावधान विशिष्ट रूप से इस प्रकार किया गया है:—

- (क) एक अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो;
- (ख) एक समाज वैज्ञानिक;
- (ग) दो व्यक्ति, जो पिछड़ा वर्गों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हों; और
- (घ) एक सदस्य-सचिव जो भारत सरकार के सचिव स्तर का केन्द्रीय सरकार का एक अधिकारी हो या रहा हो।

यह इंदिरा साहनी मामले में नौ-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा दिए गए निर्णय में उच्चतम न्यायालय के मत के अनुरूप था।

(2) 2017 के विधेयक के अंतर्गत अनुच्छेद 338ख को उप-अनुच्छेद (5) आयोग के कर्तव्यों से संबंधित है जो निम्नानुसार है:—

“(5) आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे—

- (क) इस संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अधीन सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंधित रक्षापायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और मानीटर करना;
- (ख) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के अधिकारों से वंचित किए जाने और रक्षापायों के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना।”
- (ग) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य में उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;
- (घ) राष्ट्रपति को, वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग उचित समझे, उन रक्षापायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- (ङ) ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में सिफारिश करना, जो संघ या किसी राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए, उन रक्षापायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, किए जाने चाहिए; और
- (च) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा किए गए उपबंधों के अध्याधीन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

किन्तु आश्चर्यजनक रूप से, आयोग का महत्वपूर्ण कार्य जोकि 1993 के अधिनियम की धारा 9(1) और (2) के अंतर्गत उपबंधित किया गया है, गायब है। ये कार्य भी उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय (1992, पैरा-847) में दिए गए विनिर्देशनों के अनुसार थे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 9 में निम्नानुसार कहा गया है:

#### 9. आयोग के कृत्य

(i) आयोग नागरिकों के किसी वर्ग के सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित किए जाने के अनुरोधों की जांच करेगा और ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग के अधिक सम्मिलित किए जाने या कम सम्मिलित किए जाने की शिकायतों की सुनवाई करेगा और केन्द्रीय सरकार को ऐसी राय देगा जो वह उचित समझे;

(ii) आयोग की सलाह सामान्यता केन्द्रीय सरकार पर आबद्धकर होगी।

यह संपूर्ण महत्वपूर्ण उपबंध संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया है। ये कार्य संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुरूप भी हैं। इन कार्यों को समाप्त कर दिये जाने के पश्चात् अब 2017 के विधेयक के अंतर्गत उपबंधित किये गये अन्य कार्य अधिक पर्यवेक्षी प्रकृति के हैं। इस प्रक्रिया में वस्तुतः

अनुच्छेद 340 जोकि पिछड़े वर्गों की आत्मा की तरह है, अप्रभावी हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि अनुच्छेद 340 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15, 16 और 29 के अंतर्गत लाभ पहुंचाकर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछने की परिकल्पना की गई थी। अनुच्छेद 340 में न केवल उन वर्गों से संबंधित सामाजिक और शैक्षिक स्थितियों की जांच करने और उनके समक्ष आ रही समस्याओं के समाधान हेतु सिफारिश करने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति करने की परिकल्पना की गई थी अपितु, इसलिए भी कि “पिछड़े वर्गों” शब्द को अनुच्छेद 340 (1) में निर्धारित किए गए परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए। इस अनुच्छेद का यही आशय है कि उक्त अनुच्छेद सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने के लिए प्रक्रिया को परिभाषित किए जाने का उपबंध करता है। ऐसी प्रतीत होता है कि प्रारंभ में आयोग का नाम “राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग आयोग” प्रस्तावित करने का वास्तविक कारण यही था।

3. इसके अलावा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 11 के अंतर्गत यथा उपबंधित दस वर्षों में एक बार भी पिछड़ा वर्ग की सूची के आवधिक संशोधन और केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से अनिवार्य परामर्श से संबंधित उपबंध को एक बार फिर से पूर्णतः लोप कर दिया गया है यह उपबंध इंदिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 में भी शामिल किया गया था। आवधिक संशोधन के पीछे उद्देश्य पात्र सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष लाभ जैसे कि आरक्षण, इत्यादि हेतु रास्ता तैयार करना है।

जहां तक अनुच्छेद 340 के संशोधन का संबंध है, यह विचार एक बार फिर अनुपयुक्त है क्योंकि मूल रूप से अनुच्छेद 341 और 342 और अनुसूचित जातियों की सूची या अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी जाति के समावेशन या अपवर्जन की शक्ति प्रदान करते हैं। यद्यपि संविधान बनाते समय ऐसी कोई अन्य पिछड़ा वर्ग सूची नहीं थी। यह आवश्यकता केवल मंडल आयोग को लागू किये जाने के पश्चात् महसूस की गई और इंदिरा साहनी मामले के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस कार्य को पूरा करने के लिए एक विशेषज्ञ निकाय स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी।

यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जातियों (जैसाकि अधिकांशतः उन्हें अछूत समझा जाता था) और अनुसूचित जनजातियों (जो ज्यादातर वन क्षेत्रों में रहते थे) की पहचान करना अपेक्षाकृत आसान काम था जबकि अण्विष्य सूची के अंतर्गत जातियों की पहचान के लिए और अधिक वैज्ञानिक ज्ञान, सामाजिक अध्ययन और न्यायिक दृष्टिकोण की जरूरत पड़ती है।

उपर्युक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए एनसीबीसी अधिनियम, 1993 को अधिनियमित किया गया है। अब मौजूदा एनसीबीसी के कार्यों को राज्यपाल या राष्ट्रपति को सौंपना वास्तव में पश्चगामी कदम है।

इसलिए अनुच्छेद 342 में संशोधन करने और अण्विष्य सूची की पहचान अण्जा और अण्जण सूची के समान करने का काम नहीं किया जाना चाहिए।

4. अनुच्छेद 342 और 366 में भी संशोधन हैं जिन्हें नीचे उद्धृत किया गया है:—

“342क(1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां कोई राज्य है, वहां उसके राज्यपाल से परामर्श के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट करेगा, जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग होने के रूप में समझे जाएंगे।

(2) संसद विधि द्वारा खंड (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में या उससे किसी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को सम्मिलित या अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु पूर्वोक्त के सिवाय उक्त खंड के अधीन जारी किसी अधिसूचना में किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।”

‘(26ग) “सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों” से ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342क के अधीन पिछड़ा वर्ग होना समझा गया है।’

इस बात की आशंका है कि क्या संविधान 123वां संशोधन विधेयक, 2017 के अंतर्गत संशोधित अनुच्छेद 342क और 366 (26ग) का संयुक्त पठन राज्य सूची के लिए पिछड़े वर्गों के निर्धारण हेतु राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकार को छीन लेगा? क्या राज्य आयोग की सिफारिश पर अधिसूचित करने की राज्य सरकार में निहित शक्ति को छीना जा रहा है? जब तक हमारी संघीय प्रणाली है यह किसी भी कारण से नहीं हो सकता है। इन शंकाओं को दूर करने के लिए इस अनिश्चितता का कम से कम प्रवर समिति द्वारा निराकरण करना होगा जो मेरे अनुसार प्रारूप नियमों में संशोधन कर सकती है।

5. अंततः संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने और सौंपे गए कर्तव्यों के अतिरिक्त उपर्युक्त खामियों को दूर करना होगा ताकि पिछड़े वर्गों में प्रस्तावित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रति विश्वास पैदा हो सके।

महात्मा गांधी ने कहा था: ‘यदि साधन ही गलत है तो साध्य भी गलत होगा।’

विधेयक अपने मौजूदा स्वरूप में न्यायिक संवीक्षा की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। इसलिए, इंदिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की मूल भावना के अनुरूप आवश्यक संशोधन नितांत अपेक्षित है।

आपके विचारार्थ प्रस्तुत।

ह/-

(कानीमोझी)

ह/-

(हुसैन दलवाई)

ह/-

(टी०के० रंगराजन)

ह/-

(ए० नवनीतकृष्णन)

ह/-

(बी०के० हरिप्रसाद)

**हुसैन दलवाई**

संसद सदस्य (राज्य सभा)

सदस्य—अखिल भारती कांग्रेस समिति

सदस्य—शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

सदस्य—सरकारी आश्वासन संबंधी समिति

अध्यक्ष—मौलाना आजाद विचार मंच

अध्यक्ष—रेल मजदूर संघ (मध्य प्रदेश)

अध्यक्ष—टेक्सी चालक संघ, मुम्बई



सत्यमेव जयते

1/6, श्रीराम कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसायटी,

राममंदिर के सामने

खेड़नगर, बान्द्रा (पूर्व), मुम्बई-400 051,

दूरभाष: 022-2647 2833

फैक्स: 022 - 2647 7970

ईमेल: dalwaih@yahoo.co.in

एचडी/डीईएल/155

जुलाई, 2017

माननीय श्री भूपेन्द्र यादव जी,

**विषय: संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2017 में संशोधन हेतु प्रस्ताव**

प्रिय महोदय,

मैं संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2017 में कुछ संशोधनों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु नियत विधेयक के उपबंधों को सुदृढ़ करेंगे।

मैं अभारी रहूंगा यदि इन संशोधनों को सरकार को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रवर समिति के प्रतिवेदन में शामिल किया जाता है।

सादर।

आपका विश्वासी

ह/-

(हुसेन दलवाई)

सेवा में,

श्री भूपेन्द्र यादव

माननीय अध्यक्ष

संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2017

से संबंधित प्रवर समिति।

## संशोधन

खंड	अनुच्छेद	संशोधन	कारण
1	2	3	4
खंड 3	अनुच्छेद 338ख(1)	पृष्ठ 2, पंक्ति 3 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग शब्दों के बदले निम्नलिखित शब्दों को अंतःस्थापित किया जाए अर्थात्:  'राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग'	<ul style="list-style-type: none"> <li>● यह उचित है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्थापित किए जा रहे आयोग को यह नाम दिया जाए।</li> <li>● यह स्पष्ट करना भी महत्वपूर्ण है कि पहचान के लिए मानदंड 'सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन' रहेगा न कि सामाजिक, शैक्षिक या आर्थिक पिछड़ापन।</li> <li>● ऐसी चिंता व्यक्त की गई थी कि 5 सदस्यों का आयोग अन्य पिछड़े वर्गों जो कि देश की आबादी का बड़ा हिस्सा हैं के कल्याण के मामले की पर्याप्त रूप से देखभाल नहीं कर पाएगा। यह प्रस्ताव किया है कि इसके स्थान पर एक 7 सदस्यीय आयोग गठित किया जाए।</li> </ul>
खंड 3	अनुच्छेद 338ख(2)	पृष्ठ 2, पंक्ति 5 में 'अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य' शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों को अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पांच अन्य सदस्य, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के हों, इसमें एक सदस्य सचिव भी शामिल हैं जो भारत सरकार में सचिव स्तर के अधिकारी हैं या रहे हों।	<ul style="list-style-type: none"> <li>● मौजूदा अधिनियम के उपबंधों को बनाए रखना आवश्यक है जो आयोग के गठन हेतु प्रावधान करते हैं। इन उपबंधों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया था कि ऐसे निकाय को निष्पक्ष, गैर-राजनीतिक और विशेषज्ञ निकाय होना आवश्यक है।</li> </ul>
खंड 3	अनुच्छेद 338ख(2)	पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 7 के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्: “ परंतु यह कि अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा और उपाध्यक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय से कोई व्यक्ति होगा, कम से कम एक सदस्य महिला होंगी चाहिए, कम से कम एक सदस्य सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बतौर वर्गीकृत समुदाय से होना चाहिए। परंतु यह भी कि कम से कम दो सदस्य वैसे व्यक्ति होंगे चाहिए जिनके पास पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान हो।	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ऐसे उपबंध मौलिक हैं और इन्हें नियमों पर छोड़ने के बजाय अधिनियम में ही शामिल किया जाना चाहिए।</li> <li>● इस तथ्य कि—एसे उपबंध एनसीएससी या एनसीएसटी के लिए नहीं किए गए हैं एनसीएससीबीसी के लिए ऐसे उपबंध नहीं किये जाने का बहाना नहीं बनाया जा सकता।</li> <li>● यह उपबंध यह सुनिश्चित करने के लिए अंतःस्थापित किया गया है कि आयोग प्रारंभिक सूची बनाने में और तत्पश्चात् इसके संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और ऐसी सलाह दे जो सामान्यता सरकार के लिए बाध्यकारी हो।</li> </ul>
खंड 3	अनुच्छेद 338ख(5)	पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 11 के पश्चात् दो नए उप-खंड (क) और (ख) जोड़े जाएं और मौजूदा उप-खंड (क) से (च) को फिर से (ग) से (ज) पुनःसंख्याकित किया जाए। नए उपखंड (क) एवं (ख) को निम्नलिखित प्रकार से पढ़ा जाए:—	



‘ (क) (i) अनुच्छेद 342क(1) के अधीन लोक अधिसूचना के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की प्रारूप सूची की जांच तथा केंद्रीय सरकार को ऐसी सलाह देना जिसे यह उपयुक्त समझे।	● यह ईदिसा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश के मद्देनजर है।
(ii) आयोग द्वारा दी गई सलाह सामान्यता केन्द्रीय सरकार के लिए बाध्यकारी होगी।	● अधिसूचना जारी करते समय राष्ट्रपति और सूची का संशोधन करते समय, संसद को आयोग की सलाह की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि समावेशन/अपवर्जन इत्यादि की प्राथमिक भूमिका उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोग को दी गई थी।
परंतु यह कि यह केंद्रीय सरकार आयोग की सलाह से सहमत नहीं होती है तो यह इसका कारण लिखित में अभिलिखित करेगी और प्रारूप सूची के साथ-साथ ये कारण राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगी।	● यह उपबंध अति या न्यून समावेश की शिकायतों और अन्य उपबंधों जैसे कि पूर्व अधिनियम में भी उपबंधित किए गए हैं, की जांच करते समय समावेशन हेतु अनुरोध की जांच करते समय सिविल कोर्ट की शक्तियों का विस्तार करने के लिए किया गया है।
(ख) (i) सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित करने या अपवर्जित करने के लिए अनुरोधों की जांच करना तथा अनुच्छेद 342क(2) के अधीन सूची को संशोधित करने के लिए संसद को समर्थ बनाने के प्रयोजन से केंद्रीय सरकार को सलाह देना तथा ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन और न्यून समावेशन की शिकायतों को सुनना तथा केंद्रीय सरकार को ऐसी सलाह देना जो यह उपयुक्त समझे।	
(ii) आयोग द्वारा दी गई सलाह सामान्यता या केंद्रीय सरकार के लिए बाध्यकारी होगी।	
परंतु यह कि यदि केंद्रीय सरकार आयोग की सलाह से सहमत नहीं होती है तो यह इसका कारण लिखित में अभिलिखित करेगी और संसद की दोनों सभाओं में रखेगी।	
पृष्ठ 2 पर पंक्ति 41 और 42 के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:	
‘ (8) आयोग उप-खंड (क) एवं (ख) में यथासंदर्भित अनुरोधों और शिकायतों की जांच करते हुए या उप-खंड (ग) में यथासंदर्भित किसी मामले की जांच या खंड 5 के उप-खंड (घ) में यथासंदर्भित किसी शिकायत की जांच करते हुए.....करेगा’	

खंड 3 अनुच्छेद 338ख(8)

1	2	3	4
खंड 4	अनुच्छेद 342क(1)	<p>पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 19 के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:</p> <p>‘परंतु यह कि ऐसी सावजनिक अधिसूचना अनुच्छेद 338ख(5) के अंतर्गत आयोग द्वारा दिए गए परामर्श के आधार पर जारी की जाएगी और जारी होने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों में रखी जाएगी।’</p> <p>परंतु यह भी कि राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श उस राज्य के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा राज्यपाल को दिए गए परामर्श के आधार पर किया जाएगा।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● यह उपबंध यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि राष्ट्रपति आयोग और राज्यपाल राज्य आयोग की सलाह से बाध्य होंगे।</li> </ul>
खंड 4	अनुच्छेद 342क(2)	<p>पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 23 के बाद निम्नलिखित पंक्तियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:</p> <p>‘परंतु यह कि ऐसा कानून अनुच्छेद 338(5)(ख) के अंतर्गत आयोग द्वारा दिए गए परामर्श पर आधारित हो।’</p> <p>पृष्ठ 3 पर, अनुच्छेद 342क(2) के पश्चात् एक नया खंड जोड़ा जाए, अर्थात्:</p> <p>‘342क(3)—केंद्रीय सरकार पिछड़े वर्गों के रूप में मान्यता समाप्त कर दिए गए ऐसे वर्गों को अपवर्जित करने के उद्देश्य से या ऐसी सूची में नए पिछड़े वर्गों को सम्मिलित करने हेतु आयोग की सलाह पर किसी भी समय और अनुच्छेद 342क(1) के अंतर्गत अधिसूचित सूची के लागू होने की तिथि से दस वर्षों के समाप्त होने पर, और इसके पश्चात् दस वर्षों की प्रत्येक अनुवर्ती अवधि में उस सूची की समीक्षा करेगी।’</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● यह उपबंध यह सुनिश्चित करता है कि संसद को विधेयक के माध्यम से सूची संशोधित करते समय आयोग द्वारा दी गई सलाह पर विचार करे।</li> <li>● जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है कि और जैसा कि पूर्व अधिनियम में उपबंधित किया गया है, आयोग द्वारा दी गई सलाह के अनुसार सूची की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।</li> </ul>
खंड 4	अनुच्छेद 342क(3)		

## उपाबंध-II

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)  
से प्राप्त टिप्पणियां

डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी, संसद सदस्य राज्य सभा से प्राप्त उत्तर पर टिप्पणियां

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का नाम तथा उनकी टिप्पणियां	अनुच्छेद	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की टिप्पणियां
1	2	3	4
1.	कि पृष्ठ 2, पंक्ति 3,—के लिए “राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग” “अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय संवैधानिक आयोग” प्रस्थापित किया जाए।	अनुच्छेद 3	यह राष्ट्रीय आयोग संविधान के अनुच्छेद 338ख के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338क की तरह गठित किया जा रहा है। अतः संशोधन मान्य नहीं है।
2.	कि पृष्ठ 3, पंक्ति 5,— शब्द “तीन” के लिए “पांच” प्रस्थापित किया जाए।	उपबंध 338ख(2)	मौजूदा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी पांच सदस्य हैं। अतः, आयोग की संरचना को विस्तारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः संशोधन मान्य नहीं है।
3.	कि पृष्ठ 2, पंक्ति 9 के पश्चात्—निम्नलिखित अंतर्विष्ट किया जाए: “प्रावधान है कि कम से कम आयोग में एक महिला सदस्य होगी; यह भी व्यवस्था है कि आयोग के किसी सचिव तथा अन्य प्रमुख अधिकारियों सहित किसी सदस्य का कोई पद नब्बे दिन से अधिक अवधि के लिए रिक्त नहीं होगा।”	उपबंध 338ख(2)	किसी महिला सदस्य को शामिल करना इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए जाने वाले नियमों का भाग होगा। इस विधेयक को परिवर्तित/संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है। अतः संशोधन मान्य नहीं है।
4.	कि पृष्ठ 3, पंक्ति 13ए,—शब्द “पिछड़ा वर्गों” के पश्चात् शब्द “और इसकी सलाह को केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जैसा भी मामला हो, समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।” अंतर्विष्ट किया जाए।	अनुच्छेद 338ख(9)	अनुच्छेद 338ख(6) में केन्द्र से संबंधित अनुशंसा पर की गई कार्रवाई अथवा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के साथ-साथ संसद के प्रत्येक सदन में आयोग द्वारा एक रिपोर्ट पेश किए जाने की व्यवस्था की गई है। अतः संशोधन मान्य नहीं है।
5.	कि पृष्ठ 3, पंक्ति 16—“उसके राज्यपाल के साथ परामर्श के पश्चात्” के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए: “केवल राज्य सरकार की पूर्व अनुशंसा से तथा इस प्रकार की अनुशंसा पर उचित ध्यान देते हुए।”	अनुच्छेद 342क(1)	राज्यपाल से परामर्श राज्य सरकार की अनुशंसाओं पर ही निर्भर है। अतः संशोधन मान्य नहीं है।
6.	कि पृष्ठ 3, पंक्ति 13,—निम्नलिखित अंतर्विष्ट किया जाए: “(3) प्रत्येक राज्य सरकार, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उस राज्य में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग निर्दिष्ट करे, वह राज्य जिसे उस राज्य के संबंध में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्गों की राज्य सूची होना माना जाए। (4) राज्य विधि द्वारा किसी सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, उक्त को छोड़कर उक्त अनुबंध के अंतर्गत जारी किसी अधिसूचना को उपबंध (3) के अंतर्गत जारी किसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्गों को किसी उत्तरवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा, राज्य सूची में शामिल अथवा उससे हटा सकता है।”	अनुच्छेद 324क(2)	मौजूदा विधेयक केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय सूची तक सीमित है जिन्हें केन्द्रीय साकार द्वारा अधिसूचित किया जाना है। अतः संशोधन मान्य नहीं है।

## श्री दिलीप कुमार तिकी, संसद सदस्य, राज्य सभा से प्राप्त उत्तर पर टिप्पणियाँ

क्र० सं०	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का नाम तथा उनकी टिप्पणियाँ	अनुच्छेद	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की टिप्पणियाँ
1	2	3	4
1.	पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 16 में, “उसके राज्यपाल के साथ परामर्श के पश्चात्” को “केवल राज्य सरकार की पूर्व अनुशंसा से तथा इस प्रकार की अनुशंसा पर उचित ध्यान देते हुए प्रतिस्थापित किया जाए।”	अनुच्छेद 342क(1)	राज्यपाल से परामर्श राज्य सरकार की अनुशंसाओं पर ही निर्भर है। अतः संशोधन मान्य नहीं है।
2.	पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 17 और 18 में, वाक्यांश “इस संविधान के प्रयोजनार्थ” को हटा दिया जाए।	अनुच्छेद 342क(1)	“इस संविधान के प्रयोजनार्थ” वाक्यांश विधायी विभाग द्वारा एक विधायी आवश्यकता सलाह है। अतः संशोधन मान्य नहीं है।
3.	पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 18 में, “माना जाए” वाक्यांश के पश्चात् “केन्द्रीय सूची” में अंतर्विष्ट किया जाए।	अनुच्छेद 342क(1)	इस अनुच्छेद के अंतर्गत परिकल्पित सार्वजनिक केन्द्रीय सूची ही होगी। अतः संशोधन मान्य नहीं है।
4.	पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 23 के पश्चात्, निम्नलिखित दो पैराग्राफ अंतर्विष्ट किए जाएं: (3) “प्रत्येक राज्य सरकार, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उस राज्य में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग निर्दिष्ट करे, वह राज्य जिसे उस राज्य के संबंध में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्गों की राज्य सूची होना माना जाए।  (4) राज्य विधि द्वारा किसी सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, उक्त को छोड़कर उक्त अनुबंध के अंतर्गत जारी किसी अधिसूचना को उपबंध (3) के अंतर्गत जारी किसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्गों को किसी उत्तरवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा, राज्य सूची में शामिल अथवा उससे हटा सकता है।”	अनुच्छेद 342क(2)	मौजूदा विधेयक केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय सूची तक सीमित है जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना होता है। अतः संशोधन मान्य नहीं है।

क्र० सं०	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का नाम तथा उनकी टिप्पणियां	अनुच्छेद	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की टिप्पणियां
1	2	3	4
<b>श्री बी० के० हरिप्रसाद:</b>			
1.	अध्यक्ष न्यायिक पृष्ठभूमि का कोई भूतपूर्व न्यायधीश होना चाहिए; सदस्य सचिव भारत सरकार के एक भूतपूर्व सरकारी स्तर का अधिकारी होना चाहिए, एक समाज विज्ञानी तथा पिछड़ा वर्गों से संबंधित मामलों की जानकारी रखने वाले दो व्यक्ति।	अनुच्छेद 342ख(2)	यह मात्र एक सलाह है और इस विधेयक का भाग नहीं बन सकती। आयोग का गठन अधिनियमन पर तैयार की जाने वाली क्रियाविधियों में समाविष्ट किया जाएगा। अतः संशोधन मान्य नहीं है।
2.	अनुच्छेद 338(ख) खंड 3, उप खंड 9 को निम्नानुसार संशोधित किया जाए: “केंद्रीय तथा प्रत्येक राज्य सरकार आयोग से सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श लेंगे तथा एनसीबीसी राज्य सरकार से किन्हीं राज्य विशिष्ट मुद्दों पर परामर्श करेगा।”	अनुच्छेद 338 ख खंड(3) उप खंड(9)	प्रस्तावित आयोग के कर्तव्यों में से एक, जैसा कि अनुच्छेद 338ख(5)(ग) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, में उल्लेख है कि “सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर सलाह देने तथा केन्द्र तथा किसी राज्य के अंतर्गत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।” अतः संशोधन मान्य नहीं है।
3.	अनुच्छेद 342क(2) को निम्नानुसार संशोधित किया जाए: “राष्ट्रपति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह पर खंड (1) के अंतर्गत जारी किसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्गों की केन्द्रीय सूची में समावेशन अथवा विलोपन कर सकते हैं।”	अनुच्छेद 342क(2)	यह विधेयक जिस पर सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्गों की केन्द्रीय सूची में समुदायों के समावेशन और विलोपन के लिए संसद द्वारा विचार किया जाएगा, में आयोग के विचारों को भी समाविष्ट किया जाएगा। अतः संशोधन मान्य नहीं है।
4.	अनुच्छेद 338ख, खंड(5) को निम्नानुसार संशोधित किया जाए: आयोग का यह कर्तव्य होगा—उप खंड: 5(ग) सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना सलाह देना। विकास.....के पश्चात्.....पंक्ति समाविष्ट करें “सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्गों तथा केन्द्र और किसी राज्य के अंतर्गत उनके विकास की प्रक्रिया का मूल्यांकन करना।”	अनुच्छेद 338ख, खंड (5)	अनुच्छेद 338ख खंड(5) के अंतर्गत सभी उप खंड प्रस्तावित आयोग की एक भागीदारी की भूमिका इंगित करते हैं। अतः संशोधन मान्य नहीं है।
			उक्त के आलोक में माननीय संसद सदस्य द्वारा प्रस्तावित संशोधन मान्य नहीं है।
<b>श्रीमती कनीमोझी, श्री हुसैन दलवाई, श्री टी०के० रंगाराजन, श्री बी०के० हरिप्रसाद, श्री ए० नवनीत कृष्णन:</b>			
5.	सर्वप्रथम, जबकि अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़ा वर्गों के लिए एक संवैधानिक आयोग की व्यवस्था की गई है, यह समझना कठिन है कि इस संवैधानिक संशोधन में एक दूसरे अनुच्छेद में 338 के रूप में 338ख समाविष्ट करने की मांग क्यों की गई है। मूलतः अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों के लिए एक विशेष अधिकारी के संबंध में व्यवस्था है जिसमें इसे संशोधित करते हुए एससी और एसटी के लिए दो आयोगों में परिवर्तित कर दिया गया है। (65वां और 89वां संशोधन)।	अनुच्छेद 340	वर्तमान आयोग को अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित नहीं किया गया है, किंतु इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अंतर्गत गठित किया गया है। एक नया अनुच्छेद 338ख एनसीबीसी के लिए संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए अंतर्विष्ट किया जा रहा है, चूंकि अनुच्छेद 338 और 338क के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) को संवैधानिक दर्जा दिया गया था।

1	2	3	4
6.	वास्तविक रूप से एनसीबीसी का गठन एनसीबीसी अधिनियम, 1993 द्वारा गठित, को अनुच्छेद 340 के अंतर्गत इसे मान्यता देते हुए अंगीकृत किया जाना चाहिए अथवा अनुच्छेद 338 अथवा 338क (एनसीएससी और एनसीएसटी) के अंतर्गत विद्यमान आयोग के लिए अतिरिक्त प्रकार्यों के साथ समाविष्ट किए जाने की मांग की जानी चाहिए।	अनुच्छेद 340	मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित नहीं किया गया था किन्तु यह एनसीबीसी अधिनियम, 1993 के अंतर्गत इंद्रा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में एक सांविधिक निकाय के रूप से गठित किया गया था। माननीय न्यायालय ने संघ सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्गों के प्रयोजनार्थ स्थायी निकायों के रूप में गठित करने के निदेश दिए थे। इस प्रकार, मौजूदा एनसीबीसी को अनुच्छेद 340 के अंतर्गत मान्यता नहीं दी जा सकती है।
7.	यह समस्त मूल प्रावधान को संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017 के अंतर्गत हटा दिया गया है। ये कार्य संविधान के अनुच्छेद 3 के विपरीत है। इन कार्यों को छोड़कर, अब इस विधेयक, 2017 के अंतर्गत अन्य कार्य दिए गए हैं जो अपेक्षाकृत अधिक पर्यवेक्षण प्रकृति के हैं। इस प्रक्रिया में, वस्तुतः, अनुच्छेद 340 जिसमें पिछड़ा वर्गों के लिए समान भावना है, निष्प्रभावी हो गया है।	अनुच्छेद 340	एनसीबीसी की सलाह केन्द्रीय सूची में समावेशन/विलोपन के लिए किसी प्रस्ताव का एक अभिन्न अंग होगी जिसे संसद के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा। इससे केन्द्रीय सूची में समावेशन/विलोपन की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी चूंकि इनपर संसद द्वारा बहस की जाएगी और इनकी जांच की जाएगी।
8.	अनुच्छेद 340 में न केवल इन वर्गों के सामाजिक तथा शैक्षिक सरोकारों की जांच करने और उनके समक्ष पेश कठिनाइयों को दूर करने के लिए अनुशंसाएं करने के लिए एक पृथक आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था है किन्तु 'पिछड़ा वर्ग' शब्द को अनुच्छेद 340(1) में निर्धारित संदर्भ के परिपेक्ष्य में भी समझा जाना चाहिए।	अनुच्छेद 340	प्रस्तावित अनुच्छेद 338ख वस्तुतः अनुच्छेद 340 के अंतर्गत परिकल्पित एक आयोग के गठन में वस्तुतः सहायता करता है, बल्कि एक स्थायी आधार पर भी।
9.	इस बात पर गौर करना महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जातियों (चूंकि जिन्हें अधिकांशतः अस्पृश माना जाता था) और अनुसूचित जनजातियां (अधिकांशतः वन क्षेत्रों में रहने वाले) की पहचान सापेक्षतया एक आसान कार्य था जबकि अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची के अंतर्गत जातियों की पहचान के लिए अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक ज्ञान, सामाजिक अध्ययन और न्यायिक दृष्टिकोण अपेक्षित है।  उक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए एनसीबीसी अधिनियम, 1993 को अधिनियमित किया गया है। अब, मौजूदा एनसीबीसी के कार्यों को राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति को देना वस्तुतः एक पीछे हटने वाला कदम है।  अतः अनुच्छेद 342 को संशोधित तथा अन्य पिछड़े वर्गों की सूची की पहचान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची के समान नहीं की जानी चाहिए।	अनुच्छेद 342	प्रस्तावित आयोग का गठन सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्गों के हित से पीछे हटने के लिए नहीं होगा। अनुच्छेद 342क में केन्द्रीय सूची में समावेशन/विलोपन के प्रत्येक मामले की व्यापक जांच करने संबंधी व्यवस्था होगी। इस प्रकार के समावेशन/विलोपन संबंधी अंतिम शक्ति संसद के पास होगी।
10.	इस संबंध में यह आशंका है कि क्या संविधान 123वां संशोधन विधेयक, 2017 के तहत संशोधित अनुच्छेद 342 क तथा 366 (26-ग) को संयुक्त रूप से पाठन करने पर, राज्य सूची के लिए पिछड़े वर्गों के निर्धारण हेतु राज्य में पिछड़े वर्गों के	अनुच्छेद 342 क तथा 366 (26ग)	यह एक अनुपयुक्त आशंका है क्योंकि प्रस्तावित विधेयक से राज्य की सूची में समुदायों इत्यादि को को शामिल करने/हटाने संबंधी राज्य की शक्तियां समाप्त नहीं होगी।

1	2	3	4
	अधिकार समाप्त हो जाएंगे? क्या राज्य आयोग की सिफारिश पर अधिसूचना जारी करने की राज्य की शक्ति समाप्त की जा रही है? यह किन्हीं कारणों की वजह से संभव नहीं हो सकता है जब तक हमारे यहां संघीय प्रणाली का प्रावधान मौजूद है। कम से कम प्रवर समिति द्वारा इस अस्पष्टता को दूर किया जाना है ताकि आंशकाओं को दूर किया जा सके जो, यदि मैं कहूँ, मसौदा नियमों का संशोधन कर सकती है।		उपर्युक्त के मद्देनजर, माननीय सांसदों द्वारा प्रस्तावित संशोधन मान्य नहीं है।
	<b>श्रीमती कनिमोझी</b>		
11.	अतः अभी सृजित किए जा रहे नए संवैधानिक निकाय द्वारा राज्य को पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण में उनकी परंपरागत एवं अंगभूत भूमिका से किसी भी स्थिति में वंचित नहीं किया जाना चाहिए।		प्रस्तावित विधेयक से राज्य की सूची में समुदायों इत्यादि को शामिल करने/हटाने संबंधी राज्य की शक्तियां समाप्त नहीं होंगी।
12.	<b>आशोधन करना:</b> सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास की आयोजना-प्रक्रिया में भाग लेने एवं सलाह देना तथा संघ एवं किसी राज्य के तहत प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए उप-खंड (ग)।	अनुच्छेद 338 ख खंड 5	अनुच्छेद 338 ख (5) के अंतर्गत सभी उप-खंडों का आशय प्रस्तावित आयोग की सहभागिता संबंधी भूमिका से है।
13.	<b>अंतःस्थापन:</b> (छ) सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने संबंधी अनुरोध की जांच करने तथा ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अधिसमावेशन अथवा अल्प-संमोशन की शिकायतों की सनुवाई करना और केन्द्र सरकार को ऐसी सलाह देना जिसे वह उपयुक्त समझे।	अनुच्छेद 338 ख खंड 5	प्रस्तावित आयोग द्वारा शिकायतों की सुनवाई करने का प्रावधान अनुच्छेद 338 ख (5) के अंतर्गत किया गया है। किसी पिछड़े वर्ग के रूप में किसी वर्ग के समावेशन हेतु अनुरोधों की जांच के बारे में, आयोग के पास अधिनियमित होने पर जारी की जानी वाली कार्यपद्धतियों के भाग के रूप में उपलब्ध होगा।
14.	<b>अंतःस्थापन:</b> खंड 10. खंड 9 में उल्लिखित किन्हीं बातों के होते हुए भी, राज्य सरकार के पास सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्तियां रहेंगी।	अनुच्छेद 338 ख खंड 10	प्रस्तावित विधेयक से राज्य की सूची में समुदायों इत्यादि को शामिल करने/हटाने संबंधी राज्य की शक्तियां समाप्त नहीं होंगी।
15.	“राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद” को “राज्यपाल के द्वारा किए गए अनुरोधों पर” से प्रतिस्थापित करने हेतु खंड में संशोधन करना।	अनुच्छेद 342क(1)	राज्यपाल के साथ परामर्श में राज्यों से प्राप्त होने वाले अनुरोधों पर ही विचार नहीं किया जाता है बल्कि ऐसे अनुरोधों पर भी विचार किया जाता है जो केन्द्र सरकार से प्राप्त हों।
16.	<b>अंतःस्थापन:</b> राष्ट्रपति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह पर, खंड (1) के तहत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल कर सकते हैं/से निकाल सकते हैं।	अनुच्छेद 342 क खंड 2	प्रस्तावित आयोग के गठन से सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों में कमी नहीं होगी। अनुच्छेद 342 क के तहत केन्द्रीय सूची में समावेशन/विलोपन के प्रत्येक मामले की व्यापक जांच का प्रावधान होगा। ऐसे समावेशन/विलोपन की निर्णायक शक्ति संसद के पास होगी।
17.	<b>अंतःस्थापन:</b> किसी राज्य का राज्यपाल, सार्वजनिक अधिसूचना के तहत, उस राज्य के अंतर्गत या राज्य के किसी अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत या राज्य के नियंत्रणाधीन या उस राज्य के अंतर्गत शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान करने के प्रयोजनों के लिए सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट करें।	अनुच्छेद 342 क खंड 3	इस प्रस्तावित विधेयक का संबंध सिर्फ केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची से है।

1	2	3	4
18.	अंतःस्थापन: राज्यपाल, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह पर, खंड (3) के तहत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की राज्य सूची में समावेशन अथवा विलोपन कर सकते हैं।	अनुच्छेद 342क खंड 4	इस प्रस्तावित विधेयक का संबंध केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सिर्फ केन्द्रीय सूची से है।
	श्री हुसैन दलवाई, सांसद		उपर्युक्त के मद्देनजर, माननीय सांसद द्वारा प्रस्तावित संशोधन मान्य नहीं है।
19.	पृष्ठ 2, पंक्ति 3 में, 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' के स्थान पर निम्नलिखित पदबंध अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्: "सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग।"	अनुच्छेद 338 ख (1) खंड 3	इस खंड में इस बात का उपबंध है कि सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाएगा। इस नाम का साभिप्राय उपयोग किया गया है ताकि मौजूदा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ सामंजस्य बनाया रखा जा सके।
20.	पृष्ठ 2 पंक्ति 5 में पदबंध अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्यों के स्थान पर निम्नलिखित पदबंध अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्: "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य पांच सदस्य जो सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के व्यक्ति हैं, सदस्य सचिव, जो भारत सरकार के सचिव के रैंक में केन्द्र सरकार का अधिकारी हों या रहें हों, सहित"	अनुच्छेद 338 ख(2) खंड 3	मौजूदा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में पांच सदस्य हैं। विधेयक में इसी क्षमता का प्रस्ताव रखा गया है।
21.	पंक्ति 7 के पश्चात् पृष्ठ 2 पर निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए नामतः: "बशर्ते कि अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक समुदाय से एक व्यक्ति हो, कम से कम एक सदस्य महिला, कम से कम एक सदस्य अति पिछड़ा वर्ग या अत्यधिक पिछड़ा वर्ग या रूप में वर्गीकृत समुदाय से हो। बशर्ते कि कम से कम दो सदस्यों को पिछड़ा वर्गों से संबंधित मामलों में विशेषज्ञ ज्ञान प्राप्त होना चाहिए।"	अनुच्छेद 338 ख (2) खंड 3	इन पहलुओं पर इस विधेयक के विधायन पर नियमावली तैयार करते समय विचार किया जाएगा।
22.	पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 11 के पश्चात् दो नए उप खंडों (क) और (ख) को जोड़ा जाए तथा मौजूदा उपखंडों (क) से (च) को (ग) से (ज) के रूप में पुनर्अंकन किया जाए। नवीन उपखंड (क) और (ख) को इस प्रकार पढ़ा जाए:—  '(क) (i) अनुच्छेद 342 क (1) के तहत सार्वजनिक अधिसूचना हेतु राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की मसौदा सूची की जांच करने तथा केंद्र सरकार को ऐसी सलाह देने के लिए, जैसा उपयुक्त समझे।  (ii) इस आयोग द्वारा दी गई सलाह सामान्यतया केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी होगी।  बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार आयोग की सिफारिश से सहमत नहीं होती तो यह लिखित में अपने कारण रिकार्ड करेगी तथा मसौदा सूची के साथ ऐसे कारणों को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगी।	अनुच्छेद 338 ख (5) खंड 3	केंद्रीय सूची के संदर्भ में जातियों/समुदायों के समावेशन/विलोपन हेतु तौर तरीकों और प्रयोग में आने वाली मानक प्रक्रिया तैयार करते समय इन पहलुओं पर समुचित ध्यान दिया जाएगा।



1	2	3	4
	<p>(ख) (i) संसद को अनुच्छेद 342 (2) के तहत इस सूची में संशोधन करने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में समावेशन या विलोपन के अनुरोधों की जांच तथा केंद्र सरकार को सलाह देने तथा ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग के अधिक समावेशन तथा कम समावेशन की शिकायतों को सुनने और केंद्र सरकार को, जैसा यह उपयुक्त समझे, ऐसी सलाह देने के लिए।</p> <p>(ii) आयोग द्वारा दी गई सलाह सामान्यतया केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी होगी।</p> <p>बशर्ते कि "यदि केंद्र सरकार आयोग की सलाह से सहमत नहीं होती तो इसे लिखित में अपने कारण दर्ज करने होंगे तथा संसद के दोनों पटलों पर प्रस्तुत करने होंगे।</p>		
23.	<p>पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 41 और 42 के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः:</p> <p>(8) आयोग, उपखंड (क) और (ख) में यथा उल्लिखित अनुरोधों और शिकायतों की जांच करते समय अथवा उपखंड (ग) में उल्लिखित किसी मामले की जांच करते समय अथवा खंड (5) के उपखंड (घ) में उल्लिखित किसी शिकायत की जांच करते समय।</p>	<p>अनुच्छेद 338 ख (8) खंड 3</p>	<p>इस विधेयक के अंतर्गत सिविल न्यायालय को दी गई शक्तियां दिए गए सुझावों को पूर्ण करती है।</p>
24.	<p>पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 19 के लिए निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाए नामतः:</p> <p>बशर्ते कि आयोग द्वारा अनुच्छेद 338 ख (5) (क) के तहत दी गई सलाह के आधार पर ऐसी सार्वजनिक अधिसूचना जारी की जा सकेगी तथा इसे जारी करने के पश्चात् यथा संभव संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा।</p> <p>बशर्ते कि आगे यह भी उस राज्य के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा राज्यपाल की सलाह के आधार पर राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श होगी।'</p>	<p>अनुच्छेद 342 क (1) खंड 4</p>	<p>मौजूदा विधेयक के प्रावधान केंद्रीय सूची तक सीमित है।</p>
25.	<p>पृष्ठ 3 पर पंक्ति 23 के पश्चात् निम्नलिखित पंक्तियां अंतर्विष्ट की जाए नामतः:</p> <p>'बशर्ते कि ऐसे कानून अनुच्छेद 338 ख (ख) के तहत आयोग द्वारा दी गई सलाह पर आधारित होते हैं।</p>	<p>अनुच्छेद 342 क (2) खंड 4</p>	<p>जैसा कि पहले उल्लिखित है केंद्रीय सूची के संदर्भ में समावेशन/विलोपन के मामलों की प्रक्रिया को दर्शाते हुए तैयार की जाने वाली उपयुक्त कार्य पद्धति को सुझाए गए पहलुओं को समाविष्ट किया जाए।</p>
26.	<p>पृष्ठ 3 पर, अनुच्छेद 342 क (2) के पश्चात् एक नया खंड जोड़ा जाए, नामतः:</p> <p>'342 क (3) - केंद्र सरकार, किसी भी समय तथा अनुच्छेद, 342 क (1) के तहत अधिसूचित सूची के लागू होने के दस वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् तथा इसके पश्चात् प्रत्येक उत्तरवर्ती दस वर्षों की अवधि पर, आयोग की सलाह पर, उन जातियों, जो पिछड़ा वर्ग के दायरे को पार कर लिया है, के निष्कासन के लिए सूची में संशोधन करने के लिए अथवा ऐसी सूची में नए पिछड़ा वर्गों को शामिल कर सकती है।</p>	<p>अनुच्छेद 342 (3) खंड 4</p>	<p>केंद्रीय सूची के संदर्भ में समावेशन/विलोपन एक सतत् प्रक्रिया है।</p>

उपर्युक्त के मद्देनजर, माननीय सांसद द्वारा प्रस्तावित संशोधन मान्य नहीं है।

संविधान (एक सौ तेईसवा संशोधन) विधेयक, 2017 संबंधी राज्य सभा की प्रवर समिति  
की बैठक का कार्यवृत्त

I

पहली बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 17 अप्रैल, 2017 को म०पू० 11.00 बजे, कमरा सं० 62, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

1. भूपेन्द्र यादव— अध्यक्ष

सदस्य

2. डॉ० विकास महात्मे
3. श्री राम नारायण दुडी
4. श्री बी० के० हरिप्रसाद
5. श्री सुखेन्दु शेखर राय
6. श्री ए० नवनीतकृष्णन
7. श्री टी० के० रंगराजन
8. मीर मोहम्मद फैयाज
9. श्री स्वपन दासगुप्ता

सचिवालय

1. श्री जे० जी० नेगी, संयुक्त सचिव
2. श्री आर० एस् रावत, अपर निदेशक
3. श्रीमती मोनिका बा, उप निदेशक

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्रीमती जी० लता कृष्णा राव, सचिव
2. श्री बी० एल्० मीणा, संयुक्त सचिव
3. श्री प्रकाश तरसोराकर, निदेशक
4. श्री के० नारायणन, एम डी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्तीयन और विकास निगम

विधि और न्याय मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री सुरेश चन्द्र, सचिव
2. श्री रामायण यादव, अपर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. डॉ० रीता वशिष्ठ, अपर सचिव
2. श्री आर० श्रीनिवास, अपर विधायी परामर्शदाता

2. प्रारंभ में अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें लोक सभा द्वारा यथा पारित संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ तथा अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रवर समिति को सौंपे जाने के बारे में उन्हें सूचित किया। उन्होंने विधेयक की जांच किए जाने में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में समिति के सदस्यों के विचार मांगे और सदस्यों को उन विशेषज्ञों/संगठनों के नाम सुझाने हेतु आमंत्रित किया जिन्हें अपने विचार साझा करने के लिए समिति के समक्ष बुलाया जा सकता है।

3. समिति के सदस्यों ने विधेयक के उपबंधों के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए और उनकी राय थी कि राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु, केरल, कर्णाटक और आन्ध्र प्रदेश के विचारों को इस विधेयक के उपबंधों में शामिल किया जाना चाहिए। समिति की यह भी राय थी कि व्यापार संघों और बार संगठनों सहित विभिन्न संगठनों की राय पर विचार किया जाना चाहिए।

4. तत्पश्चात्, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव ने समिति के समक्ष पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया जिसमें उन्होंने उस पृष्ठभूमि, जिसमें विचाराधीन विधेयक को तैयार किया गया था और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के इतिहास के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया। तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे अर्थात् (i) क्या किसी अधिसूचित वर्ग के 'समावेशन' और 'निष्कासन' के आधार पर निर्णय लेने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई वस्तुपरक मापदंड निर्धारित किए गए थे; (ii) विचाराधीन विधेयक के लागू होने के बाद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों की स्थिति क्या होगी; (iii) विचाराधीन विधेयक के लागू होने के बाद अफिक् की मौजूदा सूची की स्थिति क्या होगी; (iv) अफिक् सूची में वर्गों के समावेशन या निष्कासन के बारे में निर्णय लेने में राज्यपाल की क्या भूमिका होगी।

5. सचिव, विधिक कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय ने सूचित किया कि मंडल आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए ग्यारह संकेतक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अफिक् की सूची में शामिल किए जाने के लिए वर्गों को तय करने हेतु व्यापक ढांचा उपलब्ध कराएंगे। समिति को सूचित किया गया कि प्रस्तावित संशोधन मात्र राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान करने के लिए था जबकि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग वैसे ही कार्य करते रहेंगे जैसे वे कर रहे हैं। यह भी सूचित किया गया कि संसद में दो विधेयक प्रस्तुत कर दिए गए हैं, एक है संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 और दूसरा है निरसन और व्यावृत्ति खंड विधेयक जोकि उन सभी कार्रवाई से बचाएगा जोकि अभी तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा की गई है।

6. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पिछड़े वर्गों के अंतर्गत अजा और अजजा के विपरीत दो सूचियां हैं अर्थात् केन्द्रीय सूची और राज्य सूची। केन्द्रीय सूची केन्द्रीय सरकार की संस्थाओं में शिक्षा और रोजगार के अवसरों का उपबंध करती है। राज्य सूची में राज्य अपनी पिछड़ा वर्ग सूची में जिसे भी चाहें समाविष्ट या निष्कासित करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके परिणामस्वरूप, यदि कोई कतिपय वर्ग है, जोकि केन्द्रीय सूची में नहीं है, उसे अभी भी राज्य सूची में पाया जा सकता है। यह राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्वतंत्रता और विशेषाधिकार है जोकि उसके पास बना रहेगा।

7. बैठक को समाप्त करते हुए अध्यक्ष ने निदेश दिया कि प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन के एक माह के अन्दर प्रवर समिति के पास विचाराधीन विधेयक के उपबंधों के संबंध में टिप्पणियां/ज्ञापन आमंत्रित करते हुए सभी अग्रणी राष्ट्रीय और स्वदेशी समाचारपत्रों में प्रेस विज्ञप्ति जारी की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी निदेश दिया कि सभी राज्यों से अनुरोध किया जाए कि विधेयक के संबंध में समिति के विचारार्थ अपनी टिप्पणियां/विचार प्रस्तुत करें। उन्होंने सदस्यों को दोबारा आमंत्रित किया कि उन विशेषज्ञों/संगठनों के नाम प्रस्तुत करें जिन्हें मौखिक साक्ष्य हेतु समिति के समक्ष बुलाया जा सकता है।

8. बैठक की कार्यवाही का शब्दशः अभिलेख रखा गया।

9. तत्पश्चात् बैठक म०प० 12.31 बजे समाप्त हुई।

नई दिल्ली;  
17.04.2017

आर० एस० रावत  
अपर निदेशक।

संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 संबंधी प्रवर समिति की बैठक का  
कार्यवृत्त

II

दूसरी बैठक

संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) संबंधी प्रवर समिति की दूसरी बैठक सोमवार, 24 अप्रैल, 2017 को म०पू० 11.00 बजे, समिति कक्ष 'घ', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

1. भूपेन्द्र यादव — अध्यक्ष

सदस्य

2. श्री चुनीभाई कांजीभाई गोहेल
3. डॉ० विकास महात्मे
4. श्री राम नारायण डूडी
5. श्री बी० के० हरिप्रसाद
6. श्री मधुसूदन मिस्त्री
7. श्री दिग्विजय सिंह
8. श्री हुसैन दलवाई
9. श्री सुखेन्दु शेखर राय
10. श्री ए० नवनीतकृष्णन
11. श्रीमती कनीमोझी
12. श्री अनिल देसाई
13. श्री विश्वजीत दैमारी
14. श्री राजीव चन्द्रशेखर
15. श्री स्वपन दासगुप्ता

सचिवालय

1. श्री महेश तिवारी, निदेशक
2. श्री आर० एस० रावत, अपर निदेशक
3. श्री राकेश आनन्द, अपर निदेशक
4. श्रीमती मोनिका बा, उप निदेशक
5. सुश्री छाया गुप्ता, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. डॉ० जी० नारायण राजू, सचिव (विधायी विभाग)
2. श्री सुरेश चन्द्र, सचिव (विधिक कार्य)
3. डा० रीता वशिष्ठ, अपर सचिव

4. श्री रामायण यादव, अपर सचिव
6. श्री आर० श्रीनिवास, अपर विधायी परामर्शदाता

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के प्रतिनिधि**

1. श्री बी० एल० मीणा, संयुक्त सचिव
2. श्री के० नारायणन, एमडी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

2. प्रारंभ में अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें सूचित किया कि समिति के निर्णय के अनुसार समाचारपत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर इस विधेयक के संबंध में ज्ञापन आमंत्रित करते हुए 22 अप्रैल, 2017 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि गत बैठक में समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार एनबीसीएफडीसी के एमडी समिति के समक्ष संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण देंगे और तत्पश्चात् विधिक कार्य विभाग के सचिव आरक्षण से संबंधित मुद्दे के संबंध में इंदिरा साहनी से शुरू हुए प्रमुख निर्णयों से लेकर अन्य प्रमुख निर्णयों के बारे में समिति को भी सूचित करेंगे।

3. समिति ने पहले एनबीसीएफडीसी को सुना जिसने पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया और तत्पश्चात् सदस्यों ने उसमें उठाए गए बिन्दुओं के बारे में स्पष्टीकरण मांगे। एक प्रश्न पूछा गया कि क्या कोई व्यक्ति, जिसने 'मुद्रा' के अंतर्गत ऋण लिया है, एनबीसीएफडीसी की योजना के अंतर्गत ऋण के लिए भी आवेदन कर सकता है। यह स्पष्टीकरण भी मांगा गया कि महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजना क्यों है, जोकि सिर्फ एक लाख रुपए तक सीमित है, जबकि एनबीसीएफडीसी योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति पांच लाख रुपए तक का ऋण लेने के लिए पात्र है। अफि० को कौशल प्रदान करने हेतु एनबीसीएफडीसी की तारीफ करते हुए सदस्यों ने कहा कि कौशल प्राप्त करने वाले लोगों की कोई निगरानी नहीं थी या उनका पता नहीं लगाया जा सकता था। सदस्यों ने सुझाव दिया कि एनबीसीएफडीसी को कौशल विकास योजना ने तहत प्रत्येक लाभार्थी का डाटाबेस रखना चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि वह किस प्रकार लाभान्वित हुआ है, क्या वह अभी भी कौशल प्राप्त कर रहा है और क्या वह उस कौशल का लाभ उठाने में सफल हुआ है।

4. एनबीसीएफडीसी के एमडी ने उत्तर दिया कि यदि मुद्रा योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लोग एनबीसीएफडीसी के लक्षित समूह के हैं तो बैंक एनबीसीएफडीसी योजना के जरिए पुनः वित्तपोषित कर सकते हैं क्योंकि एनबीसीएफडीसी योजना में ब्याज दर काफी कम है अर्थात् पांच और छह के बीच, जबकि मुद्रा योजना में यह लगभग 10 प्रतिशत है। चैनल भागीदारी, जोकि बैंक हैं, को दो योजनाओं के अंतर्गत धनराशि दी जाती है — एक है परियोजना वित्तीयन, जिसमें एनबीसीएफडीसी उन्हें निधियां देता है और वे इसे नए ऋण लेने वालों को दे सकते हैं; दूसरा है पुनः वित्तीयन के अंतर्गत जिसमें वे ऋण लेने वाले उन लोगों की सूची प्रस्तुत कर सकते हैं जिन्होंने पहले ही उच्चतर ब्याज दरों पर ऋण लिया है और वह कम ब्याज दर वाले ऋण में परिवर्तित हो जाता है। बैंकों के साथ संयोजन गत एक वर्ष से ही हुआ है और एनबीसीएफडीसी बैंकों से अनुरोध कर रहा है कि वे उन लोगों की अपनी सूची जांच लें जिन्होंने मुद्रा ऋण लिया है और यदि वे अफि० से संबंध रखते हैं और लक्षित समूह से हैं तो वे इसे कम ब्याज दर पर प्राप्त कर सकते हैं। महिलाओं के लिए ऋण के संबंध में प्रश्न के बारे में उन्होंने कहा कि अन्य ऋणों के लिए महिलाएं भी पात्र हैं लेकिन यह ऋण कमतर ब्याज दर पर हैं। उन्होंने कहा कि वे निश्चित रूप से विचार करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वह कैसे महिलाओं के लिए अपनी कवरेज को बढ़ा सकते हैं और साथ ही महिलाओं के लिए उच्चतर राशि के ऋण प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने डाटाबेस बनाने के लिए नौकरी पोर्टल की शुरुआत की थी जोकि निगम के पास उपलब्ध होगा। इसके पास उन व्यक्तियों के मोबाइल नम्बर और मौजूदा नियोक्ता के नाम और फोन नम्बर का रिकॉर्ड है। वे वेबसाइट सूचना को लोकप्रिय नौकरी पोर्टल के साथ जोड़ने की योजना बना रहे हैं।

5. सदस्यों ने इंगित किया कि एनबीसीएफडीसी का मुख्य विचार पिछड़े वर्गों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अधिकांश पिछड़े वर्गों की सहायता करना है। इसके मद्देनजर सदस्यों ने 'द्विगुणित गरीबी रेखा' की संकल्पना पर ही प्रश्न उठाए। एनबीसीएफडीसी के एमडी ने स्पष्ट किया कि 'द्विगुणित गरीबी रेखा' को पूर्व योजना आयोग द्वारा परिभाषित किया गया था। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा के रूप में 49,000/- रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 60,000/- रुपए तय किए हैं। सदस्यों ने यह भी कहा कि शैक्षणिक ऋणों पर चार प्रतिशत ब्याज की

दर उच्च है और पिछड़े वर्गों से आने वाले छात्रों के लिए बहुत ज्यादा है। एनबीसीएफडीसी के एमडी ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक अतिरिक्त नीति है जहां शैक्षणिक ऋणों पर उद्भूत होने वाले सभी ब्याज का भुगतान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसलिए एनबीसीएफडीसी ने अपनी राज्य चैनल एजेंसियों के साथ इस योजना का प्रचार किया है और अनेक राज्य एजेंसियों ने भी इस राशि का दावा करना शुरू कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त धनराशि राज्य एजेंसियों को दी जाती है जो बदले में इसे संबंधित छात्र के खाते में जमा कर देती है।

6. उन्होंने यह भी कहा कि कृषि में काफी ज्यादा संभावनाएं हैं चूंकि अधिकांश कृषिविद् पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने गत वर्ष कृषि क्षेत्र कौशल परिषद् में नाम दर्ज कराया था लेकिन दुर्भाग्यवश वे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। अब वे खाद्य प्रसंस्करण और अन्य ऐसे क्षेत्रों की सभी संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं जहां वे प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं क्योंकि किसानों के साथ एक प्रमुख मसला है कि वे अपनी उपज का प्रसंस्करण करने में सक्षम नहीं हैं और उन्हें कमतर मूल्य मिलता है। उन्होंने विपणन और किसानों के संबंध में कहा कि उन्होंने हस्तशिल्प के विकास आयुक्त के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जहां वे कार्यकारी एजेंसी हैं। यह मूलतः उन डिजाइनों की पहचान करने के प्रयोजनार्थ है जिसका उन्नयन किया जा सकता है। हस्तशिल्प के विकास आयुक्त द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा। वे ऐसे समूहों के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने ई-विपणन संकल्पना का प्रयास किया है लेकिन यह गरीब किसानों में बहुत लोकप्रिय नहीं है क्योंकि यदि उपभोक्ता को उत्पाद पसंद नहीं आता है तो उन्हें बेची न गई वस्तुओं का नुकसान सहना होगा। इसलिए वे कैम्प उपागम पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे विभिन्न राज्य हैं जिनके पास अधिकांश पिछड़े वर्गों की देखभाल करने के लिए अपने पृथक निगम हैं। वे किसी भी राज्य निगम को अपनी सूची में शामिल कर रहे हैं जोकि अफिंक् के से किसी भी सीमांत समुदाय के लिए कार्य कर रहा है और साथ ही निधियां भी प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रतिवर्ष केवल लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान करते हैं। और इसका उपयोग करते हुए वे लगभग 350 करोड़ रुपए का संवितरण कर रहे हैं। 20,000 रुपए के औसतन ऋण पर विचार करते हुए वे प्रतिवर्ष 1.7 या 1.8 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं। वे 23 लाख लोगों तक पहुंच गए हैं जोकि देश के आकार को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एनबीसीएफडीसी का अधिदेश वित्तीय और कौशल विकास दोनों के जरिए पिछड़े वर्गों का सामाजिक आर्थिक विकास है। लेकिन वे किस सीमा तक कर सकते हैं यह उनके पास उपलब्ध निधियों पर निर्भर करता है। वे मूल्यांकन अध्ययन करते हैं और उन्होंने पाया कि वो लोग जिनकी उन्होंने सहायता की है, वे गरीबी रेखा से या द्विगुणित गरीबी रेखा से निश्चित रूप से ऊपर उठ गए हैं। लेकिन अपनी अद्यतन पहल के हिस्से के रूप में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए वे विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के साथ बातचीत कर रहे हैं। संभवतया यह सहायता कर सकता है क्योंकि वहां निधीयन इन कार्यालयों के जरिए होता है, जिन्हें निश्चित रूप से निधि की बड़ी धनराशि प्राप्त हुई है।

7. सदस्यों ने अफिंक् के अंतर्गत आने वाले विभिन्न खानाबदोश लोगों को वित्तीय सहायता के जरिए स्थिरता देने के बारे में भी पूछताछ की। वे जानना चाहते थे कि क्या उनके लिए एनबीसीएफडीसी के पास कोई योजना है। समिति को सूचित किया गया कि कुछ खानाबदोश अफिंक् की श्रेणी में आते हैं जबकि कुछ पिछड़े वर्गों में भी आते हैं। कुछ खानाबदोश दोनों श्रेणियों में ही नहीं आते हैं। तथापि, अफिंक् की सभी श्रेणियों को वित्तपोषित करना कठिन है लेकिन वे उनके कौशल विकास पर ध्यान दे रहे हैं।

8. तत्पश्चात् समिति ने विधि और न्याय मंत्रालय के विचारों को सुना। अध्यक्ष ने विधि सचिव को कहा कि मंत्रालय से प्राप्त टिप्पण स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाता है कि कौन सा मामला पदोन्नति से संबंधित है और कौन सा मामला अफिंक् आरक्षण से संबंधित है। उन्होंने यह भी इंगित किया कि मंत्रालय के टिप्पण में उल्लेख था कि उच्चतम न्यायलय ने आयोग के गठन का सुझाव दिया था लेकिन यह आयोग क्यों आवश्यक है और इस सांविधानिक आयोग का प्रयोजन क्या है, इसका उल्लेख भी टिप्पण में नहीं किया गया है। अनुच्छेद 338ख से संबंधित सांविधानिक आयोग के बारे में कुछ उल्लिखित नहीं है कि क्या इसे चुनौती दी गई थी या चुनौती नहीं दी गई थी, क्या स्थिति थी आदि। अध्यक्ष ने कहा कि जहां तक विधिक पहलू का संबंध है समिति चाहती है कि गंभीर कार्य किया जाए और इसलिए मंत्रालय से अनुरोध किया कि टिप्पण को संशोधित करे और अगली बैठक में पूर्ण और व्यापक प्रस्तुतीकरण के साथ तैयार होकर आए।

9. बैठक की कार्यवाही का शब्दशः अभिलेख रखा गया।

10. बैठक म० 12.33 बजे समाप्त हुई।

नई दिल्ली;  
24.04.2017

महेश तिवारी  
निदेशक।

संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 संबंधी राज्य सभा की प्रवर समिति की बैठक का कार्यवृत्त

III

तीसरी बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 2 मई, 2017 को म०पू० 11.00 बजे, मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

1. श्री भूपेन्द्र यादव — अध्यक्ष

सदस्य

2. श्री चुनीभाई कांजीभाई गोहेल
3. श्री मधुसूदन मिस्त्री
4. श्री दिग्विजय सिंह
5. श्री शरद यादव
6. श्री ए० नवनीतकृष्णन
7. श्री टी०के० रंगराजन
8. श्री सी०एम० रमेश
9. श्री नरेश गुजराल
10. श्री विश्वजीत दैमारी
11. श्री राजीव चन्द्रशेखर
12. श्री स्वपन दासगुप्ता
13. श्री राम कुमार कश्यप

सचिवालय

1. श्री जे० जी० नेगी, संयुक्त सचिव
2. श्री महेश तिवारी, निदेशक
3. श्री आर० एस० रावत, अपर निदेशक
4. श्री राकेश आनन्द, अपर निदेशक
5. श्रीमती मोनिका बा, उप सचिव
6. सुश्री छाया गुप्ता, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री सुरेश चन्द्र, सचिव
2. श्री रामायण यादव, अपर सचिव
3. श्री आर०एस० वर्मा, उप विधिक सलाहकार



### विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. डॉ० जी० नारायण राजू, सचिव
2. डॉ० रीता वशिष्ठ, अपर सचिव
3. श्री आर० श्रीनिवास, अपर विधायी परामर्शदाता

2. प्रारंभ में, अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें सूचित किया कि सचिव, विधिक कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय इंदिरा साहनी *बनाम* भारत संघ से लेकर अब तक आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई के मुद्दे से संबंधित प्रमुख निर्णयों के संबंध में समिति को बताएंगे। उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से यह अनुरोध भी किया कि वे गैर-सरकारी विशेषज्ञों के नामों, को अंतिम रूप प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाए जिन्हें, समिति संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 के संबंध में अपने विचार साझा करने के लिए अपने समक्ष बुला सकती है।

3. वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के मसले के संबंध में विधिक कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय ने समिति को बताया कि इंदिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में निर्देश दिया था कि आयोग या अधिकरण के रूप में एक स्थायी निकाय अवश्य होना चाहिए जिससे अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में समूहों, वर्गों और खंडों का गलत समावेशन या गैर-समावेशन की शिकायतों की जा सकती है और ऐसी सूची तैयार की जा सकती है। ऐसे निकाय का उक्त प्रकृति की शिकायतों की जांच करने और उचित आदेश पारित करने की शक्ति भी दी जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि आयोग की सलाह/राय सामान्य रूप से सरकार पर बाध्यकारी होनी चाहिए। तथापि, जहां सरकार इसकी सिफारिशों से सहमत नहीं होती है, इसे इसके कारणों को जरूर अभिलिखित करना चाहिए। भले ही किसी नए वर्ग/समूह को अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल करने का प्रस्ताव हो, ऐसे मामले को प्रथम दृष्टया उक्त निकाय को भी अवश्य भेजा जाना चाहिए और इसकी सिफारिशों के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

4. समिति को यह भी सूचित किया गया कि उच्चतम न्यायालय का विचार है कि इस निकाय में इस क्षेत्र के सरकारी और गैर-सरकारी विशेषज्ञों को शामिल अवश्य किया जाना चाहिए और उसे उचित तथा प्रभावी जांच करने के लिए आवश्यक शक्तियां जरूर दी जानी चाहिए। यह भी समान रूप से वांछनीय है कि प्रत्येक राज्य ऐसे निकाय का गठन करे, एक ऐसा कदम जिससे वास्तविक शिकायतों का समाधान करने में काफी सहायता मिलेगी। पिछड़े वर्ग के नागरिकों, जिनके पक्ष में आरक्षण प्रदान किये जाने हों, की पहचान करने और उन्हें विनिर्दिष्ट करने की शक्ति के सहवर्ती के तौर पर अनुच्छेद 16 के खंड (4) के अंतर्गत या अनुच्छेद 340 के साथ पठित अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत इस प्रकार का निकाय बनाया जा सकता है। चार माह के अंदर ऐसे निकाय का गठन केन्द्रीय स्तर और राज्यों के स्तर पर किया जाए। उन्हें तत्काल कार्यशील बनाया जाना चाहिए और उन्हें उपर्युक्त प्रकृति की शिकायतों तथा मसलों, यदि कोई प्राप्त हों, पर ध्यान देने और उनकी जांच करने की स्थिति में होना चाहिए। भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के लिए इस प्रकार की निकाय द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया को तैयार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस प्रकार गठित निकाय अथवा निकायों से अपि वर्गों की सूचियों की समय-समय पर समीक्षा के मामले में परामर्श भी किया जा सकता है। तदनुसार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था और यह कार्य उस आयोग को सौंपा गया था तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 तैयार किया गया था।

5. एनसीबीसी के 1993 में सांविधानिक निकाय के स्थान पर सांविधिक निकाय के रूप में गठन के संबंध में विशिष्ट प्रश्न पर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के विवरण में उन्होंने उल्लेख किया है कि इंदिरा साहनी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सरकार को चार माह की अवधि के अंदर स्थायी निकाय का गठन करने का निर्देश दिया था। उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था और इसीलिए उन्होंने अध्यादेश के जरिए इस आयोग का गठन किया। तत्पश्चात् इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया गया। इसलिए उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्देश का अनुपालन करने के लिए किसी सांविधानिक निकाय का नहीं बल्कि सांविधिक निकाय का गठन किया।

6. तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा अर्थात् (i) विशेष रूप से आरक्षण के अनुपात को तय करने के विशेष संदर्भ में इंदिरा साहनी से संबंधित निर्णय में अफिक् के नागरिकों के आरक्षण से संबंधित उठने वाले बिन्दुओं और साथ ही उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा इसे तय करने के कारण स्पष्ट करने; (ii) विभिन्न न्यायिक घोषणाओं का इस विचाराधीन विधेयक पर कितना वास्तविक प्रभाव पड़ेगा और अफिक् के लिए आरक्षण नीति के मार्ग में आने वाले किसी भी निर्णय को रद्द करने के लिए किन-किन संशोधनों को विधेयक में शामिल किए जाने की जरूरत है; (iii) क्या इस विधेयक के द्वारा गठित किए जाने वाले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को बुलाने, अन्वेषण करने और पूछताछ करने और अन्य शक्तियां होंगी, इस विधेयक के कार्यान्वयन और कार्यकरण को स्थानीय और राज्य स्तर पर और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन-कौन से उपबंध किए जा सकते हैं; (iv) तमिलनाडु जैसे किसी एक राज्य में खास समुदायों का किस प्रकार अफिक् के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसी के साथ-साथ इन समुदायों को आन्ध्र प्रदेश में अग्रणी समुदाय के रूप में वर्गीकृत किया गया है; (v) प्रवर समिति के विचाराधीन विधेयक के लागू होने के बाद राज्यों के अधिकार किस सीमा तक प्रभावित होंगे; (vi) क्या ऐसे कोई न्यायिक निर्णय हैं जो इस समय मौजूद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सांविधानिक निकाय बनने से रोकते हैं? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा प्रदान कीजिए; (vii) क्या ऐसी कोई पद्धति है जिसके जरिए अन्य पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण के लाभ उन राज्यों में प्रदान किए जा सकते थे जहां यह अभी तक प्रदान नहीं किए गए हैं; और (viii) विभिन्न राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर को तय करने के लिए विभिन्न मापदंड अपनाए जाते हैं। इन संबंध में, क्या इस विधेयक में संशोधन करने के लिए कोई उपबंध किए जा सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अफिक् को उन राज्यों, जहां अजा या अज्जा की बहुलता है, में आरक्षण के लाभों से वंचित न किया जाए?

7. बैठक को समाप्त करते हुए अध्यक्ष ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को निदेश दिया कि वह समिति की अगली बैठक में संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत 'सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग' शब्दों को शामिल करने के कारणों के बारे में इसे बताए। उन्होंने मंत्रालय को यह भी निदेश दिया कि वह इस मुद्दे के संबंध में संविधान में प्रथम संशोधन पर संसद में हुए वाद-विवाद और नेहरू जी के भाषण की प्रति समिति को उपलब्ध कराए चूंकि यह संशोधन सांप्रदायिक आरक्षणों के मसले के संबंध में मद्रास राज्य बनाम चम्पाकम दोरैराजन निर्णय की पृष्ठभूमि में इस संशोधन को उपस्थित किया गया था। उन्होंने मंत्रालयों को यह भी निदेश दिया कि वे समिति की अगली बैठक से पहले सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर अपनी टिप्पणियों/स्पष्टीकरणों को प्रस्तुत करें।

8. बैठक की कार्यवाही का शब्दशः अभिलेख रखा गया।

9. तत्पश्चात् बैठक म०पू० 11.51 बजे समाप्त हुई।

नई दिल्ली;

02.05.2017

महेश तिवारी

निदेशक।

संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 संबंधी राज्य सभा की प्रवर समिति  
की बैठक का कार्यवृत्त

IV

चौथी बैठक

संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 संबंधी राज्य सभा की प्रवर समिति की चौथी बैठक  
सोमवार, 15 मई, 2017 को म०पू० 11.00 बजे, मुख्य समिति कक्ष 'ग' संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

1. श्री भूपेन्द्र यादव — अध्यक्ष

सदस्य

2. डॉ० विकास महात्मे
3. श्री राम नारायण डूडी
4. श्री बी० के० हरिप्रसाद
5. श्री मधुसूदन मिस्त्री
6. श्री हुसैन दलवाई
7. प्रो० राम गोपाल यादव
8. श्री शरद यादव
9. श्री सुखेन्दु शेखर राय
10. श्री ए० नवनीतकृष्णन
11. श्रीमती कानीमोझी
12. श्री अनिल देसाई
13. श्री विश्वजीत दैमारी
14. श्री स्वप्न दासगुप्ता
15. श्री राम कुमार कश्यप

सचिवालय

1. श्री जे० जी० नेगी, संयुक्त सचिव
2. श्री महेश तिवारी, निदेशक
3. श्री आर० एस० रावत, अपर निदेशक
4. श्री राकेश आनन्द, अपर निदेशक
5. सुश्री छाया गुप्ता, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. डॉ० जी० नारायण राजू, सचिव (विधायी विभाग)
2. श्री सुरेश, चन्द्र, सचिव (विधि कार्य)

3. डॉ० रीता वशिष्ठ, अपर सचिव
4. श्री रामायण यादव, अपर सचिव
5. श्री के० बीसवाल, संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता
6. श्री दिवाकर सिंह, अपर विधायी परामर्शदाता
7. श्री आर० श्रीनिवास, अपर विधायी परामर्शदाता

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के प्रतिनिधि**

1. श्रीमती जी० लता कृष्ण राव, सचिव
2. श्री बी० एल० मीणा, संयुक्त सचिव
3. श्री के० नारायण, एमडी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

**विशेषज्ञ/साक्षीगण**

1. डॉ० के० वीरमनी, अध्यक्ष, द्रविड़ारकषगम
2. न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) वी० ईश्वरैया, पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय-पिछड़ा वर्ग आयोग
3. श्री एस० के० खारवेन्थन, पूर्व-संसद सदस्य (लोक सभा) एवं पूर्व सदस्य, एनसीबीसी
4. श्री जी० करुणानिधी, महासचिव, अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ

2. प्रारंभ में, अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें सूचित किया कि समिति ने कुछ विशेषज्ञों को इस विषय पर समिति को संक्षेप में जानकारी देने के लिए बुलाया है। तत्पश्चात् समिति ने डॉ० के० वीरमनी, अध्यक्ष, द्रविड़ारकषगम; न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) वी० ईश्वरैया, पूर्व अध्यक्ष, एनसीबीसी; श्री एस० के० खारवेन्थन, पूर्व संसद सदस्य (लोक सभा) तथा पूर्व सदस्य, एनसीबीसी; और श्री जी० करुणानिधी, महासचिव, अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ को सुना। अध्यक्ष ने विशेषज्ञों से अनुरोध किया कि वे ओबीसी आयोग और ओबीसी के बीच कार्य करने के अपने व्यावहारिक अनुभव के आधार पर विधेयक के विभिन्न उपबंधों एवं संबद्ध पहलुओं पर अपने विचार साझा करें। उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव, सचिव विधि कार्य और सचिव, विधायी विभाग से समिति के चर्चा के दौरान उठाये गये किसी विषय के संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया।

3. समिति ने सर्वप्रथम डॉ० के० वीरमनी को सुना जिन्होंने समिति के समक्ष अपने अभिसाक्ष्य, में बताया कि सम्बद्ध अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को दिये गये संवैधानिक अधिकारों की तरह ही अन्य पिछड़े वर्गों को भी ये अधिकार दिये जाने चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि आज सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, किसी भी राज्य सूची में, केन्द्र सरकार में रोजगार के लिए या केन्द्र सरकार के शैक्षणिक संस्थान में नामांकन के उद्देश्य से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं हैं। किसी राज्य में एससी/बीसी केन्द्रीय सूची में शामिल नहीं हैं। उनकी राय थी कि यदि संशोधन को मौजूदा रूप में पारित कर दिया जाता है, तो कई राज्यों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े कई लोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नहीं रह जाएंगे।

4. विधेयक में अपने प्रस्तावित संशोधनों की रूप रेखा प्रस्तुत करते हुए, उन्होंने बताया कि प्रस्तावित खण्ड 3, प्रस्तावित अनुच्छेद 338ख 5(ग) को सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेने और सुझाव देने को शामिल करने हेतु संशोधित किया जाना है, जो एनसीबीसी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए समान उपबंधों की तरह सक्षम बनाएगा। प्रस्तावित अनुच्छेद 338ख(9) को हटाया जाना है जिससे राज्य सरकार के पास सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्तियां बनी रहेंगी। प्रस्तावित अनुच्छेद 338(2) को इस उपबंध के साथ संशोधित किया जाना चाहिए कि अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो।

5. उन्होंने यह भी बताया कि प्रस्तावित अनुच्छेद 342क(1) में मौजूदा “उसके राज्यपालों से परामर्श के पश्चात्”, शब्दों के बजाय “उसके गवर्नर से अनुरोध प्राप्त होने पर” शब्दों को जोड़ा जाए। उन्होंने बताया कि यदि “उसके राज्यपाल से अनुरोध प्राप्त होने पर” शब्दों को संशोधन में जोड़ा जाए तो स्वयं ही उनको सुना जाएगा और इस तरह देश में सहभागी लोक तंत्र अपनाया जाएगा। अतएव, भारत सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत किसी अन्य प्राधिकार के अंतर्गत पदों के आरक्षण हेतु उपबंधित करने के उद्देश्य हेतु, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संदर्भ में राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट करेंगे। दूसरे, अनुच्छेद 342क(2) के अंतर्गत, संसद कानून के द्वारा ऐसा कर सकती है कहने के बजाय उन्होंने सुझाव दिया कि इस खण्ड के अंतर्गत अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट सामाजिक और आर्थिक रूप से विनिर्दिष्ट किए गए पिछड़े वर्गों को राष्ट्रपति शामिल या बाहर कर सकते हैं।

6. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि नया अनुच्छेद 342क(3) जोड़ कर राज्य के राज्यपाल को राज्य या राज्य के किसी प्राधिकारी के अंतर्गत या राज्य के नियंत्रण के अंतर्गत या राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में सीटों क्योंकि यह राज्य दर राज्य बदलता है के अंतर्गत पदों के आरक्षण हेतु उपबंध करने के उद्देश्य से, एक अधिसूचना द्वारा एससी/बीसी को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति दी जा सकती है। साथ ही, अनुच्छेद 342क(4) जोड़ कर राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति दी जा सकती है कि वह संबंधित राज्यों और पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह पर खण्ड 3 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट एससी/बीसी की राज्य सूची को शामिल या बाहर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि केवल ऐसे संशोधन ही संघवाद की अवधारणा के अनुकूल होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि यदि यह विधेयक वर्तमान प्रारूप में देश का कानून बनता है, तो राज्यों को राज्य में किसी वर्ग को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित करने से वंचित कर दिया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन उच्चतम न्यायालय द्वारा मंडल आयोग मामले में दिये गये निर्देश के विरुद्ध है। अनुच्छेद 342क, यथा प्रस्तावित, संघवाद की अवधारणा का उल्लंघन करेगा। यह स्पष्ट और मौजूद खतरा है कि कई राज्यों में कई एससी/बीसी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग का दर्जा खो देंगे।

7. तत्पश्चात् समिति ने न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) वी० ईश्वरैया को सुना। उन्होंने समिति के समक्ष प्रस्तुत किया कि इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ मामले में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम वर्ष 1993 में लागू किया गया था। यह एक शक्तिहीन आयोग है, जिसकी एक मात्र शक्ति थी ओबीसी सूची में शामिल किये जाने के लिए सिफारिश करना। प्रत्येक दस वर्षों में, पुनरीक्षण किया जाना है। किन्तु दुर्भाग्य से, कोई पुनरीक्षण नहीं हुआ क्योंकि कोई सामाजिक आर्थिक जातीय गणना उपलब्ध नहीं थी। मंडल आयोग ने सामाजिक आर्थिक जाति गणना की सिफारिश की, किन्तु भारत सरकार ने घोषणा की कि सामाजिक आर्थिक जातीय गणना संग्रह करना सरकार की नीति है। सामाजिक-आर्थिक जातीय गणना वर्ष 2011 में की गयी या किन्तु उसमें भी, यह दर्शाने के लिए कोई कॉलम नहीं है कि क्या यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है या नहीं। किन्तु जातीय गणना में, सभी विवरण वर्ष 2011 में संगृहीत किये गये थे। उसमें वह स्थायी है या अर्ध-स्थायी, उसकी योग्यता, वह दसवीं कक्षा उत्तीर्ण है या उसने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है, क्या वह दैनिक मजदूर है या साप्ताहिक मजदूर है या सरकारी कर्मचारी है दर्शाया गया था। उसमें इक्कीस कॉलम हैं। इसलिए, अब वर्ष 2011 के पश्चात् सामाजिक-आर्थिक जातीय गणना उपलब्ध है। जब तक सामाजिक आर्थिक जातीय गणना को सतर्कतापूर्वक प्रकाशित और वर्गीकृत नहीं किया जाता है, किसी संवैधानिक आयोग के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग कौन है यह पहचान कर पाना संभव नहीं है। निस्संदेह, जाति आधारित पहचान एक बात है किन्तु कुछ समय के बाद नये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग उभर सकते हैं। यही उच्चतम न्यायालय ने कहा है। यदि कोई, पिता, बेटा और पोता, चाहे वह किसी जाति या समुदाय का हो, रिक्षा चालक या बढ़ई या धोबी या मछुआरे का कार्य जारी रखता है, जो कोई भी वह व्यवसाय जारी रखता है, उसकी पहचान की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने इन्द्रा साहनी बनाम भारतीय संघ के मामले में बताया है कि जाति आधारित पहचान एक बात है किन्तु पिछड़े वर्ग की व्यवसाय सह-आय आधारित पहचान भी की जानी है।

8. उन्होंने अपनी राय व्यक्त की कि ओबीसी की दो सूची नहीं हो सकती हैं कि एक राज्य की हो और दूसरी केन्द्र सरकार की और यह कि केवल एक सूची होनी चाहिए। यह संविधान के संघीय ढांचे को प्रभावित नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक समान नीति होनी चाहिए। उन्होंने निवेदन किया कि अध्यक्ष उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया

कि उन्होंने प्रस्तावित विधान का पूर्ण रूप से समर्थन किया है और विधेयक में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

9. तत्पश्चात् समिति ने श्री एस० के० खारवेंथन, पूर्व-सदस्य, लोक सभा को सुना। उन्होंने पिछड़े वर्ग की शिकायतों का निवारण करने के लिए एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा देने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। उन्होंने उपध्याक्ष पद के सृजन का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि यह आयोग एससी और एसटी आयोग के समतुल्य है। यद्यपि उन्होंने खण्ड 338ख5(ग) में एक विसंगति के बारे में बताया। एससी और एसटी आयोग में योजना प्रक्रिया में भागीदारी हेतु एक उपबंध है। किन्तु, नये प्रस्ताव में, एनसीबीसी के लिए वह उपलब्ध नहीं है। उन्होंने निवेदन किया कि इस विसंगति को दूर किया जाए। वर्ष 1993 से एनसीबीसी के सृजन के पश्चात्, यहां तक कि ओबीसी के लिए निधि आवंटन एससी/एसटी के तुलना में बहुत कम रहा है। उस विसंगति को भी दूर किया जाना है।

10. अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में है। उन्होंने बताया कि इंदिरा साहनी मामले में बहुमत के निर्णय के अनुसार, यह कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि आयोग के अध्यक्ष के रूप में एक न्यायाधीश की नियुक्त किया जाना है। इंदिरा साहनी निर्णय के पैरा 847 के अनुसार यह बताया गया कि अधिक सम्मिलित किये जाने की शिकायतों की जांच करने के लिए एक स्थायी सांविधिक विषय की अपेक्षा है। केवल सम्मिलित और बाहर किए जाने के उद्देश्य से यह राज्य और केंद्र के लिए सृजित किया गया था। उस समय, उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में एक न्यायाधीश को नियुक्त किया, किन्तु अधिकतर राज्यों ने न्यायाधीश नियुक्त नहीं किये हैं। अब नये प्रस्तावित आयोग के पास ओबीसी लोगों की शिकायतों का निवारण करने हेतु बहुत शक्तियाँ हैं। ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाना है, जो एक विशेषज्ञ है, वैसा व्यक्ति जिसके पास विषय-वस्तु की जानकारी है और जमीनी स्तर पर संपर्क है।

11. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में उनके छह वर्षों के अनुभव के अनुसार अध्यक्ष और सदस्य पिछड़े वर्ग से हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि सदस्य सचिव भी अवश्य रूप से ओबीसी से होना चाहिए। केवल तभी ओबीसी के कल्याण हेतु सहयोग और उचित प्रशासन होगा। उन्होंने यह भी राय व्यक्त की कि प्रस्तावित अधिनियम को नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए ताकि अदालतों में विवाद से बचा जा सके।

12. तत्पश्चात्, समिति ने श्री जी० करुणानिधि महासचिव, अखिल भारतीय ओबीसी कर्मचारी कल्याण संघ को सुना। विधेयक का समर्थन करते हुए, उन्होंने विशेषकर खण्ड 3 में, अनुच्छेद 338ख(2) में संशोधन का सुझाव दिया। उनकी राय थी कि पूर्व आयोग की तरह अध्यक्ष न्यायपालिका से होना चाहिए। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश उचित रहेगा और सदस्यों तथा अध्यक्ष के बीच संतुलन रहेगा। उन्होंने बताया कि आयोग के कार्यों का विधेयक में उल्लेख नहीं किया गया है और यह सुझाव दिया कि आयोग को नागरिक के किसी भी वर्ग के समावेश, बहुतायत-समावेशन या न्यून-समावेशन हेतु अनुरोध की जांच करनी चाहिए और आयोग का विचार आमतौर पर केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी होना चाहिए। यह सिफारिश पहले की समिति ने ओबीसी के लिए अपने पहले प्रतिवेदन में कर दी है जो इसने 27 अगस्त, 2012 को संसद में प्रस्तुत किया। उक्त प्रतिवेदन में कहा गया है कि संविधान संशोधन विधेयक में ओबीसी सूची में शामिल किये जाने पर बाहर किये जाने की शक्ति और सूची संशोधन हेतु एनसीबीसी से परामर्श करने की भारत सरकार की बाध्यता के साथ-साथ प्रचलित एनसीबीसी अधिनियम के अंतर्गत एनसीबीसी की मौजूदा शक्तियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस पहलू का विधेयक में उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने अनुरोध किया कि इस सुझाव को शामिल किया जाए।

13. अनुच्छेद 338ख (5)(ग) के संबंध में उन्होंने सुझाव दिया कि खण्ड संशोधित किया जाए और योजना प्रक्रिया में “भागीदारी और सलाह” शब्दों को जोड़ा जाए। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में पहले ही इसकी सिफारिश की जा चुकी है। ओबीसी कल्याण संबंधी समिति ने अपने प्रतिवेदन में पहले ही सुझाव दिया है कि ओबीसी के लिए एक अलग उपयोजना चाहिए। इसलिए इस तर्ज पर उप-समिति की सिफारिश को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना है जिससे कि योजना प्रक्रिया में भागीदारी के लिए एनसीबीसी के पास शक्ति रहे।

14. उन्होंने सुझाव दिया कि खण्ड 3 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 338ख(9) को हटाया जाना है जिससे कि राज्य सरकारों के पास शक्तियां बनी रहेंगी। अन्ततः खण्ड 4 में, उन्होंने सुझाव दिया कि 342क (1) और 342क (2) में संशोधन किया जाना चाहिए और 343क(3) 343क(4) में भी दो परिवर्तन किए जाने चाहिए जिससे कि पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्यों के पास शक्ति बरकरार रहे।

15. इस विचार पर कि एनसीबीसी की शक्ति को विधेयक में विहित नहीं किया गया है, अध्यक्ष ने बताया कि एनसीबीसी की शक्ति प्रस्तावित अनुच्छेद 338ख (5) में विहित है। जहां तक सम्मिलित और बाहर किया जाने का संबंध है, अनुच्छेद 342 में, वह शक्ति संसद के पास है। उन्होंने बताया कि समिति विशेषज्ञों/साक्षियों द्वारा दिए गए सुझावों का अध्ययन करेगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आगामी बैठक 5 जून को होगी जिसमें समिति कुछ मंत्रालयों और विशेषज्ञों को इस विषय पर सुनेगी।

16. बैठक की कार्यवाही का शब्दशः अभिलेख रखा गया।

17. तत्पश्चात् बैठक म०प० 1.05 बजे स्थगित हुई।

नई दिल्ली;  
15.05.2017

महेश तिवारी  
निदेशक।

संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 संबंधी राज्य सभा की प्रवर समिति  
की बैठक का कार्यवृत्त

V

पांचवीं बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 5 जून, 2017 को म०पू० 11.00 बजे, कमरा संख्या 74, संसदीय ग्रंथालय, संसद भवन परिसर, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

1. श्री भूपेन्द्र यादव — अध्यक्ष

सदस्य

2. श्री बी० के० हरिप्रसाद
3. श्री मधुसूदन मिस्त्री
4. श्री दिग्विजय सिंह
5. श्री हुसैन दलवाई
6. प्रो० रामगोपाल यादव
7. श्री शरद यादव
8. श्री सुखेन्दु शेखर राय
9. श्री ए० नवनीतकृष्णन
10. श्री टी० के० रंगराजन
11. श्री दिलीप कुमार तिकी
12. श्री प्रफुल्ल पटेल
13. श्रीमती कानीमोझी
14. श्री अनिल देसाई
15. श्री नरेश गुजराल
16. श्री बिश्वजीत दैमारी
17. श्री स्वपन दासगुप्ता

सचिवालय

1. श्री एम० के० खान, संयुक्त सचिव
2. श्री महेश तिवारी, निदेशक
3. श्री आर० एस० रावत, अपर निदेशक
4. श्री राकेश आनन्द, अपर निदेशक
5. श्रीमती मोनिका बा, अप सचिव
6. सुश्री छाया गुप्ता, अवर सचिव



**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय विभाग) के प्रतिनिधि**

1. श्रीमती जी० लता कृष्णा राव, सचिव
2. श्री बी० एल० मीणा, संयुक्त सचिव
3. श्री के० नारायण, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम

**विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के प्रतिनिधि**

1. श्री सुरेश चन्द्र, सचिव
2. श्री रामायण यादव, अपर सचिव

**विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि**

1. डॉ० जी० नारायण राजू, सचिव
2. डॉ० रीता वशिष्ठ, अपर सचिव
3. श्री आर० श्रीनिवास, अपर विधायी परामर्शदाता

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के प्रति प्रतिनिधि**

1. श्री भानु प्रताप शर्मा, सचिव
2. सुश्री अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधि**

1. श्री के० के० शर्मा, सचिव
2. सुश्री इशिया रॉय, संयुक्त सचिव
3. प्रो० वी० के० मल्होत्रा, सदस्य सचिव, आईसीएसएसआर
4. डॉ० जसपाल संधु, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

**वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के प्रतिनिधि**

1. श्री अशोक लवासा, सचिव
2. सुश्री एनी जॉर्ज मैथ्यू, संयुक्त सचिव
3. श्री संदीप दवे, संयुक्त सचिव

**वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) के प्रतिनिधि**

1. श्रीमती अंजली चिब दुग्गल, सचिव
2. श्री अनिल कुमार खाची, अपर सचिव
3. श्री मदनेश कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

**साक्षीगण**

1. श्री कपिल हरीशचन्द्र पाटिल, सदस्य विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान परिषद
2. श्री रयागा कृष्णैया, एमएलए, तेलंगाना विधान परिषद
3. श्री हरिभाई राठौड़, पूर्व संसद सदस्य और एमएलसी, महाराष्ट्र विधान परिषद
4. श्री पी० एस० कृष्णन, भूतपूर्व सचिव, कल्याण मंत्रालय

5. श्री साहू अक्षय भाई, मुख्य समन्वयकर्ता, राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग परिषद
6. श्री गुट्टरी वेंकटेश्वर राव, अध्यक्ष, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग प्रजा कल्याण संगठन
7. प्रो० पी० सी० पतंजलि, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग विकास मंच
8. श्री हसीब ए० अज़ीज़ नादाफ
9. प्रो० प्रकाश सोनावाने
10. श्री हंसराज, अध्यक्ष, अति पिछड़ा वर्ग महासंघ
11. श्री विश्वनाथ पाटिल, अध्यक्ष, कुन्बी सेना राम वड़ी
12. श्री शब्बीर अहमद अंसारी, अखिल भारतीय मुस्लिम अन्य पिछड़ा वर्ग संगठन
13. डॉ० कैलाश गौड़, पूर्व सदस्य महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
14. श्री हाजी शौकत भाई तम्बोली

2. प्रारंभ में, अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची के बारे में संक्षेप में जानकारी दी। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि जनता से ज्ञापन/सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन के परिणामस्वरूप 72 ज्ञापन प्राप्त हुए थे। उन्होंने संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 के उपबंधों के संबंध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया के बारे में भी उन्हें सूचित किया। तत्पश्चात् उन्होंने वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग और वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिवों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव को समिति के समक्ष संक्षिप्त में अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया।

3. वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने समिति को सूचित किया कि जब यह विधेयक उनके विभाग में आया था तब उन्होंने इसका समर्थन किया था। उन्होंने सूचित किया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं तैयार करता है और व्यय विभाग नियमों/विनियमों के आधार पर इन योजनाओं का मूल्यांकन करता है। इस समय पिछड़े वर्गों के लिए 9 योजनाएं कार्यशील हैं जिनका परिचालन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा किया जाता है जिनका बजट वर्ष 2017-18 में कुल बजट 6833/- करोड़ रुपए है। उन्होंने समिति को आश्वस्त किया कि भविष्य में भी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने से पहले वे लोग अपने मूल्यांकन तंत्र के अनुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा भेजी गई योजनाओं की जांच करने का प्रयास करेंगे।

4. वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव ने बताया कि वे लोग विधेयक के उपबंधों से सहमत थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने बैंको और अन्य वित्तीय संस्थाओं में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने के लिए 1993 में विस्तृत निर्देश परिचालित कर दिए थे। तत्पश्चात् 1997 में अ०पि०व० के लिए पृथक संपर्क अधिकारी को नियुक्त करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए थे जबकि पहले केवल एक संपर्क अधिकारी अ०जा०/अ०ज०जा० और अ०पि०व० के संबंध में देखरेख कर रहा था। हाल की में वर्ष 2014 में चयन बोर्ड और समितियों में अ०जा०, अ०ज०जा०, अ०पि०व०, अल्पसंख्यक और महिलाओं की अनिवार्य आधार पर उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

5. तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगें अर्थात् (i) समस्त बैंकिंग क्षेत्र में अ०पि०व० से महाप्रबंधकों की संख्या; (ii) चयन समिति/बोर्ड की संरचना जो कि बैंकिंग क्षेत्र में उम्मीदवारों का साक्षात्कार आयोजित करता है; (iii) राष्ट्रीयकृत बैंकों में समूह क, ख, ग और घ में अ०पि०व० की प्रतिशतता; (iv) क्या बैंक प्राथमिकता क्षेत्र के उधार देने वाले मानदंडों को पूरा कर रहे हैं और कौन-कौन सी कमियां हैं और इसके क्या कारण हैं; (v) मुद्रा योजना से अ०ज०जा०, अल्पसंख्यकों और अ०पि०व० को दिए गए ऋणों के संबंध में आंकड़े; (vi) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा दिए गए ऋण सीधे आवेदक को दिए जाते हैं या इसमें राज्य सरकारें भी शामिल हैं और जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा; और (vii) उस प्रक्रिया

को शीघ्रता प्रदान करने के लिए उठाए जाने वाले कदम जिसके जरिए अपिक्व के कल्याण के लिए निधियां राज्य सरकारों के पास समय पर पहुंचती हैं।

6. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव ने समिति को छात्रों के प्रवेश के संबंध में स्थिति और साथ ही अपिक्व उम्मीदवारों के संबंध में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा केन्द्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों में संकाय की भर्ती के बारे में सूचित किया। उन्होंने समिति को केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के प्रभावों के बारे में भी सूचित किया। उन्होंने सूचित किया कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय की भर्ती के संबंध में इस पर चर्चा करने के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति के सम्मेलन हॉल में एक बैठक आयोजित की गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि भर्तियों में कमजोर वर्गों को यथोचित महत्व प्रदान किया जाए। इसी प्रकार विशेष भर्ती अभियान चलाकर भारतीय प्रबंधन संस्थान में कमजोर वर्गों से संकाय की भर्ती करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। यूजीसी के सचिव ने भी समिति को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अपिक्व के छात्रों के प्रवेश की स्थिति और साथ ही जेएनयू तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के विशेष संबंध में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अपिक्व संकाय की भर्ती के बारे में भी संक्षेप में जानकारी दी।

7. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव ने समिति को सूचित किया कि जब यह विधेयक टिप्पणियों के लिए उनके पास आया था तो उन्होंने इस पर अपनी सहमति दे दी थी। जहां तक आरक्षण के अनुसार नौकरियों में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का संबंध है उन्होंने सूचित किया कि वे दस बड़े विभागों की निगरानी कर रहे थे और यह सुनिश्चित कर रहे थे कि आरक्षित वर्ग की सीटें शीघ्रतिशीघ्र भरी जाएं। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि नौकरियों में प्रतिनिधित्व वांछित स्तर के करीब पहुंच जाएगा। वास्तव में उन्होंने 22 अक्टूबर, 2014 को एक कांज़ा तक जारी कर दिया था जिसमें प्रत्येक विभाग से आरक्षित पद की रिक्तियों के संबंध में सटीक स्थिति का आकलन करने हेतु आंतरिक अध्ययन के और इन्हें नहीं भरे जाने के कारणों को बताने के लिए कहा गया था। उन्होंने यह भी सूचित किया कि इन्दिरा साहनी निर्णय के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने क्रीमी लेयर के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर डीओपीटी ने दिनांक 8 सितंबर, 1993 को एक कांज़ा जारी किया जिसमें क्रीमी लेयर को तय किए जाने के तरीके का वर्णन किया गया था। इसने इस मुद्दे को काफी हद तक सुलझाने में मदद की है। केवल उन्हीं उम्मीदवारों के संबंध में कठिनाई है जिनके माता-पिता सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में कार्य करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उक्त कांज़ा उल्लेख करता है कि उनकी समानता समूह 'क' केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में तय की जाएगी। यह समानता अभी तक तय नहीं की गई है जिसके कारण आय की सीमा को क्रीमी लेयर का दर्जा तय करने के लिए मानदंड के रूप में लिया जाता है।

8. तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगे अर्थात् (i) संघ लोक सेवा आयोग के कितने सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित थे; (ii) क्या अधिसंख्या पदों का सृजन बैकलॉग रिक्तियों की संख्या को कम करने में मदद करेगा; (iii) किसी उम्मीदवार की योग्यता का आकलन करने के लिए कौन-कौन से मापदंड हैं; (iv) उस मामले की स्थिति क्या है जिसमें पात्र उम्मीदवारों की क्रीमी लेयर स्थिति उच्च न्यायालय द्वारा तय की जानी थी; और (v) क्या सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी 400 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया था क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण कार्यान्वित कर दिया गया था। अध्यक्ष ने डीओपीटी के सचिव को यह भी निदेश दिया कि 1993 से पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव भेजे और उनके संबंध में सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए थे। उन्होंने पिछड़ा वर्ग संबंधी संसदीय समिति की सिफारिशों और उन पर की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के विचारार्थ सूचना मांगी।

9. तत्पश्चात् अध्यक्ष ने मौखिक साक्ष्य के लिए विशेषज्ञों/व्यक्तियों/संगठनों का स्वागत किया। उन्होंने विधेयक के महत्वपूर्ण उपबंधों के बारे में उन्हें सूचित किया और फिर उन पर उनकी राय मांगी। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग प्रजा कल्याण संघ के अध्यक्ष श्री गुदुरी वेंकटेश्वर राव की राय थी कि पुनर्गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और छह सदस्य होने चाहिए ताकि देश की अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी का इसमें पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व हो सके। इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग में किसी जाति को शामिल किए जाने के लिए इसके संसद में भेजे जाने से पहले इसे एनसीबीसी द्वारा संस्तुत किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य, डा० कैलाश गौड की राय थी कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान

किया जाना चाहिए और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में किसी को जोड़ने या हटाने से पहले संबंधित राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से इसके साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

10. पिछड़ा वर्ग विकास मंच के अध्यक्ष प्रो० पी०सी० पतंजलि की राय थी कि एनसीबी के अध्यक्ष को या तो समाजशास्त्री या सेवानिवृत्त अथवा सेवारत न्यायाधीश होना चाहिए ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के लिए समुदायों को जोड़ने या हटाने में न्याय किया जा सके। श्री हरिभाऊ राठौड़, पूर्व संसद सदस्य ने विधेयक में सभी स्थानों पर एकल शब्द 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के प्रयोग की जरूरत पर बल दिया और उनकी राय थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को लाभों के उचित वितरण हेतु विभिन्न समूहों में श्रेणीकृत किया जाना चाहिए। प्रो० प्रकाश सोनावले की राय थी कि एनसीबीसी का अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए और उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए ताकि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए कि विमुक्ति की गई और घुमंतु जनजातियों को न्याय मिल सके।

11. श्री हाजी शौकत भाई तंबोली की राय थी कि और अधिक प्रभावी कार्यकरण हेतु राज्य और राष्ट्रीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बीच समन्वय होना चाहिए। उन्होंने राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्रों को प्राप्त करने में उम्मीदवारों के सामने पेश आ रही कठिनाइयों पर प्रकाश डाला और इसके उपचार की मांग की। श्री हसीब ए० अज़ीज़ नादाफ की राय थी कि देश में पिछड़े वर्गों की प्रतिशतता का आकलन करने के लिए जनगणना की आवश्यकता है और अन्य पिछड़ा वर्गों का उचित वर्गीकरण भी किया जाना चाहिए। श्री शबीर अहमद अंसारी, अखिल भारतीय मुस्लिम अन्य पिछड़ा वर्ग संगठन की राय थी कि शब्द "सामाजिक" राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम में शामिल किया जाना चाहिए और उस समिति के गठन के संबंध में स्पष्टता होनी चाहिए जोकि एनसीबीसी के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगी। अति पिछड़ा वर्ग महासंघ के अध्यक्ष श्री हंसराज ने भी अन्य पिछड़ा वर्ग के उचित वर्गीकरण की मांग की। उन्होंने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए सांविधानिक दर्जे की भी मांग की और यह भी कि अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में/से समावेशन/निष्कासन के मुद्दे पर राज्य आयोगों की सिफारिश अंतिम होनी चाहिए। श्री कपिल हरीशचंद पाटिल, विधान परिषद सदस्य ने एनसीबीसी की तर्ज पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए सांविधानिक दर्जे की मांग की। श्री साहू अक्षय भाई, मुख्य समन्वयकर्ता, राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग परिषद की राय थी कि उस चयन समिति के संबंध में स्पष्टता होनी चाहिए जोकि एनसीबीसी के अध्यक्ष और सदस्यों को चुनेगी तथा आयोग की सदस्य संख्या न्यूनतम 7 होनी चाहिए।

12. जनकल्याण मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री पी०एस० कृष्णन की राय थी कि अनुच्छेद 342(1) के अंतर्गत प्रक्रिया के लिए जहां सूची को अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकारों के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा सूची जारी की जाने वाली है, राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह ली जानी चाहिए। श्री कृष्णन ने यह भी कहा कि दूसरे चरण अर्थात् अनुच्छेद 342(2) में आयोग की भूमिका होनी चाहिए। बाद में जब भी कोई आवर्धन या विलोपन हो तो इस चरण में भी आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए। उनकी यह भी राय थी कि एनसीबीसी का मौजूदा संघटन नए आयोग में परिलक्षित होना चाहिए जोकि विधेयक के पारण के पश्चात् गठित किया जाएगा जैसे कि उदाहरणार्थ इसमें किसी न्यायाधीश, किसी समाजशास्त्री और अति पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति हो। तत्पश्चात् उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए अर्थात् (i) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की मौजूदा केन्द्रीय सूची को अनुच्छेद 342ए(1) हेतु पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रपति के आदेश के रूप में माना जाएगा; (ii) अनुच्छेद 338(5)(ग) में शब्द "भागीदारी" को अंतःस्थापित किए जाने के जरूरत है ताकि आयोग न केवल भागीदारी करे बल्कि साथ ही योजना बनाने की प्रक्रिया के संबंध में सलाह भी दे; (iii) आयोग के नाम में 'सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े' शब्दों को शामिल किया जाना चाहिए; और (iv) एनसीबीसी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक संवर्ग को बनाए जाने की जरूरत है।

13. बैठक को समाप्त करते हुए अध्यक्ष ने शिष्टमंडल को अपने विचार समिति के साथ साझा करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और सकारात्मक कार्रवाई के क्षेत्र में श्री पी०एस० कृष्णन के कार्य की सराहना करते हुए उनका विशेष उल्लेख किया। तत्पश्चात् अध्यक्ष ने सदस्यों से अनुरोध किया कि समिति द्वारा इस पर खंडशः चर्चा शुरू करने से पहले विधेयक में उनके प्रस्तावित संशोधन, यदि कोई हों, प्रस्तुत करें।

14. बैठक की कार्यवाही का शब्दशः अभिलेख रखा गया।
15. तत्पश्चात् बैठक म०प० 1.52 बजे स्थगित हुई।

नई दिल्ली;  
5 जून, 2017

महेश तिवारी,  
निदेशक।

संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 संबंधी राज्य सभा की प्रवर समिति  
की बैठक का कार्यवृत्त

VI

छठी बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 3 जुलाई, 2017 को म०पू० 11.00 बजे, समिति कक्ष 'ख', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

1. श्री भूपेन्द्र यादव — अध्यक्ष

सदस्य

2. डॉ० विकास महात्मे
3. श्री राम नारायण डूडी
4. श्री बी०के० हरिप्रसाद
5. श्री मधुसूदन मिस्त्री
6. श्री हुसैन दलवाई
7. प्रो० रामगोपाल यादव
8. श्री शरद यादव
9. श्री सुखेन्दु शेखर राय
10. श्री ए० नवनीतकृष्णन
11. श्री टी०के० रंगराजन
12. श्री दिलीप कुमार तिकी
13. श्रीमती कानीमोझी
14. श्री अनिल देसाई
15. श्री नरेश गुजराल
16. श्री विश्वजीत दैमारी
17. श्री राजीव चन्द्रशेखर
18. श्री स्वपन दासगुप्ता

सचिवालय

1. श्री जे०जी० नेगी, संयुक्त सचिव
2. श्री महेश तिवारी, निदेशक
3. श्री राकेश आनन्द, अपर निदेशक
4. श्रीमती नोनिका बा, अपर निदेशक

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री बी०एल० मीना, संयुक्त सचिव
2. श्री के० नारायणन, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

## विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री सुरेश चन्द्र, सचिव
2. श्री रामायण यादव, अपर सचिव

## विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. डॉ० जी० नारायण राजू, सचिव
2. डॉ० रीता वशिष्ठ, अपर सचिव
3. श्री आर० श्रीनिवास, अपर विधायी काउंसल

2. आरंभ में अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची के बारे में संक्षेप में बताया। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि जनता से ज्ञापन/सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन के परिणामस्वरूप 72 ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 के उपबंधों के संबंध में राज्य सरकारों के उत्तर के बारे में भी उन्हें संक्षेप में बताया। तत्पश्चात् उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि समिति बैठक में संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 पर खंड-वार विचार करेगी तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग तथा विधि कार्य विभाग के सचिव आवश्यक स्पष्टीकरण देंगे।

3. समिति ने विधेयक को अनुच्छेद 338 के अंतर्गत विचार हेतु लाए जाने पर आशंका व्यक्त की और इसे अनुच्छेद 340 के अंतर्गत नहीं लाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। यह आशंका व्यक्त की गई कि इस अधिनियमन के पश्चात् अनुच्छेद 340 अनावश्यक बन सकता है। उत्तर में सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय ने सूचित किया कि अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति द्वारा तदर्थ समिति के गठन के लिए है। इसके अतिरिक्त, मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने सरकार को एक स्थायी निकाय के गठन का निदेश दिया है और इसके अनुसरण में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। वर्तमान विधेयक इस आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का एक प्रयास भर है। अनुच्छेद 340 किसी भी तरह से अनावश्यक नहीं बनेगा और सरकार के पास फिर भी इसके अधीन तदर्थ समितियों का गठन करने की शक्तियां होंगी। तत्पश्चात् समिति ने खंड-वार विचार शुरू किया।

4. विधेयक के खंड 2 को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया गया।

5. तत्पश्चात् समिति ने खंड 3 को विचार के लिए लिया। समिति ने यथा उपबंधित प्रस्तावित आयोग का पुनर्नामकरण अनुच्छेद 338ख के उप-खंड(1) के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में करने संबंधी संशोधन को लिया। उत्तर में मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया कि प्रस्तावित आयोग के नामकरण का निर्णय अंतर-मंत्रालयी परामर्श के पश्चात् लिया गया था जहां यह महसूस किया गया कि इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग कहा जाना अपने आप में स्पष्ट है।

6. कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की अर्हताएं संशोधन में उपबंधित की जानी चाहिए। कुछ सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय/उच्च-न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उपाध्यक्ष ओबीसी/अल्पसंख्यक समुदाय से हो सकते हैं। साथ ही एक महिला सदस्य भी इसमें हो तथा सदस्य-सचिव भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी हो सकते हैं। अन्य सुझाव पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों में विशेष जानकारी रखने वाले समाज विज्ञानी और विशेषज्ञ तथा कम से कम एक सदस्य सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग या अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत समुदाय से शामिल करने के संबंध में थे।

7. तत्पश्चात् समिति ने प्रस्तावित अनुच्छेद 338ख के उप-खंड (5) को विचार के लिए लिया। सदस्य चाहते थे कि अनुच्छेद 338ख(5) के उप-खंड(ग) को संशोधित किया जाए और इस प्रकार पढ़ा जाए: 'सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास की आयोजना प्रक्रिया में भाग लेना तथा इसके संबंध में सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य में उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।' उत्तर में मंत्रालय ने कहा कि अनुच्छेद 338ख के खंड (5) के अधीन सभी उप-खंड प्रस्तावित आयोग के लिए सहभागी भूमिका की ओर संकेत करते हैं। समिति ने मंत्रालय के रुख को नोट किया।

8. तत्पश्चात् समिति ने कुछ अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित संशोधनों को लिया—

पृष्ठ 2, पर पंक्ति 11 के पश्चात्, दो नए उप-खंड (क) और (ख) जोड़े जाएं और मौजूदा उप-खंड (क) से (च) को नए सिरे से (ग) से (ज) के रूप में अंकित किया जाए। नए उपखंड (क) एवं (ख) को निम्नानुसार पढ़ा जाए:—

‘(क) (i) अनुच्छेद 342क(1) के अधीन लोक अधिसूचना के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की प्रारूप सूची की जांच करना तथा केंद्रीय सरकार को ऐसी सलाह देना जिसे यह उपयुक्त समझे।

(ii) आयोग द्वारा दी गई सलाह सामान्यतया केंद्रीय सरकार के लिए बाध्यकारी होगी:

परंतु यह कि यदि केंद्रीय सरकार आयोग की सलाह से सहमत नहीं होती है तो यह इसके कारण लिखित में अभिलिखित करेगी और इन कारणों को प्रारूप सूची के साथ राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगी।

(ख) (i) अनुच्छेद 342क(2) के अधीन सूची को संशोधित करने के लिए संसद को समर्थ बनाने के प्रयोजन से सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित करने या अपवर्जित करने के लिए अनुरोध की जांच करना तथा केंद्रीय सरकार को सलाह देना तथा ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन और न्यून समावेशन की शिकायत को सुनना तथा केंद्रीय सरकार को ऐसी सलाह देना जो यह उपयुक्त समझे।

(ii) आयोग द्वारा दी गई सलाह सामान्यतया केंद्रीय सरकार के लिए बाध्यकारी होगी:

परंतु यह कि यदि केंद्रीय सरकार आयोग की सलाह से सहमत नहीं होती है तो यह इसके कारण लिखित में अभिलिखित करेगी और इसे संसद की दोनों सभाओं में रखेगी।’

9. समिति ने अनुच्छेद 338ख के खंड (5) में एक नए उप-खंड (छ) के अंतःस्थापन से संबंधित प्रस्तावित संशोधन पर भी विचार किया जिसमें कहा गया है ‘नागरिकों के किसी वर्ग को सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित करने के अनुरोध की जांच करना तथा इस सूची में किसी पिछड़े वर्ग के अपेक्षित से ज्यादा अंतर्वेशन या अल्प-अंतर्वेशन की शिकायत को सुनना तथा केंद्रीय सरकार को ऐसी सलाह देना जो यह उपयुक्त समझे।’ समिति को यह स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावित आयोग द्वारा शिकायतों की सुनवाई का उपबंध अनुच्छेद 338ख(5) के अंतर्गत किया गया है और किसी पिछड़े वर्ग के रूप में किसी वर्ग के अंतर्वेशन हेतु अनुरोध की जांच के संबंध में यह अधिकार विधेयक के अधिनियमन के उपरांत जारी किए जाने वाले तौर-तरीकों के हिस्से के रूप में आयोग के पास उपलब्ध होगा।

10. तत्पश्चात् समिति के प्रस्तावित अनुच्छेद 338ख के खंड 5(घ) के संशोधन पर विचार किया जिसमें ‘और ऐसे अन्य समय पर जैसाकि आयोग को उपयुक्त लगे’ शब्दों को हटाया जाए। समिति ने संसद के समक्ष विभिन्न आयोगों/समितियों के वार्षिक प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए अत्यधिक विलंब के बारे में चर्चा की, जिसके कारण उन पर सभा में चर्चा नहीं हो पाती है। उत्तर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि आयोगों के वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाते हैं। मंत्रालय राज्यों तथा विभिन्न मंत्रालयों से की गई कार्रवाई प्रतिवेदन प्राप्त करता है और संसद के पटल पर रखता है। इसके अलावा, आयोग दो-तीन विशेष प्रतिवेदन, जैसे किसी राज्य विशेष में किसी घटना के संबंध में, भी प्रस्तुत करता है। ये वार्षिक



प्रतिवेदन से भिन्न प्रतिवेदन होते हैं। समिति ने मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को नोट किया और आशा व्यक्त की कि प्रस्तावित आयोग अपने वार्षिक प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदन संसद के विचारार्थ सही समय पर रखेगा।

11. समिति ने अनुच्छेद 338ख के उप-खंड (8) में कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया:—

पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 41 और 42 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: *‘(8) आयोग उप-खंड (क) एवं (ख) में यथासंदर्भित अनुरोधों और शिकायतों की जांच करते हुए या उप-खंड (ग) में यथासंदर्भित किसी मामले की जांच या खंड 5 के उप-खंड (घ) में यथासंदर्भित किसी शिकायत की जांच करते हुए ..... करेगा’*

12. उत्तर में यह स्पष्ट किया गया कि उप-खंड (क) में संदर्भित किसी मामले की जांच करते हुए या खंड (5) के उप-खंड (ख) में संदर्भित किसी शिकायत की जांच करते हुए आयोग के पास किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी।

13. समिति ने संशोधन पर चर्चा की जिसमें अनुच्छेद 338ख में एक नए उप-खंड (10) को अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था। इस उपखंड (10) में निम्नलिखित कहा जाएगा:

*‘खंड 9 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के पास सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्तियां बनी रहेंगी।’*

14. मंत्रालय द्वारा समिति को स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावित संशोधन सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्य सरकारों की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करता है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की मौजूदा शक्तियां संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 के पारित होने के पश्चात् भी जारी रहेंगी।

15. समिति ने प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में चर्चा की और मंत्रालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों के मद्देनजर समिति ने बिना किसी संशोधन के खंड 3 को स्वीकृत किया।

16. इसके बाद समिति ने विधेयक के खंड 4 पर विचार किया। समिति ने कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया:—

(i) अनुच्छेद 342क के उप-खंड (1) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए:

*“राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां यह कोई राज्य है, वहां उसके राज्यपाल के अनुरोध पर लोक अधिसूचना द्वारा भारत सरकार के अंतर्गत या भारत सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत या भारत सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति में या केंद्रीय सरकार की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण हेतु प्रावधान करने के प्रयोजनों के लिए सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट करेगा,”*

(ii) अनुच्छेद 342क के उपखंड (2) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए:

*“राष्ट्रपति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के परामर्श पर खंड (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में समावेशन या अपवर्जन कर सकता है,”*

(iii) अनुच्छेद 342क में खंड (3) को निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाए:

*“किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य के अंतर्गत या राज्य के किसी अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत या राज्य के नियंत्रण के अंतर्गत पदों, या उस राज्य के अंदर शैक्षिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण हेतु प्रावधान करने के प्रयोजन से लोक अधिसूचना द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट करेगा;” और*

(iv) अनुच्छेद 342क में खंड (4) को निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाए:

“राज्यपाल, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के परामर्श पर खंड (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की राज्य सूची में समावेशन या अपवर्जन कर सकता है।”

17. खण्ड 4 के संबंध में कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के अन्य सेट निम्नानुसार थे:

(i) अनुच्छेद 342क के उप-खण्ड (1) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए: “राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां यह कोई राज्य है, वहां केवल उस राज्य सरकार की पूर्व सिफारिश से और ऐसी सिफारिश को यथोचित सम्मान देते हुए लोक अधिसूचना द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट करेगा, जो यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची के रूप में समझे जाएंगे।”

(ii) अनुच्छेद 342क के उप-खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

(3) “प्रत्येक राज्य सरकार लोक अधिसूचना द्वारा उस राज्य में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट करेगी, जो उस राज्य के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की राज्य सूची के रूप में समझे जाएंगे।

(4) राज्य विधि द्वारा खंड (3) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की राज्य सूची में किसी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को सम्मिलित या अपवर्जित कर सकेगा, किन्तु पूर्वोक्त के सिवाय उक्त खंड के अधीन जारी किसी अधिसूचना में किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।”

18. खंड 4 के संबंध में कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के अन्य सेट निम्नानुसार थे:

अनुच्छेद 342क(1):—पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 19 के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

‘परंतु यह कि ऐसी सार्वजनिक अधिसूचना अनुच्छेद 338ख(5) के अंतर्गत आयोग द्वारा दिए गए परामर्श के आधार पर जारी की जाएगी और जारी होने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों में रखी जाएगी:

परंतु यह भी कि राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श उस राज्य के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा राज्यपाल को दिए गए परामर्श के आधार पर किया जाएगा।’

अनुच्छेद 342क(2):—पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 23 के बाद निम्नलिखित पंक्तियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

‘परंतु यह कि ऐसा कानून अनुच्छेद 338ख(5)(ख) के अंतर्गत आयोग द्वारा दिए गए परामर्श पर आधारित हो।’

अनुच्छेद 342क(3):—पृष्ठ 3 पर, अनुच्छेद 342क(2) के पश्चात् एक नया खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:

‘342क(3)—केंद्रीय सरकार पिछड़े वर्गों के रूप में मान्यता समाप्त कर दिए गए ऐसे वर्गों को अपवर्जित करने के उद्देश्य से या ऐसी सूची में नए पिछड़े वर्गों को सम्मिलित करने हेतु आयोग की सलाह पर किसी भी समय उस सूची की समीक्षा कर सकती है और अनुच्छेद 342क(1) के अंतर्गत अधिसूचित सूची के लागू होने की तिथि से दस वर्षों के समाप्त होने पर, और इसके पश्चात् दस वर्षों की प्रत्येक अनुवर्ती अवधि की समाप्ति पर उस सूची की समीक्षा करेगी।’

(4) राज्य विधि द्वारा खंड (3) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में या उससे किसी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को सम्मिलित या अपवर्जित कर सकेगी, किंतु पूर्वोक्त के सिवाय उक्त खंड के अधीन जारी किसी अधिसूचना में किसी पश्चात्पूर्वी अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।'

18. खंड 4 के संबंध में कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का एक अन्य सेट निम्नानुसार था:

अनुच्छेद 342(1):—पृष्ठ 3, पंक्ति 19 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:

'परंतु यह कि ऐसी सार्वजनिक अधिसूचना अनुच्छेद 338ख(5) के अधीन आयोग द्वारा दी गई सलाह के आधार पर जारी की जाएगी और इसके जारी होने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद की दोनों सभाओं में रखी जाएगी:

परंतु यह भी कि राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श उस राज्य के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह के आधार पर होगा।'

अनुच्छेद 342(2):—पृष्ठ 3, पंक्ति 23 के पश्चात्, निम्नलिखित पंक्तियां अंतःस्थापित की जाएंगी; अर्थात्:

'परंतु यह कि ऐसी विधि अनुच्छेद 338ख(5)(ख) के अंतर्गत आयोग द्वारा दी गई सलाह पर आधारित हो।'

अनुच्छेद 342(3):—पृष्ठ 3, अनुच्छेद 342(2) के पश्चात्, एक नया खंड जोड़ा जाए, अर्थात्:

'342क (3):—केंद्रीय सरकार पिछड़े वर्गों के रूप में मान्यता समाप्त कर दिए गए ऐसे वर्गों को अपवर्जित करने के उद्देश्य से या ऐसी सूची में नए पिछड़े वर्गों को सम्मिलित करने हेतु आयोग की सलाह पर किसी भी समय उस सूची की समीक्षा कर सकती है और अनुच्छेद 342(1) के अंतर्गत अधिसूचित सूची के लागू होने की तिथि से दस वर्षों के समाप्त होने पर, और इसके पश्चात् दस वर्षों की प्रत्येक अनुवर्ती अवधि की समाप्ति पर उस सूची की समीक्षा करेगी।'

19. मंत्रालय ने उठाए गए मुद्दों के संबंध में स्पष्ट किया कि प्रस्तावित आयोग द्वारा सूचियों का समयबद्ध दशकीय संशोधन एक सतत् प्रक्रिया है। तथापि, आयोग को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को अधिकार तथा रक्षोपायों से वंचित किए जाने संबंधी विशिष्ट शिकायतों की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया कि उस राज्य के अधीन अथवा राज्य के किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन अथवा राज्य के नियंत्रण के अधीन पदों अथवा उस राज्य के भीतर शैक्षिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण का पहलु वर्तमान विधेयक के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसलिए प्रस्तावित संशोधनों की अनुमति नहीं दी गई है।

20. मंत्रालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 154 के खंड (1) और अनुच्छेद 163 में स्पष्टतः कहा गया है कि राज्यपाल मंत्रीपरिषद् की सलाह पर कार्यवाई करेगा। उक्त संवैधानिक उपबंधों के अधीन, राज्यपाल अपने प्राधिकार का या तो प्रत्यक्षतः या संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों के माध्यम से अप्रत्यक्षतः प्रयोग करेगा। संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों के संबंध में राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श का उपबंध किया गया है और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में राज्य के राज्यपाल के साथ राष्ट्रपति के परामर्श का उपबंध किया गया है। जैसा कि परिपाटी रही है, राज्य सरकार को कभी भी परामर्श प्रक्रिया से बाहर नहीं रखा गया है। हमेशा अनिवार्यतः राज्य सरकार ही होती है जो राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सम्मिलित/अपवर्जित किए जाने वाले वर्गों की सिफारिश करती है। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को केंद्रीय सूची में शामिल करने हेतु पिछड़े वर्गों को संवैधानिक दर्जा देने के मामले में भी ऐसे ही प्रावधान का उपबंध किया गया है। इस प्रकार राज्यपाल से परामर्श का मतलब है राज्य सरकार से परामर्श।

21. आगे यह भी सूचित किया गया कि अनुच्छेद 342क के उप-खंड (1) में यथा उपबंधित पद “इस संविधान के प्रयोजनार्थ” विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दी गई सलाह के अनुसार एक विधायी आवश्यकता है। प्रस्तावित आयोग की स्थापना से सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के हित को कोई नुकसान नहीं होगा। अनुच्छेद 342क के केंद्रीय सूची में समावेशन/अपवर्जन के प्रत्येक मामले की विस्तृत जांच का उपबंध किया जाएगा। ऐसे समावेशन/अपवर्जन की चरम शक्ति संसद में निहित होगी।

22. समिति ने प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में चर्चा की और मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के मद्देनजर विधेयक के खंड 4 को बिना किन्हीं संशोधनों के स्वीकृत किया गया।

23. विधेयक का खंड 5 बिना किन्हीं संशोधनों के स्वीकृत किया गया।

24. खंड 1: अधिनियमन सूत्र और विधेयक का संक्षिप्त नाम समिति द्वारा बिना किन्हीं संशोधनों के स्वीकृत किए गए।

25. बैठक का समापन करते हुए अध्यक्ष ने उपस्थित सदस्यों और अधिकारियों को अपने विचार साझा करने के लिए धन्यवाद दिया और सूचित किया कि प्रवर समिति के प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकार करने के लिए समिति की अगली बैठक 14 जुलाई, 2017 को होगी।

26. बैठक की कार्यवाही का शब्दशः अभिलेख रखा गया।

27. तत्पश्चात् बैठक म०प० 12.43 बजे स्थगित हुई।

नई दिल्ली;  
3 जुलाई, 2017

महेश तिवारी  
निदेशक।

संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 संबंधी राज्य सभा की प्रवर समिति  
की बैठक का कार्यवृत्त

VII

सातवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 14 जुलाई, 2017 को म०पू० 11.00 बजे, समिति कक्ष 'क', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

1. श्री भूपेन्द्र यादव—अध्यक्ष

सदस्य

2. डॉ० विकास महात्मे
3. श्री राम नारायण डूडी
4. श्री बी०के० हरिप्रसाद
5. श्री दिग्विजय सिंह
6. श्री हुसैन दलवाई
7. प्रो० रामगोपाल यादव
8. श्री शरद यादव
9. श्री ए० नवनीतकृष्णन
10. श्री टी०के० रंगराजन
11. श्री प्रफुल्ल पटेल
12. श्रीमती कानीमोझी
13. श्री अनिल देसाई
14. श्री नरेश गुजराल
15. श्री स्वपन दासगुप्ता
16. श्री राम कुमार कश्यप

सचिवालय

1. श्री जे०जी० नेगी, संयुक्त सचिव
2. श्री महेश तिवारी, निदेशक
3. श्री आर०एस० रावत, अपर निदेशक
4. श्री राकेश आनन्द, अपर निदेशक

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्रीमती जी० लता कृष्ण राव, सचिव
2. श्री बी०एल० मीना, संयुक्त सचिव
3. श्री के० नारायणन, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

### विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री सुरेश चन्द्र, सचिव
2. श्री रामायण यादव, अपर सचिव

### विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. डॉ० जी० नारायण राजू, सचिव
2. डॉ० रीता वशिष्ठ, अपर सचिव
3. श्री आर० श्रीनिवास, अपर विधायी काउंसल

2. प्रारंभ में अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव, विधि कार्य विभाग के सचिव एवं विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के सचिव तथा उनके दल का राज्य सभा की प्रवर समिति की बैठक में स्वागत किया। अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि बैठक का आयोजन संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 के प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकार करने के लिए किया गया है। प्रवर समिति की यह सातवीं बैठक है। अध्यक्ष ने यह भी सूचित किया कि प्रारूप प्रतिवेदन जिसे चर्चा के लिए लिया जाएगा, यदि विचार-विमर्श के प्रक्रिया के दौरान सदस्यों द्वारा कोई बिंदु उठाया जाएगा तो उसका स्पष्टीकरण बैठक में उपस्थित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों द्वारा दिया जाएगा।

3. चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के संबंध में आशंका व्यक्त की कि इसे अनुच्छेद 338 के अधीन होना चाहिए या अनुच्छेद 340 के अधीन होना चाहिए। यह आशंका व्यक्त की गई कि इस अधिनियमन के पश्चात् अनुच्छेद 340 निरर्थक बन सकता है। संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 के अधिनियमन के पश्चात् अन्य पिछड़े वर्गों की राज्य सूची में समुदायों को शामिल करने या निकालने की राज्य सरकार की शक्तियों के संबंध में आशंकाएं व्यक्त की गईं। कुछ सदस्यों ने यह चिंता व्यक्त की कि हो सकता है कि आयोग की सिफारिशों को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाए, इसलिए इसके लिए विधेयक में ही उपबंध किया जाना चाहिए। कुछ सदस्यों द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि जनजातीय सलाहकार परिषद् की तरह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के मुद्दों की जांच करने के लिए एक परिषद् का गठन किया जा सकता है। कुछ सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि आयोग में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए और इसमें महिलाओं तथा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाए।

4. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव ने स्पष्टीकरण दिया कि जब कोई अधिनियम पारित हो जाता है तो यह केवल व्यापक नीति विवरण निर्धारित करेगा। किसी अधिनियमन या संवैधानिक संशोधन को लागू करने के लिए तौर तरीके नियमों की प्रक्रिया के माध्यम से निकलते हैं। इसलिए सदस्यता, अध्यक्ष की हैसियत जैसे मुद्दे नियमों में शामिल होंगे। उन्होंने यह भी सूचित किया कि अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक स्थायी आयोग की स्थापना की जा सकती है जबकि अनुच्छेद 340 के अंतर्गत प्रस्तावित आयोग को स्थायी दर्जा नहीं दिया जा सकता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किया गया था तो सहजतः ही इसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को स्थायित्व देने के लिए अनुच्छेद 338 को शामिल करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने यह भी स्पष्टीकरण दिया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना किसी भी प्रकार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की मौजूदा शक्ति को वापस लेना नहीं होगा। एकमात्र अंतर केंद्रीय सूची के संबंध में होगा जहां संवैधानिक संशोधन के पश्चात् निष्कासित करने या समाविष्ट किए जाने की शक्ति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के पश्चात् संसद के पास आ जाएगी।

5. तत्पश्चात्, प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया गया। अध्यक्ष ने कहा कि वे सदस्य जो विसम्मति टिप्पण देना चाहते हैं इसे 15 जुलाई, 2017 को म०प० 6.00 बजे तक सचिवालय में जमा करा सकते हैं।

6. बैठक को समाप्त करते हुए अध्यक्ष ने समिति की बैठक को सूचनापरक एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने में सदस्यों द्वारा किए गए प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। अध्यक्ष ने समिति की ओर से वृत्तलेखकों तथा भाषान्तरकारों सहित राज्य सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा किए गए कठोर श्रम और अध्यवसाय की सराहना

की। उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विधि कार्य एवं विधायी विभाग के अधिकारियों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने समिति के विचार-विमर्श में योगदान दिया।

7. बैठक की कार्यवाही का शब्दशः अभिलेख रखा गया।

8. समिति की बैठक म०प० 12.45 बजे स्थगित हुई।

नई दिल्ली;  
14 जुलाई, 2017

महेश तिवारी  
निदेशक।